खण्ड-203, अंक-3
शनिवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(14 मार्च, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 203 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १४ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३३७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्रकाछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपालो, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
ठीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमनाप्रसाद शक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुतन्लादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सूरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह चिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १४ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जरी व बादला को बिक्री-कर से मुक्त करने की प्रार्थना

**१--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या वित्त-मन्त्री लखनऊ के गृह उद्योग जरी व बादला के माल को बिक्री-कर से मुक्त करने पर विचार करेंगे ?

वित्त-मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--लखनऊ के जरी और बादला उद्योग को बिक्री-कर के सम्बन्ध में कुछ सुविधा देने के सवाल पर सरकार विचार कर रही है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह विचार कब से कर रहे हैं और कब इस पर विचार हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरा खयाल है ५-६ दिन हुए इनका डेपुटेशन आया था । उन्होंने कुछ अपनी बातें पेश की हैं, उसके ऊपर हम गौर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी फैसला हो जायगा ।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय वित्त मन्त्री महोदय उस डेपुटेशन ने जो प्रमुख बातें उनके सम्मुख पेश की हैं उनको सदन की जानकारी के लिए बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं मालूम होती। मैंने यह तो अर्ज कर दिया कि उनकी जो खास-खास बातें हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं । अब उसकी तफसील में कहां तक बताऊं ?

श्री भगवतीसिंह बिशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न में जो सुविधायें प्रदान करने की बात वह सोच रहे हैं, उनमें क्या प्रमुख सुविधायें वह प्रदान करने जा रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--सुविधा का क्या सवाल है ? वह चाहते हैं कि सेल्स टैक्स हटा दिया जाय। तो हटा दिया जाय या कम कर दिया जाय। यही सुविधा हो सकती है । मल्टीपुल प्वाइंट का एक प्वाइंट कर दिया जाय, वगैरह-वगैरह इस किस्म की सुविधायें होती हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सहूलियत सिर्फ लखनऊ वालों के लिए सोची जायगी या बनारस वगैरह में भी जहां यह काम होता है, वहां के लिए भी यह सुविधायें होंगी ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे खयाल से बनारस का जो काम है उसके ऊपर तो पहले ही से माफ है । लेकिन जाहिर है कि किसी जगह के नाम से थोड़े ही सुविधा देंगे । अगर देंगे तो एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री को वह सुविधा देंगे वह चाहे जहां हो।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री प्रतापसिंह ने पूछा ।

नवीन एजूकेशन कोड का प्रकाशन

२—श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ जुलाई सन् १९५७ को एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में जो यह कहा गया था कि एजूकेशन कोड का नया संस्करण जल्दी ही छपने जा रहा है वह अभी तक क्यों नहीं छपा है ?

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—छप चुका है ।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह किस महीने में छप कर तैयार हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जनवरी में ।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संस्थाओं के लिए इसकी सूचना दे दी गयी है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना देने की आवश्यकता है यह तो मैं नहीं समझता। यदि इसकी आवश्यकता समझी जाय कि शिक्षा संस्थाओं को इसकी सूचना दे दी जाय कि एजूकेशन कोड का नया संस्करण छप गया है, तो इसकी सूचना भी दी जा सकती है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसका हिन्दी संस्करण भी छपा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हिन्दी संस्करण के छपने का प्रयास हो रहा है। वह भी जल्दी ही छप जायगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्राप्य है और प्राप्त है तो कहां है और क्या इसका मूल्य भी रखा गया है और मूल्य है तो क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मूल्य की सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट प्रेस में छपा है और गवर्नमेंट प्रेस से प्राप्त होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्करण में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन भी किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां । यह जो संस्करण इसके पहले था वह बड़ा पुराना था । इसके बाद जितने संशोधन और परिवर्तन हुए हैं वह सब उसमें कर दिये गये हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी इसकी एक-एक प्रति माननीय सदस्यों को बटवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा कोई विचार तो नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसका हिन्दी संस्करण कब तक प्राप्त हो जायगा बाजारों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अंग्रेजी संस्करण के छापने में करीब दो साल लग गये । उसका हिन्दी अनुवाद हो रहा है और प्रयत्न किया जायगा कि जल्दी से जल्दी छप जाय ।

श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसके संशोधन के लिए शिक्षा संस्थाओं से कोई सुझाव मांगे गये थे या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुत से संशोधन तो सरकारी आदेशों द्वारा होते रहे हैं । जो जी० ओ० इकट्ठा थे सब सम्मिलित कर दिये गये हैं । खास तौर से सुझाव मांगे गये हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं हैं, लेकिन जो सुझाव रहे होंगे उन सब पर विचार कर लिया गया होगा ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इसका संशोधन करने में प्रमुख हाथ किन का रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विभाग ने किया है संशोधन । १९४८ या १९४९ में वह छपा था । उसके बाद बहुत से आदेश हुए हैं उन सब आदेशों को जोड़ कर के एक परिवर्तित और परिवर्द्धित संस्करण छापा गया है ।

श्री राजनारायण के विरुद्ध श्री नेकराम शर्मा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के ऊपर आज अपना निर्णय देने को कहा था । श्री नेकराम जी आज मौजूद नहीं हैं क्योंकि उनको एक मुकदमे में आवश्यकता के कारण बाहर जाना पड़ा । इसलिये मैं सोमवार को उनकी उपस्थिति में ही जो मुझे फैसला देना है वह दूंगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, तो उसी के सम्बन्ध में हमारा नियम ५२ वाला बिषय भी रह जायगा ।

श्री अध्यक्ष---वह सब एक साथ ही होगा ।

श्रमजीवी पत्रकारों की प्रान्त व्यापी हड़ताल पर विवादार्थ दो कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने दिया है ।

"आज १४ मार्च को प्रान्त के श्रमजीवी पत्रकारों की प्रान्तव्यापी प्रतीक हड़ताल, जो प्रयाग में अमृत बाजार पत्रिका व अमृत पत्रिका के अवैधानिक रूप से बन्द हो जाने के कारण प्रारम्भ हुई है, उसके परिणामस्वरूप प्रान्त में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है ।

सरकार ने न तो अवैधानिक कार्य करने वाले मिलमालिकों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है और न श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिये भी कोई कदम उठाया है । यह विषम परिस्थिति सरकार की अकर्मण्यता तथा उसकी असफलता के परिणामस्वरूप खड़ी हुई है ।

अतएव इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिए आज का सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

इस विषय में श्री राजनारायण जी का भी एक कामरोको प्रस्ताव इसी तरह का है और उस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दो दिन पूर्व यहां जिक्र किया था कि इसके ऊपर समझौते के लिए वह बात कर सकते हैं और कोई तरीका जब्र का नहीं हो सकता । यह बात उन्होंने कही थी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मैं एक निवेदन कर देना चाहता . . . .

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, मैं इसके ऊपर काफी स्पष्ट हूं, कोई आवश्यकता नहीं है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन अपने भाषण में कहा था . . . .

श्री अध्यक्ष---तो वह आप बाद में कहें ।

तो मैं कामरोको प्रस्ताव की हैसियत से इसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर सकता कि कुछ थोड़ा सा जो कुछ उन्हें इस विषय में जिक्र करना था वह उन्होंने कर दिया था कि वह एक पंच की हैसियत से आपसी समझौते की बात कर सकते हैं; और अन्य किसी तरह से उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

दूसरी बात यह है कि परसों श्रम के ऊपर बहस होने वाली है । उसमें, बहस में यह प्रश्न सदस्यगण ला सकते हैं । इसलिए कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं बन सकता । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अध्यक्ष महोदय, कम से कम मुख्य मन्त्री जी की जो उनसे बातचीत हुई है उसके बारे में एक स्टेटमेंट ही वह दे दें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मुझे भी यही निवेदन करना था कि मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि उनके समझौते के प्रयत्नों का फल क्या हुआ और जो उन्होंने यह कहा था कि अगर समझौता नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेफर करेगी ट्रिब्युनल को उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, जरा मेरा निवेदन भी सुन लें । यह आपने मेरा कामरोको प्रस्ताव भी शायद पढ़ ही लिया होगा । मैंने जो जोर दिया था वह यह दिया था कि मुख्य मंत्री जी ने जरूर कृपा की होगी उन लोगों से बातचीत करके किसी नतीजे पर आने की, लेकिन वह असफल हो गये । उसका प्रमाण हम यह देखते हैं कि हमारी प्रेस गैलरी आज यहां पर बिलकुल खाली है । इससे मालूम होता है कि कम्पलीट हड़ताल हुई । तो जैसा कि हम परसों श्रम पर विवाद करने वाले हैं वह तो समय दूर है । आप विचार करके देखें ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बहस न करें । आप मुख्य मंत्री जी से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हों तो करें ।

श्री राजनारायण---हम जानना चाहते हैं कि यह हड़ताल न हो सरकार ने इस बात के लिये क्या कोशिश की ? अखबार के मालिकों के सामने क्या-क्या दिक्कतें और बाधा आईं क्योंकि हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा कि . . . .

श्री अध्यक्ष---आप अपनी सूचना देते हुये बहस न करें । आपको जो बात पूछनी हो वह पूछें ।

श्री राजनारायण---सरकार ने अभी तक क्या प्रयत्न किया ? अखबार के मालिकों ने जो हर समय हथकंडे अखतियार किये उनको रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या कोशिश की गई ?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, यह बात तो अखबारों में आ चुकी है कि जो कुछ समझौते की बात चल रही थी वह खत्म हो गई । वह किस तरह से खत्म हो गई शायद इसको समझने के लिये कुछ थोड़ा-सा इस विवाद के इतिहास में जाना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि आपकी इजाजत से थोड़ा-सा उसको कह दूं ।

प्रेस के अखबारों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के केन्द्र में जो कानून बने उनका परिणाम यह हुआ कि अखबारों को कई वर्गों में बांटा गया । ए, बी, सी, डी, इ इत्यादि । जो ए श्रेणी का है उसका बोझ बी वर्ग वाले से कम है, जो बी वर्ग वाला है उसका बोझ डी वर्ग वाले से कम है आदि-आदि । जो जितना नीचे वर्ग का है उसको उतने ही ज्यादा अपने प्रेस कर्मचारियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को तनख्वाह देने में कुछ कठिनाई होगी । यह मामला वेज बोर्ड के सामने है, लेकिन इतना निश्चित है कि ऊंचे वर्ग को ज्यादा तनख्वाह देना पड़ेगी बनिस्बत नीचे वर्ग के । इलाहाबाद से एक अंग्रेजी का अखबार "अमृत बाजार पत्रिका" निकलता था, लेकिन एक उसी जगह से हिन्दी का अखबार भी निकलता था जिसका नाम "अमृत पत्रिका" था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कम्पनी थी जो इन अखबारों को निकालती थी। उसी कम्पनी की तरफ से कलकत्ता से भी एक अखबार निकलता था "अमृत बाजार पत्रिका"। यह तीनों अखबार एक ही कम्पनी के थे। जो नया वर्गीकरण हुआ उसके हिसाब से जो कलकते वाला "अमृत बाजार पत्रिका" अखबार था वह ए वर्ग में हुआ। जो इलाहाबाद का अंग्रेजी का "अमृत बाजार पत्रिका" अखबार था वह भी ए वर्ग में आया, लेकिन हिन्दी का "अमृत पत्रिका" अखबार जो निकलता था वह बी वर्ग का हुआ। जो अखबार निकालने वाले मालिक थे उनका यह खयाल हुआ और है कि इस वर्गीकरण की वजह से उनके ऊपर इतना बोझ पड़ेगा कि वह उठा नहीं सकते। इस लिये उनका यह कहना है कि जो कलकता वाला अखबार है उसकी सालाना आमदनी करीब ६० लाख के होती है, जो इलाहाबाद का अंग्रेजी का "अमृत बाजार पत्रिका" है उसकी आमदनी करीब १० लाख के होती है। जो हिन्दी का अखबार था उसकी अमदनी सालाना करीब ४ लाख के है इस समय उनका कहना है कि यह अखबार अब भी अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं करता है तो आगे ये अखबार अपना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह सारा खर्च करने का बोझ कलकत्ते वाले अखबार पर जाकर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसी प्रदेश में जो नेशनल हेरल्ड आदि दूसरे अच्छे अंग्रेजी के पेपर निकलते हैं यह अखबार जाकर बी वर्ग में पड़ते हैं और हमारा हिन्दी का अखबार जो इनके मुकाबले में कहीं कम छपता है और उसकी बिक्री भी कम है वह जाकर बी वर्ग में पड़ेगा। उन्होंने सही या गलत, इन दोनों अखबारों को बन्द कर दिया, प्रकाशन बन्द कर दिया। उसके बाद एक नयी कम्पनी कायम हुई। उसमें भी ऐसे लोग थे या हैं कि जिनका पुरानी कम्पनी से सम्बन्ध था। इस नयी कम्पनी ने इलाहाबाद से नार्दर्न इंडिया अमृत बाजार पत्रिका के नाम का एक अखबार निकाला। हिन्दी का अखबार बन्द था। इसके ऊपर हडताल हुई। कुछ लोगों ने नयी कम्पनी में काम करना मंजूर किया, कुछ ने नहीं। हड़ताल हुई और इसके पहले कि सरकार से कुछ बात करने की जरूरत पैदा हो जो इम्प्लाइज थे अखबार के और कुछ वे जो प्रेसों में काम करने वाले थे, उनके प्रतिनिधि मुझ से मिले । उनको मैंने नहीं बुलाया था, न सरकार ने बुलाया था, लेकिन वह मुझसे मिले और कहने लगे कि कोई कानूनी कार्यवाही न हो तो अच्छा है। उसमें बड़ी लम्बी मियाद लगती है। आप इस मामले में बीच में पड़ जायं और अगर आप चाहें तो शायद समझौता हो जाय । आप मालिकों को बुलवा लीजिये। मैंने कहा कि मुझे आशा कम है क्योंकि रुपये पैसे का मामला है। लेकिन उन्होंने दबाव डाला कि आप बीच में पड़ जायं । मैंने उनको बुलवाया और श्री तुषारकांति घोष, जो जाब्ते से डायरेक्टर हैं और एक प्रकार से सर्वेसर्वा हैं, मुझसे मिले । मुझसे उनसे बातें हुई । वह तो इलाहाबाद चले गये, लेकिन अपना एक प्रतिनिधि छोड़ गये । उनका नाम था श्री सरोज दत्त । फिर मैंने इम्प्लाइज के प्रतिनिधियों को बुलवाया और जो मुझसे और तुषार बाबू से बातचीत हुई थी वह मैंने उनको बतलाई । मैंने कहा कि चूंकि सरोज बाबू मौजूद हैं इसलिये आप लोग आपस में बातचीत कर लें तो अच्छा है । कुछ बातें उनकी हुईं । उसके बाद इम्प्लाइज और तुषार बाबू से इलाहाबाद में कुछ बातें हुईं । उसके बाद तुषार बाबू फिर आये और लिखकर दे गये कि फलां-फलां शर्तें, मैं उनको बाद में बतला दूंगा हमको मंजूर हैं और इसके आगे हम नहीं जा सकते । फिर मैंने इम्प्लाइज को बुला कर बतलाया कि यह-यह बात है और इसके आगे जाने को वह तैयार नहीं हैं । उन्होंने दो-तीन बातें और रखीं । मैंने फिर सरोज बाबू को बुलवाया और दो-तीन और बातें मनवाने में हम कामयाब हुये, लेकिन एक शर्त ऐसी थी कि जिस पर मैं समझता हूं कि समझौता होना कठिन है और इसलिये वह बात टूट गयी ।

मैं अब थोड़े में बतला दूं कि मैं दोनों को कहां तक राजी कर सका । एक तो यह कहा गया कि जो अंग्रेजी का अखबार है अमृत बाजार पत्रिका उसमें पुराने अखबार के जो लोग काम नहीं

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

करना चाहते हैं वह तो कानून के मुताबिक कम्पेन्सेशन ले कर घर बैठें लेकिन जो काम करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। अगर दो वर्ष के अन्दर यह नयी कम्पनी किसी वजह से बन्द हो गयी तो जो इस वक्त उनको कम्पेन्सेशन मिलता वह पुरानी कम्पनी उनको दे देगी। दो वर्ष के आगे पुरानी कम्पनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। उन्होंने कहा कि अगर ३, ४ साल में बन्द हो गयी तो हमने उनको इस पर राजी कर लिया कि अगर नयी कम्पनी किसी वक्त भी बन्द हो गयी तो जो कम्पेन्सेशन ड्यू है वह हम दे देंगे, वह पुरानी कम्पनी दे देगी।

दूसरी बात थी हिन्दी अखबार की। वह इस बात पर राजी हो गये कि हम हिन्दी अखबार भी निकालेंगे। बड़ी भारी बात यह थी कि हिन्दी अखबार वाले बेकार हुये जाते थे। लेकिन चूंकि अंग्रेजी अखबार चल रहा है इसलिये महीने, डेढ़ महीने के भीतर हिन्दी अखबार शुरू हो सकता है। और हिन्दी अखबार के लिये भी उन्होंने उस गारंटी को मान लिया कि अगर किसी वक्त भी यह बन्द हो गया, नयी कम्पनी बन्द हो गयी जो हिन्दी अखबार निकालेगी, तो जो कम्पेन्सेशन उनको आज मिलता, इम्प्लाइज को, उस वक्त भी जब अखबार बन्द होगा, वह पुरानी कम्पनी वाले देंगे। इम्प्लाइज ने भी इसको स्वीकार किया कि ठीक है। इससे हमारा काम चल सकता है और जो खतरा है वह दूर हो जायगा। नयी कम्पनी के पास पूंजी भी नहीं है। तो यह उनका अधिकार सुरक्षित हो गया। जो प्रेस के इम्प्लाइज हैं उनके लिये भी वह इस बात पर राजी थे कि ये इम्प्लाइज नयी कम्पनी के इम्प्लाइज होंगे और जो जर्नलिस्ट लोगों के अधिकार हैं वह अधिकार वह प्रेस वालों को देने के लिये तैयार होंगे, इस बात पर भी समझौता हो गया। चूंकि हिन्दी का अखबार निकलने में महीने दो महीने की देर होगी, उन लोगों की तरफ से कहा गया कि यह तो हम नहीं कह सकते कि पूरी तनख्वाह दी जाय मगर कुछ न कुछ बेकारी के जमाने के लिये मिलना चाहिये और वे इस बात के लिये भी राजी हो गये। यह तय हुआ कि रकम के लिये पीछे देखा जायगा। इस बात के लिये भी राजी हो गये कि हड़ताल के लिये विक्टीमाइजेशन नहीं होगा।

जिस बात पर समझौता नहीं हुआ वह यह है। उनका कहना था कि वेज बोर्ड के मुताबिक जो तनख्वाह तय होगी वही हम अब देंगे। उन लोगों का कहना था कि पुरानी कम्पनी के हिसाब से जो तनख्वाह होनी चाहिये थी वह मिले। यह एक ऐसी बात थी जो समझौते के तरीके से तय नहीं हो सकी, कानूनी तरीके से भले ही हो जाय। उसकी वजह सीधी सी है। अगर उनको पुरानी कम्पनी के हिसाब से तनख्वाह देनी होती तो उसे तोड़ते ही क्यों ? नये कायदे के मुताबिक यह है कि नये अखबार के लिये दूसरे नियम हैं और ए, बी, सी पुराने नाम नहीं चलेंगे। इस बात पर समझौता टूट गया। वे लोग कल शाम को आये थे। मैंने उनको भी खबर कर दी। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मैंने भी सलाम किया एन्ड आई वाश्ड आफ माई हैन्ड्स। and I washed off my hands मैंने दूसरी पार्टी को भी इसकी सूचना दे दी।

श्री राजनारायण---क्या मुख्य मंत्री जी ने यह भी जानने की कोशिश की कि पुरानी कम्पनी के मालिकान ने पहले दो साल में ३० लाख रुपया बचाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने निवेदन किया कि सरकार ने या मुख्य मंत्री ने कुछ नहीं किया। सम्पूर्णानन्द नाम का एक व्यक्ति था जिसे दोनों पक्षों ने यह मामला सौंपा था।

श्री अध्यक्ष---मुख्य मंत्री जी ने इस बात की जानकारी नहीं हासिल की।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दोनों दलों को सम्पूर्णानन्द जी की ओर से क्या सुझाव दिये गये ?

श्री अध्यक्ष---आपकी समझ में अब भी बात नहीं आई तो लाचारी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि समझौता नहीं हुआ तो वह मामले को आरबिट्रेशन ट्रिब्युनल को रेफर करने पर विचार करेंगे। इस पर क्या विचार हो रहा है और कब तक इसे रेफर करेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह काम हमारा नहीं है, केन्द्रीय सरकार का है। लेकिन चूंकि मामला कल रात को ही तो खत्म हुआ है, हमको भी सोचना होगा कि हम क्या करें और केन्द्रीय सरकार को क्या सलाह दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतानें की कृपा करेंगे कि अमृत पत्रिका के एम्प्लायर ने वर्कर्स को १२ जनवरी, १९५९ को जो नोटिस दिया था उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो भी दायित्व हैं, उनकी सर्विसेज में और सभी बातों में, पुरानी तरह से मानेंगे, यह बात मुख्य मंत्री जी के नोटिस में थी और क्या मालिकों ने इसे रद्द करने की कोशिश की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कन्टीन्यूइटी की बात उन्होंने मान ली थी और इस बात पर एम्पलाईज को पूरा संतोष है।

होली के हुड़दंगियों द्वारा रेलगाड़ी पर ढेले बाजी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर गृह मंत्री का वक्तव्य

***गृह मंत्री** (श्री कमलापति त्रिपाठी)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिस की गई। गोरखपुर के कलेक्टर को इसकी खबर भी नहीं थी। उनसे कहा गया है कि इसकी जांच-पड़ताल करके रिपोर्ट भेजें। अभी तक जो सूचना मिली है उससे मालूम होता है कि जी० आर० पी० में अथवा वहां के थाने में इस घटना की रिपोर्ट नहीं की गई और इस बात का वहां पता नहीं लगा कि किसने ढेला फेंका और किसको चोट आई। फिर भी, इसकी इन्क्वायरी वह कर रहे हैं और अगर कोई सूचना मिलेगी तो उसे सरकार के पास भेजें गे।

जहां तक ऐसी घटनाओं के लिये सरकार की ओर से सतर्कता बरतने की बात है, उसके लिये यह आदेश जारी हो रहा है कि होली के सिलसिले में जिला अधिकारी सतर्कता बरतें और गृह मंत्री जहां कहीं ढेला वगैरह फेंकने की घटना हो उसकी इन्क्वायरी करें और उस पर कार्यवाही करें। और ऐसी जगहों पर जहां मालूम है कि रेलों पर कीचड़ या ढेले फेके जाते हैं, जैसे कानपुर का जिक्र आया कि वहां यह होता है, ऐसी जगहों पर खास प्रबन्ध करें जिससे इस प्रकार की घटनायें वहां न होने पावें।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिला अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी तो जो सूचना मंत्री जी ने अभी दी है वह किस आधार पर दी है ?

श्री अध्यक्ष---मालूम होता है कि आज कोई नया तर्कशास्त्र आपने प्राप्त किया है। वह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या ऐसी कोई सूचना मंत्री जी के पास है कि उक्त घायल आदमी वहां के अस्पताल में दाखिल कराया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने निवेदन किया कि कलेक्टर इस मामले में और इन्क्वायरी कर रहे हैं। अभी तक इस बात की कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी स्वशासन विभाग के मंत्री जी को इस बात के लिये लिखेंगे कि वह सभी गांव प्रधानों को लिखें कि गांव सभाओं की ओर से इस बात का प्रयास हो कि इस तरह की घटना लोग न करें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, मैं अवश्य इस बात को देखूंगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती कमलादेवी की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२] के अन्तर्गत जानकारी की मांग

श्री अध्यक्ष---आज श्री जंग बहादुर वर्मा जी ने एक सूचना दी है कि "श्री सियाराम शुक्ल व श्रीमती कमला देवी शुक्ल निवासी अमौली कलां, जिला वाराबंकी पुलिस द्वारा विधान भवन के सामने २२--९--५८ को ११ बजे रात हिरासत में ले लिये गये थे और जेल में भेजकर फिर बलरामपुर अस्पताल में भरती कराये गये। श्रीमती कमला देवी की मृत्यु अनशनकाल ही में सरकार की असावधानी के कारण ३--३--५९ को अस्पताल में हो गई और सियाराम जी की भी हालत चिंताजनक है तथा सरकार व जेल अधिकारियों की ओर से असावधानी बरती जा रही है।

अतः उन दोनों के हिरासत के कारणों, श्रीमती शुक्ला की मृत्यु, तथा श्री शुक्ल की चिन्तनीय हालत आदि संबंधी बातों के संबंध में स्पष्टीकरण कराने के लिये नियम ५२ के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत करता हूं।" इसकी सूचना माननीय गृह मंत्री जी को हो तो दे दें कि क्या वे मर गयी हैं या कोई मरने वाला है।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मेरे पास इस वक्त इसकी सूचना नहीं है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले यह नोटिस मुझे मिला था। क्योंकि अभी इसके बारे में कोई इत्तला नहीं मिल सकी है, अगले दिन इसकी सूचना दे दी जायगी।

महानगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमारा एक नोटिस कार्पोरेशन के चुनावों के संबंध में कई दिन से चला आ रहा है।

श्री अध्यक्ष---मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। अभी मंत्री जी उसके बारे में निश्चय नहीं कर सक रहे हैं इसलिये नहीं बता सके हैं। जबरदस्ती तो उनसे आप कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण---मान्यवर, अगर उन्होंने तय कर लिया हो और बताना चाहें तो बता दें कि कार्पोरेशन का चुनाव कब हो रहा है?

***स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)**---कल जब मुझे इसका नोटिस मिला तो मैं अपने विभाग के उन लोगों से चर्चा कर रहा था जो इलेक्शन का प्रबंध कर रहेंहैं। मेरा खयाल इस विषय में यह भी था कि विरोधी दलों के नेताओं की राय इस संबंध में जान लूं। माननीय राजनारायण जी से सब से पहले मैंने पूछा कि सचमुच वे इलेक्शन कब चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी अपना दिमाग नहीं बनाया है, कोई बिचार नहीं किया है। मैं समझा कि जैसा उनका स्वभाव है कि सरकार ही हर चीज में गलती करती है उसी के अनुसार उन्होंने यह लिख कर भेजा कि सरकार भ्रमपूर्ण बयान दे रही है। लेकिन सरकार ने जो कहा वह यथार्थ ही था और जैसी परिस्थिति थी उसको वैसे ही रखने की चेष्टा की गयी थी नहीं तो पहले से ही हम यह कह सकते थे कि अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, अक्टूबर तक करायेंगे। लेकिन हमने ईमानदारी से यह कोशिश की कि उसको जल्द से जल्द करा सकें। कल की यह स्थिति है कि करीब १ लाख पुराने वोटर्स कैंसिल होते हैं कानपुर में, इतने ही नये एडीशन्स होंगे। तो कहीं ४० हजार और कहीं ६० हजार नये नाम रखने हैं यह सब सूचियां छपवानी होंगी; इसलिये डिपार्टमेंट की यह राय है कि १५ मई से एक दिन पहले भी हम तैयार नहीं हो सकते हैं। इस सदन में और उस सदन में जब मैंने विधेयक पेश किया था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मुझे यह आशा थी और मैंने यह कहा था कि मई के प्रथम सप्ताह में चुनाव कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम समझते थे कि १५ मई के बाद लू चलने लगती है। लेकिन चूंकि अब १५ मई के बाद ही तैयार हो पायेंगे इसलिये हमने सोचा कि २० जून के बाद या तो बारिश हो जाती है या कम से कम लू बन्द हो जाती है, पुरवा चलने लगती है। इसलिये २० जून से ३१ जून तक किसी दिन अन्तिम प्रोग्राम है चुनाव कराने का।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय विचित्र नारायण जी के मुखारबिन्दु से कुछ ऐसे वाक्य निकल गये जिनके संबंध में हमें स्पष्टीकरण करना पड़ रहा है। १०-१२ दिन हुए जब माननीय विचित्र नारायण जी से हमने निवेदन किया था कि साल भर होने जा रहा है, लेकिन पता नहीं पड़ा कि चुनाव कब होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक दिक्कत है हम एक संशोधन उसमें लाने जा रहे हैं एक क्लाज में जिसमें ६ महीने पहले की सजा के बारे में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर वह क्लाज रहता है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा हमको तो पूरी ही दिक्कत है। उधर तो ३०-३२-४०-४२ वाले लोग ही हैं, लेकिन इधर ५७, ५८, ५९, ऐसा कोई साल न होगा जब कि सजा न काटनी पड़ी हो किसी में १९ महीने की सजा हुई, किसी में ६ महीने की सजा हुई तो इसका बोझ सब तो हमारे ऊपर पड़ता ही है। इस पर उन्होंने हमसे कहा कि तुम क्या कहते हो, तो मैंने उनसे कहा कि इसको तो आपको किसी तरह से हटाना ही चाहिये और ऐसा कोई संशोधन विधेयक लावें और कभी अधिक समय तक बैठ कर उसको पास कर लिया जाय। उसी बात को स्मरण करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मैं क्या बतलाऊं, मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज पकी पकाई तो नहीं है जिसे मैं बतलाऊं। श्रीमन्, इस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ कर न कहना चाहिये। आप जरा इनको तंबीह कर दीजिये।

२३ मार्च को सदन की बैठक न करने की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के नेता से जो २३ मार्च को सदन का उपनिवेशन होने वाला है, उसके संबंध में प्रार्थना करना चाहता हूं और वह यह है कि होली जनसाधारण का एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसलिये सदन के लगभग सभी दलों के बहुत से माननीय सदस्यों से मेरी बातचीत हुई है और सभी की इच्छा यह है कि २३ मार्च को सदन का उपनिवेशन न हो। इसमें सदन के माननीय नेता को कठिनाई होगी, तो मैं चाहता हूं कि सभी दल के लोग मिल कर कोई बात तय कर लें कि या तो उस दिन उपनिवेशन न हो और किसी तरह से एडजस्ट करके एक दिन छोड़ दें या यह हो सकता है कि २३ तारीख को हम जो ४ साढ़े ४ या ५ घंटा बैठते तो किसी दिन दो ढाई घंटे तक अतिरिक्त समय के लिये शनिवार को या और किसी दिन बैठ जायं। तो इस तरह से अगर हम लोग आपस में तय करके माननीय नेता सदन के पास पहुंचें तो क्या वे इस चीज को स्वीकार करने की कृपा करेंगे कि २३ तारीख को सदन का उपनिवेशन न किया जाय ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इस संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। पालीवाल जी ने अभी सुझाव दिया है मगर मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस पक्ष के कम से कम पचीसों आदमी हमारे पास आज सुबह से आ चुके और उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये ताकि हम लोग होली से पहले घर पहुंच जायं। तो यह सुझाव कांग्रेस पक्ष का भी है। ऐसा न माना जाय कि यह खाली पालीवाल जी का ही सुझाव है, कहीं माननीय नेता सदन को यह गलतफहमी न होनी चाहिये कि यह पालीवाल जी का सुझाव है और कांग्रेस पक्ष का नहीं है।

[श्री राज नारायण]

लेकिन हां, अगर हमारे सामने यह बात आयेगी तो हम इस प्वाइन्ट से इसके ऊपर जरूर सोचेंगे कि कहीं इसका बोझ खजाने पर तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ४ दिन से ज्यादा छुट्टी हो रही है। अगर ५, ६ दिन की छुट्टी यों ही होती तब तो दूसरी बात थी। एक दो दिन की छुट्टी बढ़ जाती है तो उसका बोझ जनता पर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---६ रोज की छुट्टी तो हो रही है, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री राजनारायण---बात यह है कि हरिजन सहायक अनुदान पर मुझे बोलना है क्योंकि मैं अभी तक किसी अनुदान पर खुल कर नहीं बोल सका हूं। सारी जानकारी मैंने हासिल कर ली है कि सरकार जो हरिजनों का कल्याण करने का दावा करती है उसके द्वारा उनका कितना अकल्याण हुआ है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, कम्युनिस्ट ५०० हैं या १,००० हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। श्रीमन्, कांग्रेस का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी तो यहां १ और १० के हिसाब से है। हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं। यह हमारे नेता आगे बढ़ते जा रहे हैं यह कैसा समाजवाद है ?.....

श्री अध्यक्ष---आप कितनी छुट्टी चाहते हैं ?

श्री टीकाराम पुजारी---मैं कहूंगा कि मथुरा से उनका प्रेम है और मथुरा में ही, नन्दगांव और बरसाने में, यह त्योहार मनाया जाता है। मुझे आशा है नेता सदन इसको स्वीकार करेंगे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप मथुरा में निमंत्रित करना चाहते हैं नेता सदन को कि वह होली में वहां जायं ?

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य सभी लोगों के दुख दर्द को पहचानते ह और उनको इस बात का हमेशा खयाल रहता है, चाहे कोई किसी दल का हो, वह भी होली मना सकें। इसलिये मैं समझता हूं कांग्रेसी पक्ष के लोगों ने सभी लोगों से बातचीत की होगी कि लोग होली का त्योहार मना सकें। मुमकिन है माननीय राजनारायण जो से भी बात की हो। मुझे दस्तखत करके दिया क्योंकि लोगों की तकलीफ का पूरा खयाल था और मैं भी चाहता हूं कि २३ तारीख को सेशन न हो। उसके लिये जो भी रास्ता सब लोग तय कर लें अगर जरूरत हो तो इतवार को बैठ जायं नहीं अगर ऐसी बात हो तो जैसा माननीय पालीवाल जी ने कहा कुछ घंटे बढ़ा लिये जायं। ऐसा हो सकता है कि शनिवार के दिन सवालों का घंटा होता नहीं तो ११ बजे से पहले कुछ बैठ जायं और उधर ५ बजे के बाद बैठ जायं। जो भी तरीका हो, जैसा तय हो जाय उसको स्वीकार कर लें ताकि लोग आसानी से घर पहुंच सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने टीकाराम पुजारी जी की प्रार्थना को स्वीकार किया है ? और स्वीकार करके अगर वहां होली खेलने जायेंगे तो कौन बरसाने की तरफ से होगा और कौन नन्दगांव की तरफ से होगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं सदन के बाहर इसका निश्चय हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४५—लेखा शीर्षक ६३–क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय तथा ६३-ख—सामुदायिक विकास योजनायें

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५९–६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होंगे।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५-योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक ६३-क—युद्धोत्तर योजना (Post-war Planning) और विकास (Development) सम्बन्धी व्यय, और ६३–ख—सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८, ९७, ७३, ६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग पर विचार करते समय हमको अपने सामने प्लानिंग नियोजन, विकास के उद्देश्य को सदैव रखना चाहिये। जो भी काम प्लानिंग और डेवलपमेंट योजना और विकास के नाम से होते हैं उसके दो उद्देश्य हैं, या यों कहिये एक ही उद्देश्य है दो पहलू हैं। एक तरफ तो हम लोगों की भौतिक उन्नति को अपने सामने रखते हैं, खासतौर से देहात में रहने वाली जनता की। दूसरी तरफ हम केवल उतने से ही संतुष्ट नहीं होते, हम किसी प्रकार की ब्रेन वाशिंग नहीं करते, किसी एक बात को हठतः लोगों के दिमाग में प्रवेश कराने का प्रयास नहीं करते। लेकिन फिर भी यह तो हमारे सामने है ही कि जो विकास हो उसमें और बातों के साथ जनता के चरित्र और उसके स्वभाव का विकास हो, मनुष्य की उन्नति हो, उसके व्यक्तित्व का उचित रास्ते पर विकास हो। इन दोनों बातों को हमें अपने सामने रखना है। हमको इसका भी प्रयत्न करना है कि भौतिक उन्नति के साथ हमारे जो नागरिक हों वे ऐसे हों जिनमें वे सब सद्गुण हों जो भारत की संस्कृति के अंग हैं। उसमें सहिष्णुता हो, टालरेन्स हो, धार्मिक बातें हों, जो भारत के विशेष महत्वपूर्ण गुण रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसमें स्वार्थ की जगह परमार्थ की बुद्धि जागृत हो। हम चाहते हैं कि वह समझें कि मनुष्य की उन्नति का मार्ग संघर्ष नहीं, सहयोग है। कम्पीटीशन नहीं है, कोआपरेशन है। हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक वीर और स्वावलम्बी हों। जो भी हम कोशिश करें डेवलपमेंन्ट के नाम पर उसमें इन दो बातों को अपने सामने रखना पड़ता है। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो डेवलपमेंट, विकास के काम का क्षेत्र शायद प्रशासन और पुलिस को छोड़ कर सभी विभागों में हो जाता है। इसलिये यदि कोई विस्तार के साथ इस काम की बाबत कुछ कहना चाहे तो उसको फिर कृषि, चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि जितने भी विभाग हैं, उन सभी के बाबत कुछ न कुछ कहना चाहिये। परन्तु ऐसा करने में जो बातें दूसरे विभागीय अनुदानों के सम्बन्ध में कही गई हैं या कही जायंगी या कही जानी चाहिये थीं, उस सब की ओर जाना पड़ेगा, और यह सम्भव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसलिये बहुत थोड़ी सी बातों की ही चर्चा मैं कर सकता हूं।

जहां तक कि प्रचलित वर्ष है, उसके विषय में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि माननीय सदस्यों को जो पुस्तिकायें वितरित हुई हैं उनको उन्होंने देखा होगा, और जो विकास के काम होते रहते हैं उनको भी उन्होंने देखा होगा। फिर भी, दो-चार आंकड़े रखता हूं। इसलिये कि कुछ विभागों के ऊपर तो यहां सदन में विचार हुआ ही नहीं, और एक जगह वह आंकड़े हमारे सामने नहीं आये। पहली बात याद रखने की है कि हमारा जो बजट था प्लान का वह पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

४६ करोड़ ६६ लाख का बना प्लानिंग कमीशन से और हम से बातचीत होकर । बाद में कुछ रुपया बढ़ा और वह ४७ करोड़ ५० लाख रुपये का हुआ । इस बीच में कुछ काम जो हुआ उसका जिक्र करता हूं । जैसे, मनुष्यों के अस्पताल ३३ नये बने और ३५ की मरम्मत हुई । पशुओं के अस्पताल आई० जी० ब्लाक्स में ५४ बने और ७५ स्टेज वन ब्लाक्स में । बी० बी० के लिये बी० सी० जी० वैक्सीनेशन हुये १३ हजार ८०७ । पक्की ड्रेन्स २ लाख ३० हजार । सोकेज पिट, जिसमें गन्दा पानी निकलता है ४१ हजार ८७४ । १९० प्राइमरी स्कूल्स बने । १,८७१ लाइब्रेरीज देहाती क्षेत्रों में बनीं । २३ हजार प्रौढ़ों को शिक्षा दी गई । ब्लाक क्षेत्र में १९२ कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं जिनके ४,७८८ मेम्बर हुये । माइनर इर्रीगेशन नहर, ट्यूबवेल को छोड़ कर, पर १ करोड़ ५६ लाख ३८ हजार रुपया खर्च हुआ।

यह आंकड़े प्रदेश को देखते हुये, प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम हैं । जानबूझ कर मैंने इनका जिक्र किया है । आंकड़े थोड़े हैं । परन्तु इनसे कुछ बातों का अन्दाजा तो लगता ही है । जब हम विकास की बात करते हैं तो कितनी ही भिन्न-भिन्न दिशाओं में हमको सोचना पड़ता है । किसी एक दिशा की बात देखी जाय, किसी एक विभाग के सम्बन्ध में देखा जाय तो काम बहुत थोड़ा-सा मालूम होता है । लेकिन सब दिशाओं के काम जब किसी एक बिन्दु पर मिलते हैं तब थोड़ी सी तस्वीर इस बात की आती है कि अपने रिसोर्सेज को देखते हुये हम किस दिशा में जा रहे हैं । कितना हमने काम कर लिया इसका मैं जिक्र नहीं करता । लेकिन दो बातों का जिक्र करना पड़ता है । एक तो हमारे दो कम्पेन हुये, रबी और खरीफ, जो रबी और खरीफ अभियान कहलाते हैं । मैंने कुछ लोगों के मुंह से उनकी शिकायतें भी सुनीं और कुछ लोगों को उनके सम्बन्ध में हंसते भी देखा । कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि यदि कुछ लोगों को इन अभियानों के सम्बन्ध में ४ शिकायतों का पता होगा तो मुझे १४ शिकायतों का पता है । जहां तक हंसने की बात है, एक बात का खयाल रखना चाहिये कि एक बच्चा है । जब वह चलने की कोशिश करता है तो उस को देखकर जरूर हंसा जा सकता है, वह सीधा ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, चलता है उसका शरीर दस बार बल खाता है, गिरता है, उस पर हंसा जा सकता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से हमें यह भी याद रखना है कि यही आगे चलकर जब जवान होगा तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, तो उस के ऊपर बचपन में वह हंसना नहीं है बल्कि उस की मदद करना है ताकि वह आगे ठीक चलना सीख सके और उसका हर प्रकार का विकास हो । वह एक नया काम था, किसी सूबे में इस तरह का काम नहीं हुआ था, सबसे पहले हमारे यहां खरीफ अभियान हुआ और उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रादेशिक सरकारों का इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया कि आप लोग भी अपने यहां करें । तो कोई काम पहले कभी कहीं न हुआ हो उस में आरम्भ में गलती हो भी सकती है और जाहिर है कि जो आदमी गलती के डर से आरम्भ में ही रुक जायगा वह कभी कोई उपयोगी काम नहीं कर सकता, कोई अगर तय कर ले कि बिना पानी को छुये ही तैरना आ जाय तो यह मुमकिन नहीं हो सकता, हम में से जो लोग तैरना जानते हैं उन सबको अनुभव होगा कि पानी में दो-चार बार गोता खाये बिना तैरना नहीं आता । इसी तरह से हमने इस नये काम को किया, उसमें शिकायतें भी हैं और वह कई प्रकार की हैं ।

मंत्रियों के दौरे के बारे में कहा गया । मैं तो बहुत कम दौरा करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करता ही हूं, शहरों में भी जाता हूं और देहातों में भी जाता हूं, लोगों से मिलता भी हूं, जो चीजें अपनी आंखों से देख सकता हूं वह देखता हूं, जो कुछ अपने कानों से सुन सकता हूं वह सुनता भी हूं, लेकिन इस सदन में जो ४०० से अधिक व्यक्ति हैं उन की आंखों से मैं बहुत कुछ देखता हूं और उनके कानों से सुनता हूं, उसी से मुझे अधिकतर खराबियों और सफलताओं का पता चलता है । लेकिन एक ही चीज का चारों तरफ से जिक्र होने लगे तो उसका बड़ा असर होता है । हमने खरीफ अभियान की गलतियों को देखकर रबी अभियान चलाया और हमारा विश्वास है कि खरीफ अभियान की अपेक्षा हमारा रबी अभियान सफल रहा । आगे फिर हम दूसरा अभियान चलाने वाले हैं और आगे भी हम और बड़े अभियान चलायेंगे ।

इसी तरह से हमने एक चीज और चलाई है जैसा कि अभी हमने ग्राम सहायकों की बात कही। हमने ढाई लाख व्यक्तियों को ट्रेन्ड करके ग्राम सहायकों के रूप में अभियानों में काम लिया है। इस सम्बन्ध में पिछले प्रयोगों की सफलता से हमें सन्तोष है और नये वर्ष में हम ढाई लाख के मुकाबले में दस लाख ग्राम सहायक और ट्रेन्ड करेंगे। इसके अलावा हम उनसे केवल इतना ही काम नहीं लेते कि वे अभियानों का काम करके घर बैठें, हालांकि उनको कोई खास शिक्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी यह ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि यह हमारा काम है और हमारे ऊपर इस काम की भारी जिम्मेदारी है। हम केवल इतने से ही सन्तुष्ट होकर नहीं बैठेंगे बल्कि उनसे आगे और भी काम लेंगे उन कामों के बारे में मैं बता दूं जैसे हम ने तय किया है कि हर गांव में एक छोटी सी समिति होगी जिस समिति का काम खास तौर से होगा उस गांव में कृषि के काम को देखना, उस समिति में कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे वहां की पंचायत उसके विरोध में हो जाय, वह समिति गांव पंचायत के मातहत रहेगी, उसमें ग्राम सहायक होंगे, विलेज लेविल वर्कर होंगे, उस गांव के पंचायत सेक्रेटरी होंगे, लोकल कोआपरेटिव के सदस्य, सरपंच, गांव के मास्टर साहब होंगे। वहां अगर कोई ट्यूबवेल आपरेटर हैं तो वे होंगे, तो वहां इस तरह से एक कृषि कार्य समिति कायम होगी। वह उस गांव के लिए योजना तैयार करेगी फैमिली वाइज और फिर विलेज-वाइज। यह छोटी सी बाडी है गांव की जो कि हर परिवार की बाबत देखेगी कि उनके पास कितने साधन हैं, और उनसे कृषि के मामले में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, किस चीज की उन्हें जरूरत है और उसके आधार पर वह विलेज का टार्गेट बनायेंगे। उसको फिर वह ग्राम पंचायत के सामने रखेंगे। ग्राम पंचायत उस पर राय देगी और उसके अनुसार उस पर इम्पलीमेंटेशन करेंगे। मैं समझता हूं कि हम सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उनको देनी है वह खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए एक ऐसी चीज है जो गांव पंचायत के आदेश के अनुसार और उनकी देखरेख में होगी। तो हर गांव में यह कृषि कार्य समिति कायम होगी।

एक चीज और पिछले साल हुई, जो कि खत्म होने वाला है, वह यह कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का रूप बदला। अभी तक यह इरादा था कि एन० ई० एस० ब्लाक्स होते थे। कुछ दिनों के बाद वह इंटेंसिव ब्लाक्स हो जाते थे और फिर नार्मल ब्लाक्स हो जाते थे और सामान्य प्रशासन के अन्दर आ जाते थे। अब केन्द्र से यह निश्चय हुआ और मेरी समझ में अच्छा निश्चय हुआ कि इसको बदला। दो रूप ब्लाक्स के हैं---स्टेज १ और स्टेज २। स्टेज १ के माने यह हैं कि जब एन० ई० एस० ब्लाक आई० डी० में बदल जाता था और स्टेज २ वह है जो आई० डी० खत्म होने के बाद नार्मल, साधारण, अवस्था हो जाती थी। स्टेज १ में ५ वर्ष लगेंगे और स्टेज २ में भी ५ वर्ष लगेंगे। स्टेज १ में १२ लाख रुपया खर्च होगा और स्टेज २ में ५ लाख रुपया खर्च होगा। मेरी समझ में यह तरीका अच्छा है पहले तरीके से। क्योंकि पहले जब आई० डी० के बाद नार्मल अवस्था होती थी तो ब्लाक बिल्कुल छूट जाता था। अब उसका विकास होता रहेगा। इस वक्त प्रदेश में ३७० ब्लाक्स हैं, २५५ स्टेज १ में है और ३३ स्टेज २ में और ८२ पुराने इंटेंसिव डेवलपमेंट के तरीके में चले आ रहे हैं। इनमें प्रदेश के क्षेत्रफल का ४६ प्रतिशत अंश कवर होता है और देहात की जन-संख्या का ४६.८ कवर होता है। अब जो नया साल शुरू होने वाला है इसमें हम यह करने वाले हैं कि ५६ ब्लाक स्टेज २ में जायेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि ५२.६ प्रतिशत क्षेत्रफल तो उससे कवर हो जायगा और आबादी का ५३.४ कवर हो जायगा। इसके बाद हम ७४ ब्लाक्स की तैयारी करेंगे तैयारी से मतलब यह है कि जो नया कायदा है उसके अनुसार ब्लाक को स्टेज १ में लेने के पहले कृषि की दृष्टि से उसको तैयार किया जाता है तो ७४ का आधा ३७, ३७ को तो अगली अप्रैल में लेंगे और ३७ को जो बाकी बचे उनको अगले अक्तूबर में लेंगे, ताकि जो नया साल शुरू हो उसमें ७४ तैयार हो जायं। यह एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जो कि हर दृष्टि से अच्छा है और हमको इसका स्वागत करना चाहिए।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अभी तक स्त्रियों का जो प्रोग्राम होता था उसमें यों कहिये कि वह दो तरफ से होता था। कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से होता था और कुछ सोशल वेल्फेयर की तरफ से, तो दोनों डिपार्टमेंट का काम एक में मिला दिया गया है। इससे काम भी अच्छा होगा और जो एक संघर्ष रहता था, क्योंकि जब दो संस्थाएं काम करती हैं तो कुछ ही हो जाता है वह खत्म होगा और जो रुपया आयेगा उससे अच्छा काम होगा।

माइनर इरिगेशन में स्वभावतः सबको अच्छी तरह से दिलचस्पी है। यह नहीं कि नहरें और ट्यूबवेल बेकार हैं। अभी कल मैं यहां बहस सुन रहा था, तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहां ट्यूबवेल की जरूरत है। ठीक है, ऐसी जगहें हैं जहां जरूरत है और लगने चाहिये। लेकिन नहरों के बनाने में कुछ खतरा भी होता है। हमको ही नहीं--- योरुप के बारे में तो मैं नहीं कह सकता---लेकिन अमरीका में उनको खतरा है और वह यह कि जब नहरें बहुत दिनों तक चलती हैं तो नीचे पानी का लेवेल ऊपर उठ आता है और उसके साथ-साथ सोडियम साल्ट नीचे से खिंच कर ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से वहां पानी से लाइम, खारा हो जाता है और जमीन ऊसर हो जाती है। हमारे यहां पश्चिमी जिलों में जहां नहरें बहुत पहले से चल रही हैं इस बात का कुछ-कुछ खतरा आ गया है। अमरीका में इसका काफी खतरा है, लेकिन उनके पास रुपया भी बहुत काफी है लिहाजा वे तो यह कर रहे हैं कि जहां न हों हैं उनके पैरेलल, उनके साथ-साथ ड्रेनेज का भी इन्तजाम कर दिया है। लेकिन यह चीज बड़ी महंगी है, जितना रुपया नहर बनाने में लगता है उतना ही रुपया ड्रेनेज बनाने में भी लगता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम इतने गरीब हैं कि यह हमारी शक्ति के बाहर है। इसलिये नहरें बढ़ाने की जहां बात है वहां यह बात भी देखनी है, यह न हो कि एक बीमारी को हम दवा करें और वह दवा खुद एक बीमारी पैदा करे। इसीलिये जो नयी नहरें हम बनाते हैं तो कोशिश यह करते हैं कि उसकी दीवारों को पक्की कर दें। लेकिन यह बहुत महंगी चीज है और हमारे लिये बहुत मुश्किल हो रहा है।

छोटे-छोटे पक्के कुएं हर जगह हो सकते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। उसमें एक बड़ा भारी फायदा है। यह नहीं कि हम नहर और ट्यूबवेल को छोड़ रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे कुएं कम से कम एक व्यक्ति के जाती होते हैं। नहर और ट्यूबवेल सरकार के होते हैं और उनकी देखभाल करने के लिये काफी रुपये की जरूरत पड़ती है। कुंआ जिसका होता है साधारणतौर से माना जाना चाहिये कि वह आदमी खुद ब खुद उसकी देखभाल कर लेगा। इसलिये हम जरूर इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने जो पीछे पब्लिक लोन लिया था तो जो लोन हमने मांगा था उससे ७० लाख रुपये ज्यादा मिल गया था, हमने उसका बहुत बड़ा हिस्सा छोटे कुओं में ही लगाया। कल यहां कुछ जिक्र हुआ, छोटे कुओं के सिलसिले में कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि रहट और कुआं मिला कर ६--७ सौ रुपये में बन जाते हैं। हमने जो औसत लगाया तो हमारे हिसाब से १८--१९ सौ रुपये लग जाते हैं और फिर जैसा जहां पानी होगा वैसे कम कीमत भी लग सकती है बहरहाल, माननीय सदस्य देखेंगे कि हमने सब मिला कर २,६६,६६,००० रुपये तो माइनर इर्रीगेशन के लिये बजट में रखे हैं।

बार्डर एरिया का भी जिक्र आया जहां तिब्बत की ओर हमारी सरहद मिलती है। वहां के क्षेत्रों के विकास की खास जरूरत है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कल कहा था वहां के भोटिया लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। पहले उनका तिब्बत से व्यापार होता था, यहां की चीजें तिब्बत जाती थीं और तिब्बत की चीजें इधर आती थीं और खासतौर से सोहागा इधर ल आया करते थे। लेकिन जब से तिब्बत में चीन सरकार का प्राधान्य हुआ है तब से यह तो मैं नहीं कह सकता कि व्यापार बिल्कुल बन्द हो गया है, लेकिन हमारे भारतीय भोटिया व्यापारियों के रास्ते में बहुत बाधा पैदा हो गयी है, उनके क्षेत्र का विकास करना ही होगा। उनके लिये जीविका के दूसरे साधन निकालने होंगे। हमने इस साल भी बजट में वहां के लिये विशेष रूप से ३८,००,००० रुपये रखे हैं, और रख सकते तो अच्छा होता।

एक चीज का जिक्र मैं सदन में पहले कर चुका हूं कि हमारे कुछ क्षेत्र हैं जिनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक तो जो परमानेंट स्केयरसिटी एरियाज हैं, यानी जो पूर्वी जिले कहलाते हैं दूसरे बुंदेलखंड का क्षेत्रफल, तीसरे पहाड़ का क्षेत्र और चौथा उसी से कुछ मिलता जुलता मिर्जापुर और दूधी का क्षेत्र। ये क्षेत्र कई दृष्टियों से बहुत ही पिछड़े हुये हैं। इनमें यातायात के साधन नहीं हैं और आबादी बहुत ज्यादा है। जमीन लोगों के पास बहुत कम है, इत्यादि इत्यादि। उनके लिये कोई न कोई विशेष प्रबन्ध करना होगा क्योंकि स्पून फीडिंग कब तक होगी। खैराती तरीके से कब तक काम चलेगा। इसी के लिये हमने स्कीम बनायी। करीब १० करोड़ से कुछ ज्यादा की करीब १३ और १४ करोड़ के हमने स्कीम बनायी और प्लानिंग कमीशन के पास भेजी, भारत सरकार के पास उसको भेजा गौर करने के लिये और उसके साथ-साथ कुंआ बनाने के लिये जो हमारी स्कीम थी उसके लिये हम ३ या ४ करोड़ रुपया चाहते हैं। एक और मुसीबत है जो पिछले तीन चार वर्षों से हमारे सामने आ रही है। पश्चिमी जिलों की ड्रेनेज स्कीम की वह बात है। आम तौर से वहां पानी ज्यादा नहीं बरसता, लेकिन जब बरसता है तो नहीं निकलता। मथुरा जिले में हाल में पानी जमा रहा। अलीगढ़ के जिले में और मेरठ के कुछ हिस्से में कई हिस्सों में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वहां पानी जब बरसता है तो बहने का कोई साधन नहीं है और खेती बारी को नुकसान पहुंचाता है और कस्बों को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिये भी ६ करोड़ पये का एस्टीमेट है यानी सब मिलाकर २० करोड़ का एस्टीमेट है।

हमने प्लानिंग कमीशन से कहा कि रुपया दीजिये तो उनका एक सीधा सा जवाब होता है कि प्लान को काट कर निकालिये। कहां से निकालें? ४६ करोड़ का प्लान है, ५४ करोड़ मांगा था, लेकिन ५० करोड़ मिला है। अब किसमें से काटें, खेती में से काटें, इंडस्ट्रीज से काटें, दवा दर्पण से काटें? कोई जगह काटने की नहीं है। तो हमने कहा कि हम इसमें तो काट नहीं सकते हैं। हमने कहा कि हमें इन कामों के लिये अलग से रुपया दो। अगर अलग से रुपया नहीं मिलेगा तो आखिर लोगों को तकावी देनी पड़ती है, रिलीफ देनी पड़ती है, मकान गिरते हैं तो बनवाने होते हैं, सड़क टूट जाती है तो मरम्मत करवानी पड़ती है, सस्ते गल्ले की दूकानें खुलवानी पड़ती हैं। इस सब में काफी रुपये खर्च किये गये हैं इसलिये हमको रुपया मिलना चाहिये। हमसे वादा किया गया कि हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। ध्यान दिया गया, लेकिन सिर्फ २ करोड़ रुपया प्लान के बाहर मिल सका। हमने उनसे कहा था कि आप एक साल के अन्दर न दे सकें तो इसको ३-४ चार वर्ष के अन्दर फैला दीजिये। बहरहाल वह तो नहीं हुआ और २ करोड़ रुपया मिला है। अब इसमें जैसे एक मसल है कि "नंगी क्या निचोड़े और क्या पहने" अब उसी २ करोड़ रुपये को हम फैला रहे हैं। कितना कुओं के लिये दें, कितना पूर्वी जिलों के लिये दें और कितना पश्चिमी जिलों में ड्रेनेज स्कीम के लिये दें? बहरहाल इसमें सबके लिये कुछ न कुछ तो करेंगे ही।

हमने २५ लाख रुपये पश्चिमी जिलों की ड्रेनेज स्कीम के लिये रखे हैं और ऐसा विचार है कि २० लाख रुपये और शायद दे दें क्योंकि वहां ड्रेनेज बहुत कम है। यह बहुत कम है, लेकिन हमें आशा है कि अगले साल के लिये ४५ लाख रुपये ड्रेनेज स्कीम के लिये रख सकेंगे।

अब अपने दो तीन और कामों का जिक्र करता हूं। एक जैसे स्पोर्ट्स का काम है। स्पोर्ट्स के लिये कई माननीय सदस्यों को यहां दिलचस्पी भी है। वे देखते हैं। केन्द्रीय सरकार काफी रुपया खर्च करती है और थोड़ा बहुत हम भी खर्च करते हैं। स्पोर्ट्स के सिलसिले में एक बात की जरूरत है कि आम तौर से जिन स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया जाता है वह वही होते हैं जो ओलम्पिक्स में आते हैं। तेवरस साल मेरा खयाल इस तरफ गया कि हमारे देश में भी कई तरह की चीजें हैं जो ओलम्पिक्स में नहीं हैं।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

भारतीय एक्सरसाइजेज और भारतीय स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देना चाहिये । तेवरस साल हमने शुरू किया । पहला काम था और हमने हर जगह से टीम बुलाई । एक टीम बड़ौदा से भी आयी थी । हमारी एक शिकायत भी है कि हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं उनमें से शायद दो चार सज्जन गये होंगे । अगले साल हम उसे फिर करेंगे और उसे हम बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमें आशा है कि हमारे लोग सब इसमें दिलचस्पी लेंगे और अगर हम लोग दिलचस्पी लेंगे तो बहुत संभव है कि हमारी चीजें भी ओलम्पिक में शामिल हो जायंगी और वह न भी शामिल हों तो भी हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उनमें कई ऐसी चीजें हैं जो दूसरे स्पोर्ट्स से किसी माने में कम नहीं हैं । उदाहरण के लिये रेसलिंग यानी कुश्ती लड़ना । आज तो पश्चिमी ढंग की जो कुश्तियां हैं उनकी बड़ी चर्चा है, लेकिन मैं उसको लज्जाजनक समझता हूं, पाप की चीज समझता हूं । मैंने कई वर्ष पहले से ही संकल्प कर लिया है कि मैं ऐसी चीज कभी नहीं देखूंगा। जिस देश में हजारों वर्ष की परम्परा चली आती है वहां के पहलवान उसको छोड़कर इस तरह की कुश्तियां लड़ें, यह कोई भी देखने जाय तो यह बड़ी लज्जा की बात है । ओलम्पिक्स में हमारे यहां की सी कुश्तियां नहीं हैं । पहले राजा महाराजा जो होते थे वह इस तरह लोगों को प्रोत्साहित किया करते थे । लेकिन अब चूंकि राजे महाराजे रहे नहीं इसलिये उनको प्रोत्साहन करने वाला कोई नहीं रहा । इसका नतीजा यह हुआ है कि भारतीय पहलवान अपने पेट पालने के लिये आज फ्री स्टाइल की कुश्तियां लड़ते हैं । जहां राजा महाराजा न हों वहां समाज को प्रोत्साहन देना चाहिये । रूस में राजा महाराजा नहीं हैं वहां पब्लिक प्रोत्साहन देती है । इसी तरह से हम लोगों को भी इसका बहुत ध्यान रखना चाहिये । यह हमारी चीज है, हमारे राष्ट्र की चीज है और हमारे राष्ट्र का तकाजा है कि हम इसको अपनायें । अगर हम इसको अपनाने के लिये तय करेंगे तो सारी दुनिया को इसे मानना पड़ेगा । यह बहुत अच्छी चीज है और बहुत ऊंची चीज है ।

इसी तरह से हमारा थोड़ा सा काम टूरिज्म का है। इंविजिबिल इंकम, अदृश्य आमदनी हमारी टूरिज्म के द्वारा हुआ करती है, पहले जो कुछ भी हो जाती थी और कुछ विदेशी लोग ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थानों में आजाते थे और तीर्थ-स्थानों में कुछ लोग आजाते थे । अब भारतीय सरकार टूरिस्ट्स को आकर्षित करने की कोशिश करती है और हम भी उनको सुविधा देने की कोशिश करते हैं । अब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है । हमारे यहां ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सौन्दर्य की दृष्टि से बहुत सी अच्छी जगहें हैं । इसलिये हम आशा करते हैं कि भविष्य में अधिक से अधिक लोग हमारे यहां आयंगे और इस तरह से हमारे अदृश्य आमदनी काफी हो सकेगी ।

एक चीज और है जिसकी कभी कभी आलोचना हो जाया करती है। जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते हैं उनमें हंसी, खुशी तथा मनोरंजन के कार्यक्रम सम्मिलित हैं । इनका हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान है । वह तत्व जो जगत को परिचालित कर रहा है उसका रूप है "सत्यं, शिवं, सुन्दरम्" । जिस हद तक हम ज्ञान का संग्रह करते हैं उस हद तक हम उसके सत्यं रूप को देखते हैं, जिस तरह से हम अपने आचरण में एकता लाते हैं, द्वेष को दूर करते हैं और स्वार्थ बुद्धि को त्यागकर परार्थ बुद्धि की स्थापना करते हैं उस हद तक हम उसके शिवं रूप से साक्षात्कार करते हैं । जिस हद तक हम सौन्दर्य को ग्रहण करते हैं चाहे वह पहाड़ के जमें हुये बर्फ के रूप में हो, चाहे चटकती कली के रूप में हो और चाहे सुन्दर आकाश के रूप में हो उस हद तक हम उसके सुन्दरम रूप से साक्षात्कार करते हैं ।

हमें भूलना नहीं चाहिये कि जिस शंकर को इस देश के इस करोड़ों आदमी ज्ञान का भंडार मानते हैं, उसका नाम नटराज है और जिस कृष्ण ने हमारे देश में गीता का उपदेश

दिया और उसमें कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया वही संगीत मार्ग में हमारे कुलगुरू हैं । जैसे कहा गया है कि :—

"साहित्य संगीत कला विहीनः ।
साक्षात पशुः पुच्छ विषाण हीनः ॥ "

यानी हम अपने देश में पशु नहीं चाहते हैं बल्कि मनुष्य चाहते हैं जिसे संस्कृत भाषा में "कृत्स्न" कहते हैं और अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड कहते हैं। इसके माने हैं कि जीवन का हर पहलू जाग्रत हो । वैसे तो आज भी लोग गाते हैं, नाचते हैं, होली पर भी लोगों के यहां गाया जाता है । लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों का सांस्कृतिक जीवन हो और उसमें सुरूचि आनी चाहिये । आपने देखा होगा कि साल के शुरू में कलेंडर्स बिका करते हैं, उनमें किसी में शिव पारवती की तस्वीर होती है और किसी में किसी और की । उनको सिवाय इसके कि अश्लील कहा जाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है । लेकिन पढ़े लिखे लोग छपवाते हैं और कमरों में भी लगाते हैं । यह बड़े शर्म की बात है । हमारे कौंसिल के एक मुस्लिम सदस्य ने ऐसी दो तस्वीरों की तरफ ध्यान दिलाया तो हमने यू० पी० गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस निकाल दी है पब्लिशर्स को । कुरुचि की यह हालत है कि पढ़े लिखे आदमी ऐसी तस्वीरों को रखते हैं, और कोई आवाज नहीं उठाते। फिर बे पढ़े लिखे आदमी बेचारे क्या करेंगे ? जरूरत यह है कि लोगों के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाया जाय । लोगों की रुचि को संस्कृत किया जाय ।

माननीय सदस्यों को याद होगी कि कुछ दिन हुए हमने माननीय गोविन्द सहाय की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई थी । उसके सामने कई काम थे । खासतौर से यह काम था कि जो हमारे विकास के काम हो रहे हैं उनमें कितनी सफलता हुई और कितना पब्लिक कोआपरेशन हासिल हो सकता है । उस कमेटी के सामने कई सदस्यों ने और कई विरोधी दल के नेताओं ने साक्ष्य दिया है । जो कुछ भी साक्ष्य हुआ है वह बहुत उपयोगी है । अभी वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है । मुझको बतलाया गया है दस रोज के अन्दर प्रकाशित हो जायगी । हमें पूरा विश्वास है कि हम उससे पूरा लाभ उठा सकेंगे और हम अपने विकास कार्य को अधिक सफल और जनप्रिय बना सकेंगे ।

कई बार यहां यह सवाल उठा कि जो प्लान बनता है ऊपर से बनता है । नीचे से नहीं बनता है । ठीक बात है । जो हमारा पहला प्लान था वह गवर्नमेंट का प्लान था विद दि पीपुल्स कोआपरेशन । दूसरे प्लान के लिए कहा गया कि पीपुल्स प्लान विद आफिशियल्स कोआपरेशन। पूरे तौर से वह चीज नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश की गयी । लेकिन थर्ड प्लान कम से कम पीपुल्स प्लान होना चाहिये । उसमें आफिशियल्स का कोआपरेशन हासिल हो, लेकिन होना चाहिए पीपुल्स प्लान । इसके लिए जो तरीका हम सोच रहे हैं वह यह है कि हमारे यहां से आदेश जा रहे हैं हर जिले में कि जो ब्लाक की कमेटी है जिसका ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी नाम हो गया है, उसमें हर ब्लाक के सरपंच और सभापति भी हैं । वह अपने ब्लाक की बाबत बतायें कि उनके ब्लाक में क्या क्या होना चाहिए । शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, सिंचाई के लिए क्या होना चाहिए, उद्योग के लिए क्या होना चाहिए । जो जो आवश्यकताएं वह अपने ब्लाक के लिए समझें वह बतायें और यह मानना चाहिए कि ब्लाक की कमेटी अपने यहां की एक अच्छी सी तस्वीर भेज सकेगी । जब हर ब्लाक की रिपोर्ट आ जाय तो वह जिला स्तर पर प्लानिंग कमेटी या जिला अंतरिम परिषद् के सामने आये । हर ब्लाक की आवश्यकताएं उनके सामने होंगी । सब की तुलना करके, सबको एक साथ मिला कर वह अपने जिले की बाबत बतायें कि उनके जिले में क्या क्या विकास का कार्यक्रम होना चाहिए । वह चीज जब यहां आयेगी तो हमने हर विभाग में एक वर्किंग ग्रुप मुकर्रर कर दिया है ; फिर सब

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

को मिला कर सारे प्रदेश के लिए हम एक चित्र बनायेंगे । उसको लेकर प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार से बात करेंगे । मैं समझता हूं कि इसके सिवा और कोई दूसरा व्यावहारिक तरीका नहीं हो सकता । इस प्रकार जब नीचे से प्लान आयेंगे तो ऐसा होगा जिसको हम बैलेंस्ड प्लान कह सकते हैं । उसको ले कर प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार से बात करने में भी ताकत होगी । हम कह सकेंगे कि यह हमारे मिनिस्टरों की राय नहीं है, सरकार की राय नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश की जनता के प्रतिनिधियों की राय है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह सुझाव माननीय सदस्यों को पसन्द होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह मांग पेश करता हूं और आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ६३-क--योजना और एकीकरण के अन्तर्गत ८,९७,७३,६०० रुपये की सम्पूर्ण धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

योजना का प्रदेश की वर्तमान आवश्यकतानुसार अपर्याप्त, अव्यावहारिक तथा प्राथमिकता विहीन होना ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो अभी भाषण दिया है इस प्रमुख अनुदान को पेश करते समय उसमें एक बात की चर्चा उन्होंने की है कि इस नियोजन का उद्देश्य होना क्या चाहिये । उसकी चर्चा करते समय माननीय मंत्री जी ने कुछ बहुत सैद्धान्तिक बातों की भी चर्चा की है कि आया इस प्लान में संघर्ष से काम लिया जाय या सहयोग से काम लिया जाय और सहयोग को ही उन्होंने श्रेयस्कर बताया है । श्रीमन्, सेकेंड फाइव ईयर प्लान जब बन रहा था उस समय यूनियन के एक मंत्री देशमुख साहब ने प्रथम पंच वर्षीययोजना की चर्चा करते हुये कहा था कि प्रथम पंच वर्षीय योजना इसीलिये बनी थी कि जनता की क्रय शक्ति बढ़े, जनता में परस्पर सहयोग हो और देश का सर्वतोमुखी विकास हो । मगर श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद भी विकास के एक बहुत बड़े प्रोफेसर महालनवीस साहब ने अपने वक्तव्य में बताया था कि जनता की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, उनकी आमदनी दिनों दिन क्षीण होती गई और इस प्लान से कोई ज्यादा खास चीजें नहीं हो सकीं । श्रीमन्, जिस देश और जिस प्रदेश की जनता के लिये विकास की योजनायें बनायी जा रही हैं वह जनता कहां खड़ी है इसे भी हमें और योजना बनाने वाली सरकार को देखना होता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि जितना पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जनता का पैसा खर्च हुआ है उससे लोगों की क्रय शक्ति में क्या कोई वृद्धि हुई है ? हमारे यहां खाद्यान्नों के उत्पादन और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या वृद्धि हुई है ? खेती के अन्दर इन योजनाओं के पहले कितनी भूमि थी और योजनाओं के बाद कितनी भूमि ज्यादा आयी ? मैं यह सब जानना चाहता था, लेकिन माननीय मंत्री जी के भाषण से इस ओर मुझे निराशा हुई । इस पर कोई खास प्रकाश नहीं डाला जा सका । श्रीमन्, इन योजनाओं के ऊपर जब इस प्रदेश में करोड़ों रुपया खर्च हो चुका, जनता जो इस गरीबी और भुखमरी में भी टैक्स देती रही है, उसको देने के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद प्रति व्यक्ति की आमदनी कितनी बढ़ाई जा सकी है यह सरकारी आंकड़ों से माननीय सदस्यों को जाहिर होगा । सन् १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति ग्रामीण १८९.३ रुपया इनकम थी और १९५७-५८ में वह १८३.६ हो गई । ६ , ७ प्वाइंट प्रति व्यक्ति आमदनी घट गई ।

माननीय मंत्री जी ने कुछ पुरानी स्कीमों का जिक्र किया था और कुछ आगे आने वाले प्रोग्रामों का, नाचने-गाने, खेलने-कूदने के प्रोग्रामों का जिक्र किया था । मगर यह जानना चाहता हूं कि जब इतना व्यय होता है तो माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में क्या यह भी दिया गया कि वह असेस करे कि प्रति व्यक्ति इन योजनाओं

के बावजूद भी आमदनी क्यों घट गई ? उससे प्रदेश की जनता को यह मालूम होता कि इस गरीबी और भुखमरी के जमाने में भी अपना पेट काटकर हमने जो रुपया दिया उसको खर्च करने के बाद भी उसकी आमदनी क्यों घट गई ?

खाद्यान्नों की उपज का जहां तक सम्बन्ध है मैं एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं—गेहूं, चावल, जौ, चना, ज्वार, महुवा, कोदों, सावां, टांगुन, इनकी उपज १९५६–५७ में १०,७१३ हजार टन थी और १९५७–५८ में वह ९८८८ हजार टन हो गई । ८२५ हजार टन की कमी हो गई तमाम खाद्यान्नों में । बड़े बड़े ब्लाकों में हर ब्लाक पर ६४–६४ हजार रुपया खर्च करके मकान बनाया गया है । श्रीमन्, मैं बताऊं इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार एक्सपेरीमेंट में जनता का पैसा खर्च कर रही है । यह हमारे नियोजन में एक्सपेरीमेंट हो रहा है । माननीय मंत्री जी बड़े शिक्षा विशारद हैं, उनकी प्रयोगात्मक खोज में जब यह सब चीजें आती हैं तो श्रीमन्, इस बात की जांच क्यों नहीं हुई कि इस ८२५ हजार टन खाद्यान्न का क्या हुआ ? जब कभी इस सवाल को सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से उठाया जाता है तो सरकार के नुमाइन्दे या हमारे मंत्री महोदय कह देते हैं कि कमी का कारण दैवी आपत्ति है । दैवी आपत्ति का प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है । खासतौर से हमारे पूर्वी जिलों के लिये तो यही कह दिया जाता है कि बाढ़ आ गई होगी । अगर किसी वर्ष फसल अच्छी हो जाती है तो यह नहीं कहा जाता है कि बारिश अच्छी हुई या धूप अच्छी निकली । उसके लिये तो यही कहा जाता है कि यह सब हमारी विकास योजनाओं का फल है । उसका श्रेय सरकार अपनी रबी और खरीफ की अभियान योजनाओं को देती है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में इसको नहीं बताया कि इस पिछले २ वर्षों के अन्दर ८२५ हजार टन खाद्यान्न की कमी क्यों हो गई? इसकी चर्चा माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं नहीं की ।

हमारी सोशलिस्ट पार्टी बराबर चिल्लाती रही है कि अगर बेकारी दूर करना है और लोगों को रोजी देना है तो उसके लिये कम से कम एक 'अन्न सेना' बनाइये । इस प्रदेश में बहुत जमीन परती पड़ी हुई है जहां पर लोगों को काम पर लगाया जा सकता है जिससे लोगों को अन्न मिले, पेट भर भोजन मिले और बेकारी की समस्या हल हो और साथ ही पर कैपिटा इनकम भी बढ़े । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्लान पीरियड के अन्दर हमारी प्रदेशीय सरकार ने कितनी परती जमीन को हल के अन्दर लिया ? श्रीमन्, मैं उसके सम्बन्ध में आंकड़े इस सदन के सामने रखना चाहता हूं जो यह बतलाते हैं कि खेती के क्षेत्रफल में कितना विकास हुआ है । खेती का क्षेत्रफल सन् १९५६–५७ में ४०२.९ लाख एकड़ और सन् १९५७–५८ में ४००.४ लाख एकड़ है । पहले साल ज्यादा था, लेकिन दूसरे साल जाकर वह क्षेत्रफल कम हो गया । जो खेती के अन्दर जमीन थी उसमें भी कमी आ गई ।

इस प्लान के लिये जो हम इतनी बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं उससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ है । इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हमको क्या मिला है । सोशलिस्ट पार्टी बराबर बेकारों की समस्या की बात को यहां पर उठाती रही है । हमने सरकार से यह जानना चाहा है कि भीख मांगने वालों की संख्या और बेकारों की संख्या हमारे प्रदेश में कितनी है जो रात में सड़कों पर सोते रहते हैं और चौराहे पर बैठ कर भीख मांगते हैं । इसके आंकड़े सरकार के पास होने चाहिये । मैं चीन की पुस्तक पढ़ रहा था जिससे मालूम हुआ कि चीन की सरकार ने जो वहां पर लूटमार करते थे, आवारा थे उनका सेन्सस कराया और उनके लिये नाइट स्कूल खोलकर उनको पढ़ाया और फिर उनको उद्योगधन्धों में लगाया । अगर हमारी सरकार कर सकती है तो उसको भी इनके लिये कोई प्रबन्ध करना चाहिये जिससे यहां की बेकारी समाप्त हो । मगर हमारी सरकार के पास ऐसे आदमियों का कोई आंकड़ा नहीं है । प्लानिंग विभाग बहुत बड़ी सेवा जनता की करता अगर वह अपने ब्लाक के जरिये से इन आंकड़ों को इकट्ठा कर लेता ।

[श्री उग्रसेन]

हमारा एक विभाग इम्प्लायमेंट एक्सचेंज का है जो नाम रजिस्टर्ड करके नौकरी दिलाने का काम करता है । मगर इस दफ्तर ने बेकारों को बढ़ाया ही है कम नहीं किया है । अगर उसके आंकड़े देखे जायं तो कई लाख नाम रजिस्टर्ड किये हैं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार १९५५-५६ में ३,२१,९७७, १९५६-५७ में ३,३६,४४० और १९५७-५८ में ३,४३,६६३ रजिस्टर्ड थे । मगर इस बात के आंकड़े कोई भी प्राप्त नहीं हैं कि जब इतने लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराये तो फिर कितने लोगों को काम मिला । एम० ए० और बी० ए० को तो काम नहीं मिला, लेकिन जो टेक्निकल लोग थे उनमें कितने को काम मिला इसका कोई फिगर इसमें नहीं है । सरकार तो यही समझती है कि उनका नाम उनके यहां लिस्ट में दर्ज हो जाता है और उनका काम पूरा हो जाता है । तो रोजगार दफ्तर में क्यों इतने बेकार हैं ? माना इतने बेकार हैं तो साल में इनमें से कितनों को काम मिला इसके भी कोई आंकड़े नहीं हैं । सरकार ने वादा किया था कि देश में और प्रदेश में पंचवर्षीय योजना के लागू होने पर लाखों आदमियों को काम मिलेगा । १० लाख आदमियों को काम मिलने वाला था और २० लाख से ज्यादा बेकार हो गये । दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने यह कहा था कि हम पुराने बेकारों को काम दे सकते हैं, लेकिन आगे की बेकारी को रोक नहीं सकते । तो इन योजनाओं का मतलब क्या है ?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि हम पहली और दूसरी योजना में इस बात का ध्यान नहीं रख सके कि वह जनता का प्लान हो । अब सरकार करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद यह कहने जा रही है कि हम पिपुल्स प्लान चलायेंगे । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक बलवंत राय मेहता कमेटी बैठायी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने लिखा है कि यह जो सरकार का नियोजन हुआ है उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन नहीं है । इसमें जनता की कोई सहायता नहीं है, जनता ने इसमें भाग नहीं लिया है । मैं उदाहरण के लिये कहना चाहता हूं कि एक खाद का गड्ढा बनाया जाता है देहात में, बी० एल० डब्लू० बनवाता है गांव में । लेकिन पंचायत का सेक्रेटरी उसको नोट कर लेता है, कृषि का कामदार उसे नोट कर लेता है, प्रान्तीय रक्षक दल उसे नोट कर लेता है और कानूनगो साहब अगर रिपोर्ट मांगते हैं तो लेखपाल भी उसी को नोट करके दे देता है और किसी प्रश्न के उत्तर में हमारे राजस्व मंत्री उसका जिक्र यहां कर देते हैं । तो आप देखें कि एक खाद का गड्ढा कितनी जगह नोट होकर चला जाता है । वन महोत्सव हमारे गवर्नर साहब किया करते थे । इसमें दिया हुआ है कि वन महोत्सव के लिये इतना रुपया विकास में खर्च किया गया । लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन क्या विकास अफसरों के पास इसके आंकड़े हैं कि जितने पेड़ लगाये गये हैं उनमें से सरवाइवल कितनों का हुआ, कितने पेड़ उनमें से मर गये, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है । प्लानिंग कमेटी में एक सवाल उठा था तो ब्लाक डेवलपमेंट अफसर ने बड़े तैश से कहा कि हम पेड़ लगाते हैं और उनकी रखवाली किया करते हैं, लेकिन सर्वाइवल की कोई रिपोर्ट नहीं है । जब तक जनता उत्साहपूर्वक इस विकास के कार्य में भाग नहीं लेगी और जनता को अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक देश और प्रदेश का कोई विकास नहीं होने वाला है ।

एक बात उस कमेटी ने और अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि जितने विकास के विभाग हैं कोआपरेशन का, एग्रीकल्चर का और दूसरे जो विभाग हैं, उनमें आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है । जब तक इन विभागों में समन्वय नहीं होगा, विकास का काम ठीक से नहीं चल सकता, पूर्ण नहीं हो सकता । मैं जानना चाहता हूं कि इस पीपुल्स प्लान के द्वारा क्या उनमें कोआर्डिनेशन हुआ ? सिफारिश की गयी डेवलपमेंट कमिश्नर्स कांफ्रेंस में कि पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, बी० एल० डब्लू० और सीड गोदाम का सुपरवाइजर इन सब के लिये एक ही आदमी रहे और उसको काफी अधिकार दिये जायं ताकि हमारा यह प्लान जो नीचे से चल रहा है उसमें प्रगति हो सके । डेवलपमेंट कमिश्नर्स कांफ्रेंस की इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । क्यों ?

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया कि जैसा कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब आगे जनता का प्लान बनाने

के लिये गांवों में कमेटी बनायी जायगी । श्रीमन्, इस संबंध में मैं उस कमेटी की रिपोर्ट की दो लाइनें आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"In order to achieve best results, and implement agricultural development programme successfully, it is necessary to have a working plan for each village in a Block".

हर गांव में हमारा यह नियोजन सफलतापूर्वक आगे चल सके इसके लिये एक वर्किंग प्लान होना चाहिये यह सिफारिश बलवन्तराय मेहता कमेटी ने की । हमारा प्लान बन रहा है ठीक ही होगा । इस कमेटी की रिपोर्ट निकले काफी दिन हुए, पर अभी तक हमारा कोई एग्रीकल्चर प्लान नहीं है । मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि गांव पंचायत को, जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी बराबर कहती है, क्या अधिकार दिये गये ? राजस्व का चौथायी हिस्सा उनको दिया जाय, पुलिस उनकी अपनी हो, राजस्व की वसूली के अधिकार उनको दिये जायं। जब तक उनको ये अधिकार नहीं दिये जायंगे, वे सबल और स्वच्छ नहीं बनायी जायंगी, तब तक यह जो हमारा एग्रीकल्चर प्लान बनने वाला है यह सफल नहीं होगा । इस सिलसिले में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्रीमन्, एक चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं की, लेकिन इस बजट में प्रान्तीय रक्षक दल की बात है । पहले पी० आर० डी० पर १८,८६,००० रुपये खर्च किये जाने की व्यवस्था थी, लेकिन इस साल वह बढ़ाकर २१,०१,००० रुपये कर दिया गया है । इसने १९५५–५६ में २५१ मील नालियों की मरम्मत की और १९५६–५७ में ५७ मील नालियों की मरम्मत हुई । बजट में रुपया १८ लाख से बढ़ कर २१ लाख हो गया, लेकिन काम यह हुआ । पी० आर० डी० ने १९५५–५६ में ६१६ कुएं बनवाये जो १९५६–५७ में घट कर ३५१ रह गये और १९५७–५८ में उनकी तादाद ११२ हो गयी । तालाब मरम्मत हुए १९५५–५६ में १,४३१ जो १९५६–५७ में २२४ रह गये । खाद के गड्ढे १९५५–५६ में ३०,४४३ बने, १९५६–५७ में हो गये ५२३ ।

खेलों का जिक्र किया गया है, माननीय मंत्री जी ने कहा । १९५६–५७ में ४,००६ दंगल कराये गये जिनमें केवल ८३७ पहलवानों ने भाग लिया, लेकिन १९५५–५६ में जब ३,१२७ दंगल कराये गये तो उनमें १,२६,१६९ पहलवानों ने भाग लिया । यह आंकड़े हैं और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि खेलों का प्रचार बहुत किया जाता है । क्रिकेट का बड़ा प्रचार हुआ, लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि क्रिकेट आलेम्पिक का कोई खेल नहीं है । यह नेटिव लोगों को सिखाया गया था १०, डाउनिंग स्ट्रीट के जरिये से । कामनवेल्थ ने सिखाया था । एक उसमें महाराजा विजयनगरम है और एक दो आदमी और हैं, लेकिन जब वेस्ट इंडीज की टीम आयी तो उसके सामने साफ हो गये । कहीं पता नहीं लगा । आप देखिये कि हाकी की क्या हालत है । हर जगह राजनीति चल रही है । उसमें भी पर्सनल राजनीति का बोल-बाला है । व्यक्तिवाद, भाई-भतीजावाद उसमें भरा हुआ है और यह भी है कि बड़े-बड़े हाई आफिशियल्स के लड़के, भतीजे जो यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते हैं वही डेलीगेशनों में चले जाते हैं और वास्तविक खिलाड़ियों को मौका ही नहीं मिलता । एक बार हाथीसिंह साहब तेनसरोवैली स्कीम पढ़ने न्यूयार्क गये तो लौटने पर बताया कि वहां की स्त्रियां साड़ी किस प्रकार की पहनती हैं:

संस्कृति का माननीय मंत्री जी ने बहुत जिक्र किया । मैं मानता हूं कि काशी संस्कृति का केन्द्र है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो लोकगीत हैं, जो देहातों का स्टेज है उसमें हमारे भारत की आत्मा बसती है । वहां कोई विकास नहीं हुआ है । देहात के वह बंजारे जो कठपुतली का नाच करते हैं उनको कितना अनुदान दिया गया है ? होली तथा दूसरे अवसरों पर, जो त्योहारों आदि पर नाच होते हैं देहातों में उनके विकास के लिये कितना अनुदान दिया गया है?

[श्री उग्रसेन]

स्कूलों में कार्यक्रम बनाये जाते हैं और ब्लाक डेवलपमेंट पार्टियां नाटक खेलती हैं। उनके लिये पर्दे दिये जाते हैं, लेकिन जब ब्लाक टूट जाता है तो पर्दे वहीं पड़े सड़ा करते हैं। जब दूसरा नया ब्लाक खुलता है वहां दूसरे पर्दे भेजे जाते हैं। बड़ा सुझाव दिया गया कि उन्हीं पर्दों को काम में लाया जाय, आपके आडीटर ने भी यही सुझाव दिया, लेकिन नहीं वे पर्दे वहीं सड़ते रहते हैं। रूस में, ब्रह्मा में तमाम तरह के डांसिंग स्कूल्स हैं। हमारे यहां भी हैं, लेकिन उनमें इस प्रकार का कोई खास प्रयास नहीं होता कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को ऊंचा उठाना है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अपने यहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम को विकसित कीजिये ताकि आपके गांव के लोगों को ऊपर उठने का मौका मिले। इसलिये अगर आपको अपने देश और प्रदेश को ऊंचा उठाना है तो वह केवल इन कागजी नक्शों से ऊंचा नहीं हो सकता है, उसके लिये आपको रचनात्मक कार्य करने होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

योजना की फिजूलखर्ची व भ्रष्टाचार।

श्री प्रताप सिंह — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

नियोजन में प्राथमिकता के सिद्धांत (Principle of priority) का पालन न होना।

श्री हरिदत्त कान्डपाल — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

अल्मोड़े जिले में (Co-ordination) एकीकरण की नीति (वर्तमान) की असफलता की चर्चा तथा सुझाव।

श्री रामस्वरूप वर्मा — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

वर्तमान योजना खर्चीली, अपव्ययपूर्ण व गरीबी, बेकारी मिटाने व विकास करने में असमर्थ।

श्री रामकुमार वैद्य तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी। — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

योजना की धीमीगति तथा सहयोग का अभाव।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

टेहरी-गढ़वाल में स्वावलम्बी बनाने की योजनाओं की अपर्याप्तता ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार के अपर्याप्त प्रयास ।

श्री झारखंडे राय तथा
श्री चन्द्रजीत यादव

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में बनने वाली इमारतों पर अनावश्यक रूप से अधिक रुपया खर्च होता है ।]

श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है वह अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इसके अन्दर जितने भी काम हुए हैं उनमें बहुत ही सफलता मिली है। हरिजनों के पानी पीने के लिये बहुत से स्थानों पर कुएं नहीं थे, शिक्षा के लिये पाठशालायें नहीं थीं, रोगियों के लिये अस्पताल नहीं थे, ये सारी चीजें बनवायी गयीं। कृषि के लिये नये-नये औजार, नये-नये खेती के तरीके और अच्छे बीज, कहने का मतलब यह है कि इन सब बातों में हमें काफी सफलता मिली है। यह बात अवश्य है कि जितनी मात्रा में सफलता मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिली। जो कुछ कमियां रही हैं मैं चाहता हूं उनको सदन को बता दूं और अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनको मुख्य मंत्री जी के सामने रख देना चाहता हूं । उसका कारण यह है कि यह कह कर कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है या उन कमियों का यहां पता ही नहीं था इस सदन के माननीय सदस्य बरी नहीं हो सकते। आगे जो संतानें आयेंगी या २, १ बरस के बाद, अगर हमारी ये स्कीम्स फेल हो गयीं तो हमारा भी अन्त होगा और हमारे ऊपर कलंक वे लगायेंगी, इसलिये मैं उचित समझता हूं कि उन कमियों को यहां पर बता दूं ।

जिला स्तर पर जो आपने राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खोले हैं, उनमें जो कर्मचारी भेजे हैं उनका रचनात्मक कार्यक्रम से, कृषि से या देहात से कोई संपर्क नहीं रहा। यही कारण है कि केवल नौकरी के बहाने, ऐश आराम के लिये, वे वहां जाते हैं और इसीलिये आप के काम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते या बहुत से लापरवाह लोग वहां पर भेजे गये हैं, इसलिये आपके रुपये का ठीक उपयोग नहीं हो पाया है। कुछ ऐसे कर्मचारी भी गये हैं जिन्होंने अपने काम को

[] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं किये गये परन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रस्तुत किये गये माने गये ।

[श्री शिवराजबली सिंह]

लगन के साथ किया है और जो कुछ हमें सफलता दिखाई दे रही है वह उन्हीं के प्रयास के कारण दिखायी दे रही है। इसके साथ ही साथ अधिकतर उसमें जनता का प्रयत्न है। दूसरी सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि जब हमारी सरकार ने इस बात का विचार किया कि झोपड़ियों में, गांवों में ऐसी योजनाओं को फैलाया जाय ताकि गरीबों का स्तर ऊंचा हो, उनके खाने के लिये अन्न, पहनने के लिये कपड़े तथा उनकी शिक्षा और औषधि आदि का भी इन्तजाम हो। लेकिन जहां तक मैंने देखा और समझा है, जहां आप समझते हैं कि किसान बे पढ़े लिखे हैं और वे वाउचर और एस्टीमेट का नाम नहीं जानते थे, वहां अब वे ऐसे नाम काफी जानने लगे हैं। लेकिन चूंकि वे गरीब और असहाय हैं और उनमें ताकत नहीं है तो फर्क यह पड़ता है कि एस्टीमेट वे अपने काम का बनाते हैं और वाउचर ब्लाक का जब जिले के स्तर पर पहुंचता है तो पचासों बार उसे वापस आना पड़ता है। यह कह दिया जाता है कि गलत है। मैं समझता हूं कि जहाँ कर्मचारियों का इतना अखाड़ा है और फिर उनकी जिम्मेदारी है कि एक बार, दो बार इस तरह की जो गलतियां हैं उनको बतलावें और उनका सुधार किया जाय।

(इस समय १२ बजकर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए।)

दूसरी बात यह है कि काम काफी हुआ और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन महीनों ही नहीं बल्कि सालों दौड़ने पर भी उनको पैसे नहीं मिले। यह कह कर उनको वापस कर दिया जाता है कि वाउचर ठीक नहीं है।

तीसरी बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आगे चल कर सरकार को करोड़ों नहीं अरबों रुपये इस योजना में खर्च करने हैं इसलिये जो पिछली गलतियां हैं उनका सुधार होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सम्भव है कर्मचारियों के दिलो-दिमाग से गवर्नमेंट के रुपये का सदुपयोग ठीक से न हो। तो मैं कहता हूं कि पंचवर्षीय योजना के कार्य के लिये जो रुपये भेजे गये उसकी जांच-पड़ताल की जाती तो अच्छा था। अगर यह समझा जाय कि पूरे सूबे का प्रश्न तो बहुत कठिन है तो कुछ जिलों को ही ले लिया जाय और उनमें मेरा जिला फतेहपुर का अवश्य लिया जाय। यदि आप समझते हैं कि अनुदान कुछ ऐसे लोगों को दिया गया जो काम नहीं कर सकते या रुपया उनका खर्च हो गया तो यदि उचित समझा जाय तो सरकार की तरफ से बताया जाय कि वह क्या चाहती है, लेकिन हिसाब साफ हो। यह नहीं होना चाहिये कि गड़बड़ी सड़बड़ी में हिसाब पड़ा रहे। क्योंकि मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि बहुत से अनुदान ऐसे हैं जो दो-चार, छः वर्ष से पड़े हुए हैं और मौके पर काम नहीं हुआ है, बहुत से अनुदान ऐसे हैं उनका वाउचर आ चुका है और मौके पर काम नहीं हुआ है या अध बना पड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह चीज देखने सुनने लायक है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो विभाग है, बड़े गर्व की बात यह है कि, इसमें बहुत काफी स्नेह और संगठन है क्योंकि जितने दूसरे विभाग हैं उनकी जब रिपोर्ट निकलती है तो उसमें यह देखने को मिलता है कि इतने आदमी मुअत्तल हुए या इतने बर्खास्त किये गये। लेकिन इस विभाग में ऐसा प्रतीत होता है कि आपस में एक दूसरे की गलती को छिपाने की कोशिश की जाती है। इसलिये मेरी यह उचित राय है कि इसको देखा सुना जाय और ताड़ना दी जाय तथा उचित कार्यवाही की जाय।

आगे चल कर मैं बतलाऊं कि इस विभाग में बहुत अच्छे से अच्छे सरकारी कर्मचारी हैं जैसे विकास आयुक्त, हमारे डाइरेक्टर, पंचायतराज आफिसर और कमिश्नर लोग भी दौरा करते हैं और मौके पर जाते हैं और काम को खूब देखते हैं। वहां पर जो आम जनता रहती है उनके द्वारा उनकी सेवा-शुश्रूषा भी खूब होती है। होनी भी चाहिये क्योंकि यह तो हमारी प्राचीन संस्कृति है। यह बहुत गलत चीज है कि आपके यहां कोई आ जाय तो उसकी उचित खातिर न हो। लेकिन वह अपने दृष्टिकोण से जाते हैं। मेरी उचित राय है जिसको मैं आपके सामने रखता हूं कि जब हमारे अधिकारी जाते हैं तो पहली बात तो यह है, मैं समझता हूं सम्भव

है हर जिले का यह प्रश्न होगा कि कुछ चीजें या कुछ इमारतें ऐसी बना दी जाती हैं कि जिले में जहां पर सरकारी अधिकारी पहुंचा तो जिले के अधिकारी उन्हीं जगहों को दिखाते हैं और वे चुपचाप देख करके वापस आ जाते हैं। तरीका क्या होता है कि जिले के सारे कर्मचारी इस तरह से उस अधिकारी को घेर लेते हैं कि सिर्फ सामने भर को वह देख सकते हैं अगल बगल कुछ नहीं देख सकते, फर्क इतना होता है कि कैदी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, लेकिन इनको जिले के अधिकारी इस तरह से घेरे रहते हैं कि अगल बगल को कुछ नहीं देख सकते, जनता की तरफ एक इंच भी नहीं देख सकते। साहब आ रहे हैं सामने से हटो यह जनता से कहा जाता है। तो यह तरीका छोड़ दिया जाय। मैं चाहता हूं जब यह लोग जायं तो ब्लाक में मीटिंग बुलायें, जिला स्तर पर मीटिंग बुलायें और प्रधानों को अवसर दें, उनसे मिलें ताकि वहां की शिकायतें उनको मालूम हों। अगर ऐसा करेंगे तो जिला अधिकारी यह समझेंगे कि ऐसा न हो हमारी शिकायत हो इससे काम ज्यादा अच्छा होगा।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुन करके। एक तो यह है कि हमारे धर्म-शास्त्रों में नाच और गाने का कोई प्रमुख स्थान नहीं है। दूसरे यह भी है कि जो लोग हिन्दू संस्कृति को मानते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं वे इस बात को जरूर मानते हैं कि हमारा आदर्श जो है वह "स्मरणं कीर्त्तनम् केलिप्रेक्षणम् गुह्य भाषणम्।" हमारी संस्कृति यह है कि अगर लड़कियों का स्कूल है तो उसमें ४ साल का लड़का न जाने पाये और अगर लड़का का स्कूल है तो उसमें ४ साल की लड़की न जाने पाये। इसके अलावा संस्कृति में नाचने और गाने का अधिकार, अगर कभी होगा तो किसी त्योहार के मौके पर होगा, और वह भी उन्हीं को जो विद्या न पढ़ सकें, शस्त्र न चला सकें, वाणिज्य न कर सकें "शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणो याति शूद्रताम्"। भगवान कृष्ण का कभी नाचने वाले का रूप नहीं है, वह सुदर्शन चक्रधारी का रूप है, वह धर्म की रक्षा करने वाले का रूप है। भगवान कृष्ण का रूप नयनानन्द गोविन्द माधव मुकुन्द आनन्द कन्द केशव, सुदर्शन चक्रधारी का रूप है। नाचने गाने वाले का नहीं है। दूसरे जिस देश के अन्दर भुखमरी हो, जहां हजारों आदमी अभाव के कारण आत्म-हत्या करके मरते हों उस देश के अन्दर नाचने गाने को किसी तरह से भी प्रोत्साहित करना बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। माघ कवि ने कहा है---"बुभुक्षितैः व्याकरणं न भुज्यते पिपासितैः काव्य रसो न पीयते"। जिस देश में हजारों भूख से परेशान हों वे आज की इस काव्य और कला को जिसे हम अश्लीलता कहते हैं समझ नहीं सकते। बेशक हमारे यहां गाने का स्थान है। लेकिन अथर्ववेद के गान का स्थान है। कुलटाओं के गाने के लिये कोई स्थान नहीं। भगवान ने गीता में कहा है "मद्भक्तः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद"। लेकिन कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर जो कंचन प्रोग्राम चल रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पर जो दुःसांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं इनसे राष्ट्र का चरित्र गिरता जा रहा है। एक ओर भुखमरी से हजारों लोग त्राहिमाम् कर रहे हैं और दूसरी ओर कंचन प्रोग्राम के ऊपर हजारों रुपया बरबाद किया जा रहा है। आज हालत यह है। शेख सादी के लफ्जों में "चुना कहत साले कि अन्दर दमिश्क, कि यारां फरामोश करदन्त इश्क"। अगर कोई भी जिम्मेदार शख्स नाचने और गाने की तारीफ करता है तो देश की भुखमरी को बढ़ाता है और उसके चरित्र को गिराने की कोशिश करता है। जिससे यहां के पढ़े लिखे का चरित्र गिरे। नृत्य शब्द से पहले लोक शब्द का जोड़ना जाहिर करता है कि कुछेक आदर्श-भ्रष्ट लोग सारी जनता को इस पाप का भागी बनाना चाहते हैं। श्रीमन्, गीदड़ को अपनी बिरादरी बढ़ाने का शौक होता है। नाचने वालों को भी बिरादरी बढ़ाने का जोश है। आज देश भूखा है, कंगाल है। देश के अन्दर अभाव की, आग की ज्वाला है।

[श्री यशपाल सिंह]

मेरी प्रार्थना है कि जो कल्चरल प्रोग्राम है, जिसे मैं कंचन प्रोग्राम कहता हूं, उस पर रोक लगाई जाय और व्यायाम सेन्टर खोलकर, ब्रह्मचर्य संस्थान खोलकर इस देश का निर्माण किया जाय । आज देश के निर्माण की जरूरत है । आज गाने से और नाचने से देश नहीं बन सकता । यह राज्य है । "कसीदे से न चलता है न ये दोहे से चलता है, समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है ।" आज मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत है, व्यायाम की शिक्षा की जरूरत है । मैं जिन सिद्धान्तों को मानता हूं, जिनमें विश्वास करता हूं उनकी नित्य प्रति बिला नागा फरफारमेंस करता हूं, जैसे शीर्षासन है, व्यायाम है । लेकिन जो माननीय मंत्री जी नाचने और गाने को मानते हैं वह मुझको कभी नाचते और गाते नहीं दीखते हैं । मैं प्राणायाम का हामी हूं, उसे करता हूं । मैं शिकार का हामी हूं, शेर का शिकार खेलता हूं । लेकिन जो मंत्री जी नाचने और गाने के हामी हैं वह हमको नाचते गाते नहीं दिखते । यह जरूरी नहीं कि इस तरह के अश्लील गाने को रक्खें । वेदों में इस तरह की कोई आज्ञा नहीं है कि लोग नाचें या तमाशा देखें या गाने गाएं । वैसे ही देश पतन की ओर जा रहा है । जब हमारे कर्णधार नाचने-गाने की तारीफ करते हैं, तो हजारों नौजवान इसीलिये नाचने-गाने आ जाते हैं कि मंत्री जी खुश होंगे । "महाजनो येन गतः स पन्था" । क्योंकि जिस मार्ग से महापुरुष चलते हैं लोग उसे ही अपना रास्ता समझते हैं । देश के लिये चरित्र की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, स्वास्थ्य निर्माण की आवश्यकता है । इस तरह से लोगों को पतन की ओर तो आसानी से ले जाया जा सकता है । हजारों आदमी होली में शराब पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं । आज जरूरत है कि उन्हें पतन की ओर जाने से रोका जाय । पतन की ओर ले जाना आसान है । जाति का उत्थान कठिन है । "नशा पिलाके गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी" । जरूरत यह है कि सरकार आज्ञा दे कि होली के मौके पर कोई शराब नहीं पिएगा, अश्लील गाने नहीं गाएगा । मैं प्रार्थना करता हूं कि देश आज निर्माण चाहता है । देश के निर्माण में आज मिलिट्री ट्रेनिंग की आवश्यकता है । स्वास्थ्य के निर्माण की आवश्यकता है । हमारा देश भूखा है, नंगा है । इसमें सख्त कदम उठा कर नाच और गाने को रोका जाय, और खास तौर से पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिये रोका जाय । यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है ।

मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं, मैं विद्वान तो नहीं हूं लेकिन विद्वानों के चरणों में बैठा अवश्य हूं । मैं ने उनकी २०-२२ साल सेवा की है और मैं कह सकता हूं कि चारों वेदों के २४,००० से अधिक मंत्री में कहीं भी गाने और बजाने की आज्ञा नहीं है । हम ने पढ़ा है कि सीतामाता को कभी उनके कपड़ों में भी नंगा नहीं देखा गया । आज जब नौजवान लड़के और लड़कियां इकट्ठा नाचते जाते हैं तो महात्मा गांधी की आत्मा धिक्कारती होगी, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और जिन का कहना था कि हमारा आदर्श बर्थ कंट्रोल नहीं है बल्कि सेल्फ कंट्रोल है । आज जो परिवार नियोजन का प्रचार किया जाता है यह परिवार नियोजन नहीं बल्कि व्यभिचार नियोजन है । हमारे यहां परिवार नियोजन आत्मसंयम द्वारा होता है । हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है कि मातापिता ने केवल एक पुत्र रत्न को जन्म देकर जीवन भर ब्रह्मचर्य का, सेल्फ कंट्रोल का, जीवन व्यतीत किया है । जिस आदर्श को मनीषी लोग मानते हैं वही प्रेक्टिकेबिल हो जाता है । आज इस प्रदेश के कर्णधारों का कर्तव्य है कि परिवार नियोजन की अनैतिकता को रोक कर प्रदेश के चरित्र का निर्माण करें और अश्लील नाच और गानों को कानूनन बन्द कर के नौजवानों को सैनिक शिक्षा दें । यही मार्ग कल्याण का मार्ग है ।

"नाऽन्यः पन्थाविद्यते, अयनाय ।"

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)––अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान संख्या ४५––योजना और एकीकरण––लेखा शीर्षक ६३-क व ६३-ख प्रस्तुत किया है मैं उस सम्पूर्ण अनुदान का विरोध करते हुए प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता––आप को कटौती प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, वह तो प्रस्तुत मान लिया जायगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी––मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और जो कुछ मैंने सुना उससे मैं काफी प्रभावित भी हुआ । बड़ी खुशी की बात है कि कुछ अनुभव की कमी और कुछ हम लोगों की जनरल कमियों के वाबजूद भी हम लोगों को जो नियोजन के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल हुई हैं वह काफी संतोषजनक हैं । बड़े संतोष की बात है कि जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इस बजट वर्ष में हमारे यहां ब्लाकों की संख्या ५६ और बढ़ा दी जायगी ताकि इस बजट वर्ष के अन्त तक लगभग ५२.६ प्रतिशत गांवों में और उन गांवों में रहने वाले लगभग ५३.४ जन-संख्या में यह राष्ट्रीय प्रसार सेवायें या सामुदायिक विकास कार्य-क्रम लागू हो जायगा । यह सब चीजें बड़ी अच्छी हैं और जब मैंने यह बातें सुनी या देखी तो मुझे याद आई श्री चेस्टर बावेल्स की जो पहले अमेरीकन राजदूत यहां रह चुके हैं । जब यह काम यहां शुरू हुआ था तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा था कि भारत एक ऐसे प्रगतिशील अध्याय में प्रवेश कर रहा है कि जिससे कुछ ही वर्षों में भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक नया इन्कलाब पैदा होगा । हमारे देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा है कि हमारा उदीयमान भारत क्या होगा उसका प्रतिबिम्ब आज हम अपने ब्लाक्स में देख रहे हैं । हम एक नया उगता हुआ भारत देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भावी भारत के तीन प्रमुख स्तम्भ होंगे । उसमें एक स्तंभ होगा सहकारी समिति, एक होगी ग्राम पंचायत और एक होगा ग्रामीण स्कूल । ये सब बातें हैं और इनसे नवीन आशा आज पैदा होती है और नये काम करने और नयी जिन्दगी पैदा करने का उत्साह पैदा होता है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में क्या होता है ? मैं सोचता हूं कि इस पर माननीय गोविन्द सहाय जी और उनकी कमेटी जो रिपोर्ट करेगी उसी से कुछ अन्दाज होगा । मेरी व्यक्तिगत जानकारी इसमें बहुत कम है,क्योंकि मैं इस आदरणीय सदन का एक ऐसा अभागा सदस्य हूं जिसके इलाके में अभी तक एक भी ब्लाक नहीं खुल पाया है । इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि इससे मेरे इलाके का बहुत अहित हुआ है । खैर, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि अगर वह कुछ कर सकें तो देखें कि हमारे क्षेत्र के अन्दर (केदारनाथ क्षेत्र में) अगले कुछ महीनों के अन्दर एक या दो ब्लाक अवश्य खुलें ताकि हम भी देखें कि इन ब्लाकों के अन्दर होता क्या है ? जहां तक मेरी निजी जानकारी है, श्रीमन्, और अपने अन्य सहयोगियों के कथनों से, उनके अनुभवों से तथा अखबार और पत्र-पत्रिकाओं से तो यही मालूम होता है कि जो कुछ प्रसार सेवा खंडों के अन्दर हो रहा है वह बहुत आशाप्रद नहीं है । यही नहीं मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो कुछ इन खंडों में हो रहा है उससे क्योंमिंटांगी चाइना का इतिहास हमारे सामने आ जाता है । कहा जाता है कि क्योंमिंटांग चायना के मार्शल च्यांग काई शेक का सब से बड़ा अभिशाप यह था कि गृह युद्ध के लिये जो अमेरिकन बन्दूकें या लड़ाई का सामान अमेरिका मार्शल च्यांग काई शेक को दे रहा था वह किसी न किसी प्रकार कम्युनिस्टों के हाथ में पहुंच रहा था और जिसका उपयोग कम्युनिस्टों ने मार्शल च्यांग काई शेक की नेशनलिस्ट फौजों को खत्म करने के लिये किया । मैंने सुना है और कुछ अंशों में अनुभव भी किया है कि हमारे राष्ट्रीय सेवा खंडों के अन्दर या सामुदायिक विकास खंडों में जो रुपया जाता है वह या तो सरकारी अफसरों के यात्रा व्यय में खर्च होता है या प्रदर्शनों में, या ऐसी चीजों में जिनका हमारे जीवन

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमें किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देती। मुझे अफसोस है कि एक ओर कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी ओर उसका अपव्यय इस ढंग से हो रहा है जैसे कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम जितना चाहें खर्च कर सकते हैं।

यही नहीं, मुख्य मंत्री जी ने कहा और मैं उनकी इस बात का बड़ा आदर करता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि हमारे ग्रामीण जगत में ग्रामीण आंचल में भौतिक सम्पदा बढ़े। बहुत अच्छा है, भौतिक सम्पदा के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते, लेकिन भौतिक सम्पदा का रसास्वादन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि एक साधारण नागरिक को रोजगार न मिले। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि इस योजना के अन्दर, प्रथम या द्वितीय योजना के अन्दर, कौन सी चीज है जिससे लोगों का रोजगार बढ़े? कम से कम मुझे अपने क्षेत्र में कोई ऐसी चीज दिखलाई नहीं देती जिससे रोजी का कोई अवसर प्राप्त हो। यह संभव हो सकता था अगर हमने वहां के उद्योग-धंधों को जिन्दा करने की कोशिश की होती। कहा जाता है कि वहां उद्योग-धंधे शुरू तो कर सकते थे, लेकिन शक्ति का अभाव है और हम बिजली तब तक नहीं ला सकते जब तक फारेन एक्सचेंज की कमी रहेगी। आपके सामने हिमांचल प्रदेश का उदाहरण है जहां उन्होंने बिजली के अभाव को दूर किया है जल-शक्ति का प्रयोग करके। कुछ दिन पहले जब नेगी जी डिप्टी मिनिस्टर थे, प्लांनिग का एक क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, हम सभी लोग गये थे मैंने उस सम्मेलन में सुझाव दिया था कि हमारी प्रदेशीय सरकार हिमांचल प्रदेश में अपने विशेषज्ञों को भेजे। क्योंकि हिमांचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति वैसी ही है जैसी कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की है और देखें कि जल-शक्ति का जैसा उपयोग हिमांचल प्रदेश ने किया है जिससे नाना-प्रकार के छोटे कुटीर उद्योग उस प्रदेश में शुरू किये गये हैं वैसे ही हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भी शुरू किये जायं।

मैं आपका ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री नम्बूद्रीपाद के एक वक्तव्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं। उसकी कुछ रेलेवेन्स हमारे मामले में भी है। कुछ महीने पूर्व उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि मैं दिल्ली आकर परेशान हो गया क्योंकि मैं आया इस उद्देश्य से था कि केरल के उत्कर्ष के लिये भारत सरकार से कोई नया उद्योग खुलवायें। मैं उद्योग मंत्री से मिला, उन्होंने कहा कि हम आपके यहां उद्योग खोल सकते थे लेकिन परेशानी यह है कि आपके यहां कोई सड़क नहीं है। मैं रेल मंत्री से मिला उन्होंने कहा कि हम रेल जरूर निकाल सकते थे लेकिन बात यह है कि आपके यहां कोई उद्योग नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप का समय समाप्त हो गया।

***श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के संबंध में जो कटौती के प्रस्ताव हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। नियोजन का बहुत व्यापक विषय है। किसी भी देश अथवा परिवार में जब नियोजन की समस्या आती है तो उससे पहले यह मान लेना पड़ता है कि उस देश में सचमुच आर्थिक संकट है। दुनिया के मुल्कों में जहां-जहां प्लांनिग के सिलसिले में कार्य हुआ है वे सचमुच पिछड़े हुए थे। हमारे देश में प्लांनिग का कार्य कई वर्षों से चल रहा है। जो देश धनाड्य है, जैसे अमरीका वहां पर नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जैसे देश में जहां हजारों वर्षों के बाद हमने स्वाधीनता को प्राप्त किया उसके बाद हम भी उन मुल्कों की तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकें, स्वतंत्रता के बाद जो सही सुख होता है, समानता, सम्पन्नता, उसको हम प्राप्त कर सकें, दुनिया के सामने अपना भी स्टेट्स वही रख सकें जो दूसरे खुशहाल देश रखते हैं इसके लिये नियोजन की बड़ी आवश्यकता है। जहां तक कागजी कार्य का संबंध है उसमें अपने देश में नियोजन में मैं कोई कमी नहीं पाता हूं। यों तो भारत का नियोजन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुन्दर है परन्तु विकास कितना हुआ है, देश कितना आगे बढ़ा है, आज से ८–१० वर्ष पहले जो देश की स्थिति थी उससे आज क्या फर्क आया है, इसको देखने से पता चलेगा कि सचमुच क्या काम हुआ है क्योंकि नियोजन का उद्देश्य होता है देश की गरीबी, भुखमरी, बेकारी आदि जो भी समस्यायें हों उन सब का हल हो सके। तो जब नियोजन को चलते हुए वर्षों गुजर जायं और देश की किसी भी समस्या का हल न हो सके तो एक बात समझ में नहीं आती है कि अब तक अरबों रुपया देश में और करोड़ों रुपया प्रदेश में जो व्यय हो चुका है उससे क्या बुनियादी परिवर्तन हमारे समाज को मिला है ?

नियोजन ही ऐसा विभाग है जो सारे विभागों में नया जीवन डालने वाला है और नया परिवर्तन लाने वाला है। इसी नियोजन के द्वारा हम प्रदेश की काया पलट करना चाहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज नियोजन इतने वर्षों से हमारे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं उसको कितने वर्ष हो गये तो उन्होंने क्या खास बात करके दिखाई ? हमारे प्रदेश में बेकारी बढ़ रही है। हमारे भाई उग्रसेन जी ने बतलाया कि गरीबी और बेकारी बढ़ी है। मैं एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा हूं। मेले होते हैं देहातों में। अक्सर आप लोग गये होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बिक्री की चीजें आती हैं उनकी बिक्री घटती जाती है। इसका कारण स्पष्ट है कि किसानों की पर्चेजिंग कैपेसिटी गिरती जाती है। जितनी वस्तुयें किसान और मजदूर अपनी आवश्यकताओं के लिये खरीदता था उसमें अब वह कमी करता चला जा रहा है और उसमें जब कमी होती जाती है तो ऐशो-आराम की चीजों के लिये पैसा कहां से आवे ? इससे पता चलता है कि किसानों की आमदनी गिरती जाती है।

मजदूर उद्योगों में काम करता है। उसकी भी आमदनी गिरती जाती है। वह कपड़ा बनाता है और-और वस्तुयें जो मनुष्य के जीवन के लिये आवश्यक है उन्हें पैदा करता है और किसान हमारे भोजन की वस्तुयें ८ घंटे हल चलाकर पैदा करता है। किसान और मजदूर हमारी समाज रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। अगर इनकी आमदनी में परिवर्तन हुआ है तब हम कह सकते हैं कि हमारे देश और प्रदेश का नियोजन सफल हुआ है। अगर हमें किसी देश की माली हालत को देखना हो तो इन वर्गों की ही हालत को देखा जाता है। यही कारण है कि आज जितने भी दल हैं सब इन्हीं का नारा लगाते हैं। आज किसान, मजदूरों की, व्यापारियों की, रिक्शा चलाने वालों की हालत क्या है ? उनकी हालत आज गिरती जा रही है। हम इस नतीजे पर इस बात से पहुंचते हैं कि सरकार ने जो योजनायें हमारे देश और प्रदेश में लागू की हैं उन पर खर्च तो बहुत ज्यादा है लेकिन लाभ उतना नहीं है।

वह खर्च भी कहां से पूरा होता है। सरकार ने अल्प बचत योजना के नाम से एक फंड बना रखा है। रेवेन्यूज से पैसा आता है। दूसरे देशों और केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलती है वह सारा पैसा हम इसी देश और प्रदेश की योजनाओं पर व्यय करते हैं। लेकिन इन सब के होने के बावजूद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा नियोजन सफल क्यों नहीं हो रहा है। सफल इसलिये नहीं हो रहा है कि जो कुछ सरकार कहती है वह केवल कागज पर रह जाता है और कार्य रूप में नहीं आ पाता। अगर कथनी करनी में आ जाय तो इस देश और प्रदेश का उद्धार हो जाय। लेकिन गवर्नमेंट की कथनी केवल कागज पर पड़ी रहती है करनी में परिणत नहीं होती।

जन-सहयोग की हमारे यहां बड़ी शून्यता है। हमारे इसी सदन के एक माननीय सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है कि जन-सहयोग के लिये किस प्रकार प्रयत्न किया जाय ? उसमें क्या कमियां हैं जिसकी वजह से जन-सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, इसकी ओर हमें देखना चाहिये।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि नियोजन सम्बन्धी जो विदेशी नीति सरकार अपना रही है वह उचित नहीं है। वह अमीरों की संख्या बढ़ाना चाहती है और अमरीका की नकल करती है। मैं समझता हूं कि यह नकल गलत है। यह बात सही है कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद

[श्री हरदयाल सिंह]

और जवाहरलाल जी अगर नकल करेंगे तो वह अपने स्टेटस को बुलगानिन आदि की तरह बना सकते हैं, लेकिन किसान कुछ नहीं कर सकता है । नियोजन में जो सरकार ने नकल करने की ठानी है उससे हमारे देश का भला नहीं हो सकता है । हमारे देश का भला जब होगा जब हम देखें कि जो काम करने के लिये हम एक प्लान बनायें तो वह ऐसा हो जिसको देश की गरीब जनता समझ सके । आज गांवों में समितियां स्थापित करने के सिलसिले में जो योजना बताई कि ऐसे-ऐसे काम करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इन ९-१० वर्षों में जो कुछ भी प्लानिंग में काम हुआ है और जिन व्यक्तियों ने सहयोग दिया है तो उनमें वह लोग हैं जो सचमुच में समाज और देश का हित नहीं समझते हैं क्योंकि वह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ नहीं थे । वह लोग आज अपने मतलब से चाटुकारिता से, चापलूसी से उनके साथ हैं । इसीलिये आज हमारा प्लानिंग सफल नहीं हो रहा है क्यों कि किसान मजदूर आपके साथ नहीं हैं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मुख्य मंत्री जी ने सदन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं । श्रीमन्, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि देश की तथा राष्ट्र की उन्नति के लिये योजना बनाना परम आवश्यकीय है और बिना योजना के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं । पहली योजना समाप्त हो गई और दूसरी भी आधी हो चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो योजनायें जनता की भावना जाने बिना बनाई गईं उनसे जनता संतुष्ट नहीं है । इस पर हमें विचार करना है ।

श्रीमन्, पहली योजना में कृषि के ऊपर जोर दिया गया और ऐसा मालूम होता था कि हम उत्पादन के बढ़ जाने से खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे । लेकिन श्रीमन्, जहां यातायात के साधन नहीं है वहां के किसानों को आपकी योजनाओं की कुछ जानकारी नहीं है । वैसे तो सरकारी कर्मचारी और सूचना विभाग के लोग हू हल्ला तो बहुत मचाते हैं, लेकिन जहां यातायात के साधन नहीं हैं वहां के लोगों को सरकारी कामों की कुछ जानकारी नहीं हो पाती है । वे न अच्छा बीज ले सकते हैं और न खेती के अच्छे साधन जुटा सकते हैं । पैदल यात्रा में हमें लोगों ने बताया कि यातायात के साधन मुहैया किये जायं । यदि साधन हो जायं तो सरकारी कर्मचारी भी वहां पहुंच सकेंगे लेकिन जहां साधन नहीं हैं वहां वे नहीं पहुंच पाते हैं । यातायात के साधनों की जैसी दुर्दशा प्लानिंग में होती है उसका क्या वर्णन करूं । किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है । मिसाल के तौर पर मैं अपने इटावा जिले की एक सड़क का जिक्र करता हूं । हमारे भर्थना से ऊसराहार तक की १५ मील की सड़क है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जनता से यह कहा कि अगर इस सड़क की श्रमदान से भराई कर दी जाय तो यह पक्की बना दी जायगी । जनता ने उस १५ मील सड़क की कहीं-कहीं पर ५-५,६-६ फुट तक भराई की । बड़े उत्साह के साथ भराई करने के बाद कोई काम नहीं हुआ । प्लानिंग विभाग की तरफ से चार मील सड़क पक्की करने की कोशिश की गयी । चार मील सड़क पर ईंट का सोलिंग करके बिछवा दी गयी, लेकिन यातायात अधिक होने के कारण पांच, छः महीने के अन्दर वह भी टूट गयी । हजारों रुपया प्लानिंग का बरबाद हो गया । ईंट के टुकड़े बैलगाड़ियों और जानवरों के पैरों को तोड़ने लगे । जनता को चलना दूभर हो गया । मैंने जिलाधीश से कहा कि बजाय सुविधा के एक बड़ी दिक्कत पैदा कर दी गयी है । उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक कर दी जायगी । मैं तो सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि प्लानिंग के नाम पर जो काम होता है उसकी तरफ काफी तवज्जह देने की आवश्यकता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जनता की भावना को देखते हुये अगर कोई काम नहीं किया गया तो कामयाबी नहीं होगी । अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ब्लाक एडवाइजरी कमेटी की राय ली जायगी । फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की राय जो होगी । यह आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है । जब जनता की राय यहां पर आती है तो वहां पर अधिकारी जनता की राय की कदर नहीं करते । द्वितीय पंचवर्षीय योजना

के बनने के समय पी० डब्लू० डी० की तरफ से एक सेक्रेटरी साहब हर जिले में दौरा कर रहे थे। उन्होंने जिला प्लानिंग कमेटियों से राय ली कि आप कौन-कौन सा काम पहले चाहते हैं। वह राय लेकर यहां आये। लेकिन मुझे काफी दुःख हुआ कि उस पर कोई परवाह नहीं की गई। पी० डब्लू० डी० के जो बड़े सेक्रेटरी थे उनकी ही राय पर काम किया गया। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये जनता की राय की परम आवश्यकता है। जो योजना चल रही है उसमें सबसे प्रथम आवश्यकता यह है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाय।

जब तक हमारा देश खाद्य में आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं, लेकिन हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं इस पर विचार करना है। हम बाहर के देशों की नकल करके कामयाब नहीं हो सकते। आज हमारे विशेषज्ञ कुछ भी कहें, देश खाद्य में आत्म-निर्भर कैसे हो सकता है यह तो उन किसानों से जाकर पूछें जो काम करते हैं। मैंने देखा कि बड़े फार्म वालों से छोटे किसान ज्यादा पैदा करते हैं जिनके पास कम जमीन है। इसलिये जमीन की अधिकतम जोत की सीमा तय करना सबसे आवश्यक है। इसके साथ-साथ जिस तरह से पंडित जी कहते हैं सहकारिता से अन्न उत्पादन बढ़ायेंगे इसमें मुझे बड़ा शक पैदा होता है। इस तरह चाहिये तो यह कि काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। काश्तकार को आज जो सुविधायें दी जाती हैं वह पूरी उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। अभी जो हम देहातों में गये, काश्तकारों से जो हमारी बातें हुईं उनको सुनने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके कानों तक कोई चीज पहुंचती ही नहीं है। उन्नत बीज या खाद का प्रयोग वह नहीं करते हैं। वह तो वैसे ही जैसे कि पुराने जमाने से करते चले आये हैं उसी तरह काम करते हैं। तो इस बात की कोशिश की जाय कि देहात के अन्दर ज्यादा से ज्यादा बीज पहुंचे और किसानों को बतलाया जाय, उन्हें अच्छे बीज दिये जायं, यंत्र दिये जायं, नये साधन जुटायें जायं, जिससे वह उन उपायों को करके अपनी पैदावार बढ़ा सकें।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से फिर प्रार्थना करूंगा कि जनता की भावना को देखते हुये हमें प्लानिंग बनाना चाहिये। आज जो तीसरी पंच वर्षीय योजना बनने को है उसमें खासतौर से सरकार को इस बात की जरूरत है कि वह इस पर ध्यान दे। कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर हमारी कही हुई बातों पर अमल नहीं हुआ, हमने कह दिया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उससे कोई काम नहीं होगा। यही वजह है कि हम आज तक कारगर नहीं हो रहे हैं। अधिकारी जो चाहते हैं वही काम होता है। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मानित सदस्य के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिसका सम्बन्ध देश की तरक्की, देश के उत्थान से है। इसलिये इस प्रस्ताव की सबसे ज्यादा अहमियत है। देश की आजादी के बाद देश के रहने वालों के सामने सबसे मुख्य सवाल सबसे बड़ा काम देश के नव-निर्माण का है, देश को ऊंचा उठाने का है। मान्यवर, देश तभी ऊंचा उठ सकता है, नव-निर्माण तभी हो सकता है जब गांव का स्तर ऊंचा हो और गांवों के रहने वाले ८० प्रतिशत किसानों का स्तर ऊंचा हो. वह खुशहाल हों, उनके खाने के लिये रोटी मिले, पहनने के लिये मोटा-झोटा कपड़ा मिले और रहने के लिये बड़े-बड़े आलीशान मकान नहीं, चढ़ने उतरने के लिये लिफ्ट नहीं तो एक ऐसी झोपड़ी होनी चाहिये जिसमें वह और उसके बच्चे गुजर कर सकें। वह अपने बाल-बच्चों की शिक्षा और दवाई का प्रबंध कर सके। किसान जब तक भूखा और नंगा है और उसकी तरक्की जब तक नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं तो यह समझता हूं कि आज इस सरकार का मुंह शहरों की तरफ है। देहात की तरफ नहीं है। बड़े-बड़े संग्रहालय, बड़ी-बड़ी इमारतें, शहरों में बन रही हैं। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। मगर देहात के लिये कुछ नहीं किया जाता। मेरा सरकार को सुझाव है कि अगर सरकार बड़ी-बड़ी योजनायें देहात में चला सकती तो कम से कम जो यह बड़े-बड़े संग्रहालय और नाचने कूदने के स्थान बन रहे हैं उनको सरकार

[श्री कोतवालसिंह भदौरिया]

बन्द कर दे और सरकार के पास जितना रुपया, ईंट और सीमेंट है उसको वह गांवों में पटक दे जिससे कि किसानों के लिये कुयें बनवा दिये जायं और वह सिंचाई कर सकें।

दूसरी समस्या खाद की है। आज गोबर को किसान अपने ईंधन के काम में लाता है। मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसी लकड़ी का इन्तजाम करे जिससे कि ऊसर और बंजर में वह लकड़ी बोयी जाय और उसको ईंधन के रूप में किसान जला सके। गोबर को वह खाद के रूप में इस्तेमाल करे।

तीसरी बात यह है कि किसान को अच्छे बीज और अच्छे औजार देने चाहिये जिससे कि खेती की उन्नति हो। जब तक देश के अन्दर किसान की उन्नति नहीं होगी, किसान ऊपर नहीं उठेगा तब तक देश के उत्थान की बात करना खोखला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को उन योजनाओं को बनाकर के देहात की तरफ जाना चाहिये। शहरों में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं। देहात में कच्ची सड़कें नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि देहात में छोटी-छोटी सड़कें बनाई जायं और उनको बड़ी सड़कों से मिला दिया जाय। चौथी बात यह है कि ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० वगैरह जो किसानों में काम करते हैं उनकी वेशभूषा किसानों की तरह हो और उनका व्यवहार ऐसा हो कि किसान पर अच्छा असर पड़े। पांचवीं बात यह है कि ब्लाकों को जो कारें दी जाती हैं उनसे किसानों का कोई फायदा नहीं है। उनसे वह कारें ले ली जायं। उनका दुरुपयोग होता है। देहात में ग्राम सेवक और पंचायत सेक्रेटरी होते हैं उनमें से एक हटाया जाय। देहात के अन्दर जिन लोगों का स्तर गिरा है उनको ऊंचा किया जाय। गरीब किसानों और मजदूरों की समस्या को हल करने के लिये इस योजना के अन्दर खास स्थान होना चाहिये, पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी के आधार पर ब्लाक न होकर क्षेत्रों के आधार पर होने चाहिये। सीमान्त जिलों के लिये ८० हजार रुपया दिया गया था, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ है। सरकार से निवेदन है कि उस रुपये को खर्च किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)--अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह सन्तोष है और खुशी की बात जान पड़ती है कि नियोजन विभाग के प्रोग्राम में अन्य दायरों से हट कर फर्स्ट इम्फैसिस कृषि उत्पादन पर आगया है। इतिहास इस बात का साक्षी है, किसी भी सरकार तथा किसी भी इज्म के लिये विशेषकर अन्डर डेवलप्डकन्ट्रीज में कामयाब होने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक रहा है कि उस देश के अन्दर दौलत की पैदावार में बढ़ावा हो। हमारा देश और प्रदेश सदियों से एक कृषि प्रधान देश रहा है। इसलिये सब से सहज उपाय जो दौलत की पैदावार बढ़ाने का है वह कृषि की पैदावार बढ़ाना हो सकता है। आज अन्तर्राष्ट्रीय हालत को देखते हुये तो इस बात की आवश्यकता है कि किसी प्रदेश के और देश के तथा उसके नागरिकों के स्वतंत्र वक्तव्य के बढ़ावे के लिये खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जाय। इस दृष्टि से यह उचित है कि हमारे नियोजन के प्रोग्राम में फर्स्ट इम्फैसिस फिर लौटकर कृषि उत्पादन पर आगया है इन्हीं दृष्टिकोण से मैं तो इस हद तक चाहूंगा कि जो नियोजन के तहत में कार्य-क्रम हैं, इम्फैसिस इस समय सांस्कृतिक प्रोग्राम या सामाजिक एजूकेशन पर है वह इम्फैसिस घटाया जाय और अधिक इम्फैसिस कृषि के उत्पादन पर दिया जाय। श्रीमन्, नियोजन के तहत में कृषि प्रोग्राम जो गत वर्ष चालू रहा और इस वर्ष भी चालू रहेगा उससे संबंधित जो सवालात मुझे परेशान करते रहे वह मैं बड़े अदब से इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। गत वर्ष जब हमने बजट पास किया था यह निश्चय किया था कि नये बीज गोदाम खोले जावेंगे। महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में स्वीकार किया था कि इस प्रदेश में रबी की पैदावार १६.६ परसेंट कम पैदा हुई। इन कारणों से तो जरूर प्रदेश के अन्दर बीज के मामले में सरकार को सतर्क रहना चाहिये था। मैं अपने जिले के तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि गतवर्ष सरकार के बीज गोदामों से सैकड़ों मन ही नहीं, बल्कि हजारों मन की तादाद में गल्ला बाजार में, रोजगारियों को बेचा गया और

वह सस्ते दाम पर बेंचा गया। इसके बाद जब बीज की जरूरत हुई तो नये बीज गोदाम खोले गये और उनके लिये ऊंचे दाम पर बीज बाजारों से खरीदा गया और यही नहीं हुआ, बल्कि बीज के लिये अन्य प्रदेश के सामने हमको हाथ फैलाना पड़ा। उसका नतीजा यहां तक पहुंचा कि बीज के मामले में हम अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि नियोजन का हमारा इतना बड़ा विभाग है उससे ऐसी भूल ऐसे वक्त में जबकि गल्ले कि हमारे यहां कमी है, और गल्ले की पैदावार बढ़ाने की जरूरत है तब बीज जैसे मामले में हो गई। गल्ले की पैदावार का सवाल हमारे सामने बहुत अहम है। इस विभाग से ऐसी भूल हुई। इसका मुझे खेद है।

दूसरा प्रश्न जो मैं सदन के सामने पेश किया चाहता हूं वह यह है कि बीज की क्वालिटी कैसी है। मैं कई गत वर्षों से सरकार के प्रोग्राम देख रहा हूं कि वह ए क्लास सीड स्टोर खोलने पर लगी हुई है। ए क्लास सीड स्टोर की परिभाषा यह है कि वह पंजाब–५९१ है। कोई भी माननीय सदस्य इससे इन्कार नहीं कर सकता कि इस गेहूं को कम से कम दो आबपाशी वरना तीन आबपाशियों की जरूरत है। अगर सूखे खेतों में जहां आबपाशी का कोई जरिया नहीं है यह बीज दिया जायगा तो पैदावार घटेगी। यह भी अम्र मुसल्लम है कि हमारे प्रदेश की लगभग ३० प्रतिशत भूमि सिंचित है और यदि हम छोटे काश्तकारों की ही भूमि लें तो वह केवल २० प्रतिशत ही होती है। उसमें भी उसने ज्यादातर गन्ना बोना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि छोटे काश्तकार को लगभग १५ फीसदी भूमि सिंचित है और १०० प्रतिशत बीज छोटे काश्तकारों को सिंचित भूमि का दिया जाता है। आज जरूरत है कि छोटे काश्तकारों को बीज सिंचाई के लिहाज से दिया जाय।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अब मेजर इर्रीगेशन स्कीम्स से हटकर हमारी प्रान्तीय सरकार की माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स की तरफ मुतवज्जह हुई है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि २४६ लाख रुपया वह इस वर्ष मेसनरी वेल्स पर खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बजट में यह देखकर दुख होता है कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर गत वर्ष से सबसिडी १५,००० रुपया घटा दी गई है और मेसनरी वेल्स पर (subsidy) ८ लाख रुपया घटा दी गई है। मैं तो उम्मीद करता था कि इस वर्ष के नियोजन कार्यक्रम में सर्विस कोआपरेटिव्ज का जिक्र भी होगा लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। आज जो मेसनरी वेल्स बनाये जा रहे हैं उनमें सर्विस कोआपरेटिव्ज का कोई लिहाज नहीं है। आज खुली छूट है कि कोई काश्तकार कहीं भी कुआं बना सकता है, लेकिन जब हम कोआपरेटिव बना लेंगे तो ये बेतरतीबी से बने कुयें एक ही सोसाइटी में कई-कई हो जावेंगे और बहुत से बेकार हो जावेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि ये मेसनरी कुयें इस प्रकार बनाये जावें कि जब हम कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू करें तो ये बेकार न हो जावें। एक ट्यूबवेल के खर्चे में सरकार इतने मेसनरी कुयें बनवा सकती है कि वे उसके एरिया को कमान्ड कर सकते हैं।

अन्न के उत्पादन के सरकारी टार्जेट्स के बारे में मेरी समझ में नहीं आता कि इनके मायने क्या हैं और उनको पूरा करने के लिये वे कैसे अनुमान लगाते हैं। १९५७–५८ का एडीशनल फूडग्रेन (प्रोडक्शन) का टार्गेट ५·२१३ लाख टन था, १९५८–५९ का ६·४९ लाख टन था और १९५९–६० का ५ लाख टन है। हमारी आबादी हर वर्ष इतनी बढ़ती जा रही है कि एक नया जिला बढ़ जाता है। तो फिर एडीशन फुडग्रेन्स का टार्गेट क्यों घट रहा है? खासतौर से जब कि गत वर्ष के टार्गेट पूरे नहीं होते हैं तो वह बढ़ना चाहिये। मैंने हिसाब लगाया है कि १९५९–६० की पैदावार का यदि (target) पूरा भी हो जाय तो १९५६–५७ के लिहाज से ८·४ लाख टन कम होगी। मेरा ख्याल है कि टार्गेट बजाय यहां से तय होने के हर जिले में देहात की पोटैन्शलीटीज को देखकर तय होना चाहिये।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि योजना के द्वारा

[श्री हिम्मत सिंह]

हम भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करने जा रहे हैं। मुझे आध्यात्मिक की उन्नति बात सुनकर कुछ प्रसन्नता तो हुई लेकिन उन्होंने इसपर प्रकाश नहीं डाला कि हम आध्यात्मिक उन्नति और ग्रामीणों के जीवन का कैसे उत्थान कर सकते हैं ? उन्होंने बताया कि स्वार्थ को परमार्थ में और संघर्ष को सहयोग में परिवर्तित करने की वह चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिये किसी योजना पर प्रकाश नहीं डाला। योजनाओं का उदाहरण देते हुये बच्चे का उदाहरण दे डाला कि जैसे वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और उठता है वैसे ही हम भी गिरेंगे और उठेंगे। इसका मैंने यही मतलब निकाला कि हमारी योजनायें भी गिरेंगी, उठेंगी और हम उनसे अनुभव लेते रहेंगे और तब कहीं ४०, ५० वर्ष बाद जैसे बच्चा नौजवान और अनुभवी होता है वैसे ही हम उतने समय बाद देश का कल्याण कर पावेंगे। तो मैं यह समझा कि अमरीका के कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और साम्यवादी देशों से प्लानिंग लेकर एक मिक्स्चर सा बना लिया है। यह सफल नहीं होगा। खाद्यान्न के लिये पंचवर्षीय योजना में घोषणा की गई थी कि हम इतना अन्न पैदा कर लेंगे कि हम उसके लिये दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलावेंगे। लेकिन फिर भी ११,१२ साल बाद हमारे यहां अन्न की कमी है और कमी का परसेंटेज भी कुछ १६ के लगभग बताया। तो मालूम होता है कि पहली योजना तो फेल हुई और दूसरी में हम चल रहे हैं और जिस उद्देश्य से वह बनाई गई थी उसे छोड़ कर हम कृषि पर मुख्य ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश का काश्तकार जानता है कि किस समय क्या बोना चाहिये और कौन सा बीज बोना चाहिये। आपके खरीफ और रबी आन्दोलनों से कोई लाभ किसान को नहीं दिखाई पड़ रहा है। काश्तकार को यह समझाना होगा कि मेंह कौन से वक्त बरस सकेगा और कितना पड़ेगा। पहले एक ढाई आने का पत्रा ही काम कर देता था लेकिन अब इस युग में उस पर भरोसा नहीं रह गया है। आज किसान मक्का बो देता है और बेसमय पानी बरस जाता है तो मक्का मारी जाती है। गेहूं के लिये अक्तूबर या नवम्बर में बारिश हो जाती है तो उसे फिर से जोतना पड़ता है। तो सारी दिक्कतें मौसम की हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया है ?

बहुत से ए०डी०ओ० इत्यादि बढ़ा दिये हैं जैसे ए०डी०ओ० प्लानिंग, ए०डी०ओ० सोशल एजूकेशन इत्यादि। फिर नहर और समाज कल्याण के विभाग भी मौजूद हैं। उसके ऊपर बी०डी०ओ० का दफ्तर कायम कर दिया ये सब क्या है ? हमारे प्रदेश में यह फिजूलखर्ची चल रही है। आपका बच्चा गिरता उठता रहेगा और देश और प्रदेश के किसान का दम निकल जायगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लिखा है—प्लान की कुछ योजनाओं को देर से शुरू करने और दूसरी योजनाओं को वित्तीय वर्ष के आरम्भ से ही पूर्णरूप से कार्यान्वित न किये जाने से ३०८ लाख रुपये की शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, सहकारिता और समाज कल्याण के अन्तर्गत कमी हुई। यह कमी हुई या बचत हुई ? जब आप इन पर खर्चा नहीं कर सके तो बचत ही है। अगर आप काश्तकार को कुछ देना चाहते हैं तो आपको समय पर काम शुरू करना चाहिये।

आज प्रदेश के अन्दर ट्यूबवेल्स हैं, नहरें हैं सिंचाई के और साधन हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक ट्यूबवेल ५०–६० हजार रुपये में बनता है और एक कुआं २ हजार रुपये में बनता है। तो इतने रुपये में ३० कुयें बन जायेंगे। ४-५ बीघा की एक कुयें से सिंचाई होती है जबकि ट्यूबवेल २४ बीघा करता है। इस हिसाब से छोटे-छोटे कुओं से अधिक सिंचाई होगी। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया भी है, लेकिन उन्नतिशील बीज अगर बांटा जाता है तो किन काश्तकारों को मिलता है, छोटे-छोटे काश्तकार जिनकी ए०डी०ओ०, बी०डी०ओ० से साठ-गांठ नहीं होती, उन लोगों को वह नहीं मिल पाता। मेरे जिले में मैंने देखा कि बड़े-बड़े काश्तकारों को जिनको बीज की आवश्यकता न थी उनको बीज मिल गया और उन्होंने बाजार में बेच दिया। या तो वह खाने के काम में आया या छोटे-छोटे काश्तकारों ने ब्लैक में उसको खरीदा। यह कहां का न्याय है ? इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आजकल प्लानिंग विभाग से जो भी चीज दी जाती है वह लौट फिर कर वहां आ जाती है। एक-एक बोरे पर १०–१० रुपया अधिक लिया गया है तब बीज दिया गया है।

पहले छाया खंड थे, उनमें पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत इंस्पेक्टर ही काम करते थे। वह दरख्वास्तें ले लिया करते थे। कुछ व्यक्तिगत रूप से बनते थे। रुपया ग्राम प्रधान के नाम से जमा होता था। आज तक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि जहां पर बहुत से व्यक्तियों को रुपया नहीं मिल पाया है। हमीरपुर जिले में ऐसे गांव हैं जहां ऐसा रुपया नहीं दिया गया।

जब कुआं बन कर तैयार होता है तब उसका असेसमेंट होता है। अगर भेंट नहीं चढ़ाई जाती तो असेसमेंट भी पूरा नहीं होता। इस प्लानिंग विभाग के द्वारा जो पंचायतघर और स्कूल बनाये गये हैं उनकी लाइफ बहुत कम है। अगर पी०डब्लू०डी० द्वारा उनकी जांच कराई जाय तो मालूम होगा कि १० वर्ष से अधिक की उनकी लाइफ नहीं है। बी०डी०ओ० पर एक कार है जब कि डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग के पास कोई कार नहीं है। वह ऊपर के आफिसरों के काम में आती है। क्षेत्र मामूली सा होता है। लेकिन इस प्रकार से पब्लिक का पैसा बेकार खर्च किया जाता है।

दूसरी बात यह है कि जितने भी बी०डी० ओ० और ए०डी०ओ० हैं वे सब के सब नौजवान हैं, नये हैं, उनको कोई अनुभव नहीं है। इसलिये हमारी योजना पूरी तरह से सफलता को प्राप्त नहीं होती। बी०डी०ओ० को एप्लीकेशन लेने, असेसमेंट करने आदि की सारी पावर्स आपने दे रखी हैं वह भ्रष्टाचार का एक द्वार हमने खोल रखा है। जब हम श्रमदान के द्वारा कोई काम करते हैं, सड़कें बनाते हैं तो उस वक्त कहा जाता है कि प्लानिंग के द्वारा इसको पुख्ता करा दिया जायगा, लेकिन आज तक हमने देखा है कि उन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, वे उसी तरह से पड़ी हुई हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)––आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह निर्विवाद है कि किसी भी देश की उन्नति वहां पर नियोजन कार्य से ही होगी। इस समय हमारा देश भी इसी दौर से गुजर रहा है। इसलिये मैं अपने अनुभव के आधार पर नियोजन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, एक चीज जो मैं आपके द्वारा सदन से कहना चाहता हूं वह यह है कि आजकल नियोजन विभाग और राजस्व विभाग, इन दोनों का आपस में समन्वय होना चाहिये। उदाहरण के लिये जो श्रमदान से सड़कें बनती हैं, दो-चार छः महीने बाद ही उनके किनारे जिनके खेत रहते हैं, वे काट कर उसे अपने खेतों में मिला लेते हैं। या कुछ स्थानों पर हमारे प्रदेश में चकबंदी हो रही उन चकबंदी वाली जगहों पर नियोजित ढंग से कहीं सड़कें बनायी जाती हैं, कहीं आबादी के लिये जगह छोड़ी जाती है, कहीं पर स्कूल वगैरह अन्य कार्य के लिये जगह छोड़ी जाती है, लेकिन नियोजन विभाग की तरफ से वहां पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। तो सरकार को चाहिये कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नियोजन विभाग की तरफ से जहां चकबंदी हो रही है वहां का विशेष खयाल रखा जाय जिससे वहां जो कार्य हो रहा है वह आगे बढ़ सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल अधिक अन्न उपजाओ की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन खेत की पैदावार तभी बढ़ सकती है जबकि खेती करने वाले वास्तव में वे ही लोग हों जो कि खुद अपने हाथ से खेती करते हों। आज हमारा दुर्भाग्य है कि खेती का बहुत ज्यादा अंश ऐसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं खेती नहीं करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं या कोई दूसरा उद्यम करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करेगी कि खेत उन्हीं लोगों को मिले जो स्वयं अपने हाथ से खेती करते हों तब तक देश की पैदावार नहीं बढ़ सकती, चाहे कितना ही उपाय क्यों न किया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने देश में चल रही अल्प सिंचाई योजना का भी जिक्र किया। इस संबंध में मुझे यह कहना है कि हमारे पूर्वी जिलों में बहुत से ऐसे सैकड़ों कुयें एक-एक गांव में हैं जिनकी आज बड़ी ही खराब हालत है, वे टूटे,फूटे जा रहे हैं लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान

[श्री माताप्रसाद]

नहीं दिया जाता। साथ ही श्रीमन् एक-एक कुआं ऐसा है जिस पर एक बार ८-८ पुरवट या १६-१६ पुरवट तक चलते रहते हैं और उनसे सैकड़ों एकड़ भूमि की सिंचाई होती रहती है। वे बहुत पुराने जमाने के बने हुये कुयें हैं जिनकी हालत आज बड़ी खराब है। नियोजन विभाग सिंचाई के कुओं के लिये अनुदान या सहायता नहीं देता है, सिंचाई के नये कुओं के लिये वह ऋण देता है। आज जरूरत इस बात की है कि जो पुराने कुयें हैं उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और उनको ऋण दिया जाय तथा कुछ अंश तक अनुदान भी दिया जाय जिससे उनका जीर्णोद्धार हो जाय।

इसके सिवा दूसरी बात यह है कि नियोजन विभाग के अधिकारी जब देहातों में जाते हैं तो वे वहां सूटेड बूटेड होकर जाते हैं जिससे वे अपने को साहब समझते हैं तथा जनता भी उनको साहब ही समझती है। इसलिये उनको चाहिये कि देहात में रहने वालों की तरह साधारण पोशाक में ही जायं तथा उनके रहन-सहन से ही रहें तथा उनसे बातचीत करें जिससे उनका सहयोग उनको मिले। अगर वे देहात में रहने वालों की पोशाक में वहां नहीं जायेंगे तो वे उनका सहयोग कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे अपने को उनसे अलग समझेंगे। इसलिये इस विभाग के कर्मचारियों को चाहिये कि देहात में जाने पर वे उनसे परस्पर मिल जुल कर रहें और तभी वे उनका विश्वास भी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वे उनका विश्वास प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक जितनी भी योजनायें चल रही हैं वे सफल नहीं होंगी। चौथी चीज बी०डी०ओ० को जीप दी गई है उनके विषय में कहा जाता है, मैं भी समझता हूं कि जनता में इसके प्रति बड़ी अच्छी भावना नहीं है। मैं चाहता हूं यह जीपें ले ली जायं। यद्यपि अड़चन है कि चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है और अमेरिका से संधि के मुताबिक मिली हुई है तो केंद्रीय सरकार को प्रदेशीय सरकार यहां के विचारों को लिख सकती है कि इसका असर देहातों में अच्छा नहीं पड़ता। बी०डी०ओ० को साइकिल पर दौरा करना चाहिये जिससे जनता उनको अपने से अलग न समझे।

प्रदेश में नियोजन कार्य जो हो रहे हैं तो प्रत्येक गांव में २,४ ऐसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं जिनको हर प्रकार की सहायता दे दी जाती है और कमजोरों को नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि जब तक गिरे हुओं को, दलितों को सहायता नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं चल सकता। अधिकारी इसके बिल्कुल विपरीत करते हैं कुछ बड़े लोगों के यहां जाते हैं और हर तरह से उन्हीं को सहायता देते हैं।

हरिजनों के लिये मान्यवर एक अड़चन यह भी पड़ती है नियोजन विभाग की ऐसी शर्त है कि एक बटे तीन धन वे लगायें.....

श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय देखें मंत्री जी अफसरों से बातें कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठें।

श्री माता प्रसाद---तो मान्यवर, उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वे कुछ धन लगा सकें। इसलिये मैं कहता हूं सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जब हरिजनों के लिये अनुदान स्वीकार किया जाय तो उन्हें अग्रिम धन दे दिया जाय अगर सरकार सचमुच चाहती है कि गरीबों का फायदा हो।

इसके अलावा टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के लिये ५ प्रतिशत अनुदान रखा गया है उसे भी बढ़ाया जाय। हमारे जौनपुर जिले में करीब ३,००,००० रुपया छाया ब्लाकों में आज से करीब २ वर्ष पहले से ज्यादा खर्च हो गया है। मैं चाहता हूं सरकार वहां ज्यादा रुपया दे, क्योंकि सभी काम रुक गये हैं।

वाउचर्स की जांच में कर्मचारी बहुत देर करते हैं जिससे जनता को परेशानी होती है। सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि वाउचरों की शीघ्र जांच की जाया करे और उन्हें शीघ्र किस्त दी जाय।

हमारे जिले की जिला अंतरिम परिषद् से एक प्रस्ताव आया था कि जो ब्लाक बने हैं उनकी सीमा में हेरफेर किया जाय। सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिये यह मेरी प्रार्थना है।

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि बहुत से ग्राम-सेवक ट्रेनिंग पा चुके हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है। अगर उनकी नियुक्ति सरकार नहीं कर सकती है तो आगे ट्रेनिंग ज्यादा न दी जाय जिससे वे भी बेकार रहें।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई माननीय सदस्य सरकार की जो नीति है उसके विरोध में पूरा भाषण करे और अन्त में यह कह सकते हैं कि वे उसका समर्थन कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––वे सुझाव दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––नीति का विरोध तो नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता––नीति में भी वे अपने सुझाव दे सकते हैं।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)––अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज का जो अनुदान है वह कहां तक सफलीभूत हुआ है। हमारे यहां जो नियोजन विभाग का कार्य चल रहा है, वह अपने देश के बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक उन्नति के लिये चल रहा है। आर्थिक उन्नति के प्रोग्राम में रबी अभियान और खरीफ अभियान खास बातें हैं जिनसे अपने सूबे की हालत अच्छी हो सकती है। यह कार्य जिनके द्वारा संचालित है उन लोगों की मनोवृत्ति कैसी है? कितना सही काम करते हैं? जो रुपया उनको दिया जाता है वह किस तरह से गांव में देते हैं? किसानों तक पहुंचते-पहुंचते उसका कैसा उपयोग होता है? इन पर हमें खास तरीके से विचार करना है।

अगर हम बी०डी०ओ० और ए०डी०ओ० की तुलना ऐसे लोगों से करें जैसा कि कुछ धर्मों में यह है कि जो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं उन्हें कुछ हूरें मिला करती हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज जो उन्हें मोटरें मिली हुई हैं उनको लेकर के वह देहातों में क्या करते हैं? हर विधायक जानता है कि वह कितना काम करते हैं। बहुत से कार्य जो गांव में किये गये हैं, अभी काम तो हुए नहीं हैं, अपूर्ण हैं, और उनके पूर्ण होने की रिपोर्ट दे दी गई है। जैसे एक ग्राम पिपरापाती महाराजगंज क्षेत्र के अन्दर है वहां पर स्कूल को अनुदान दिया गया है। स्कूल नहीं बना है, लेकिन उसके पूर्ण होने की रिपोर्ट पहुंच गई है। इस तरह से उनका कार्य आज हो रहा है। वह बराबर अपने क्षेत्र में गरीबों को दबाने का प्रयत्न करते हैं। अभी परतावल के बी०डी०ओ० ने एक आदमी को दबवा कर मरवा डाला है, जिसकी रिपोर्ट कांग्रेस आफिस में तथा और भी जगह हुई है। तो जब उन्नति कराने वाले की ऐसी भावना है तो वह कैसे उन्नति करा सकता है। इसलिये इनके कामों को हमेशा देखा जाय कि क्या करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अभी हमारा खरीफ अभियान जो है वह पूर्ण सफल नहीं है। रबी अभियान पूर्ण सफल नहीं है। तो मैं खरीफ अभियान के सिलसिले में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा ऐसा मत है कि खरीफ की तरक्की के लिये, खरीफ की पैदावार बढ़ाने के लिये जो धान जापानी ढंग से बोया जाता है, अगर पानी बरसता है उसे लेवा जब लगाया जाता है तो उसे एक ही लेवा में न बैठवा दिया जाय। बल्कि तीन लेवा लगवा

[श्री दुर्योधन]

लें, जब खूब मिट्टी सड़ जाय तब उसमें धान बैठाया जाय। तो मेरा मत है कि पैदावार दुगनी हो सकती है। इसलिये हर अधिकारी को यह सुझाव दिया जाय कि वह गांवों में यदि पानी की सुविधा हो तो किसान से कहे कि वह एक ही लेवा में धान न बैठावे, बल्कि तीन लेवा देकर कोशिश करे धान बैठाने की तो उसकी पैदावार बढ़ेगी।

आज जो हमारे अधिकारी विकास योजनाओं में काम करते हैं यदि उनकी मनोवृत्ति अच्छी हो जाय, वह उनकी मदद करें, उन्नति के काम में अग्रसर हों, तो कोई वजह नहीं है कि गांव की उन्नति न हो। विकास योजनायें जो चल रही हैं उनसे काम तो अवश्य ही कुछ हुआ है, जैसे सड़कों का निर्माण। जहां के बी०डी०ओज० ने पूरी कोशिश की, उस ब्लाक में अवश्य काम हुआ है, लेकिन अधिकतर बी०डी०ओज० ने यही काम किया है कि अपने यहां केवल एक दिखावे का प्रोग्राम बनाया है। बहुत से किसान मेले इत्यादि जो लगाये जाते हैं वह केवल खर्चा बढ़ाने के लिये ही लगाये जाते हैं। वहां पर भत्ते आदि में अधिक रुपये खर्च किये जाते हैं। वह अगर बचाये जायं और गांवों में ही अधिक काम कराये जायं तो उन्नति हो सकती है।

इसके अलावा कुओं आदि की जो समस्या है वह विकास के लिये जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि हम अधिक कुयें बनवाया चाहते हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारा अनुभव है कि यदि कुओं की संख्या बढ़ाई गई तो देश की पैदावार बढ़ेगी। उस से अव्वल तो लोगों को रोजगार मिलेगा और दूसरे जब भी जिस समय चाहें वह कोई भी फसल बोकर पैदा कर सकते हैं। कुओं से पानी के लिये किसान को किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं होती। अतः कुयें अधिक से अधिक तादाद में बनवाये जायं, लेकिन इस संबंध में जो अनुदान और सहायता दी जाती है वह कैसे मिलती है यह हर सदस्य जानता है। मैं सरकार से कहूंगा कि इस संबंध में जितनी सहूलियत हो सके वह दी जाय, ताकि आसानी से वह सहायता किसानों को मिल जाय और कोई उन से अनावश्यक पैसा न ले और देरी न लगावे। ऐसा भी बहुधा देखा जाता है कि जो कुयें मंजूर होते हैं उनका पैसा मिलने में आखिर तक कोई कुआँ ऐसा नहीं रहता कि किसी को १०० रुपया खर्च न करना पड़े। इस तरह की चीजों को दूर करके आसानी पैदा की जाय कि किसान को रुपया आसानी से मिल जाय, जिससे वह अपना कुआं बना सके और देश की तरक्की में पूर्ण सहायक हो सके।

इस के अलावा अन्य छोटी छोटी योजनायें जो देहातों में चालू हैं उनपर विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि हमारे यहां बहुत सा गोबर जला दिया जाता है, उस को जलाकर लोग देश की सम्पत्ति जलाते हैं और गांव का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिये अधिकारियों को खास तौर से हिदायत की जाय कि वह अपने यहां गड्ढे बनवा कर गोबर इकट्ठा करावें और उस की खाद बनवाकर खेतों में प्रयोग करावें और ऐसी योजना बने कि जो अधिकारी काम अधिक उत्तम करें उन को इनाम और प्रोत्साहन दिया जाय। गांव सभायें भी जो अच्छा काम करें उन को भी इनाम और प्रोत्साहन दिया जाय ताकि देश में पैदावार बढ़ सके।

दस्तकारी के संबंध में मैं कहूंगा कि हमारे यहां गांवों में बहुत से लोग बेकार बैठे हुये हैं। दस्तकारी का काम जो विकास के द्वारा चलाया जा रहा है उस को और बढ़ाया जाय और किसानों को और उनकी औरतों को चरखे का काम देकर उनकी मदद कराई जा सकती है, लेकिन आज के जो सरकारी अधिकारी हैं उन का रवैया यह है कि वह विशेष रूप से इस तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि आराम करते हैं। वे चाहते हैं कि जब वह गांव में पहुंचें तो उन्हें ज्यादा लोग सलाम करने वाले मिलें और उनकी मीटिंग में ज्यादा लोग हाजिर रहें, परन्तु वह यह कोशिश नहीं करते कि गांव के लोगों की हालत कैसे सुधरे।

एक तरफ तो हम देखते हैं कि वन महोत्सव होता है और दूसरी तरफ तमाम बाग कटते चले जाते हैं। अधिकारियों का रवैया ऐसा हो गया है कि वह अगर पैसा पा जाते हैं

तो लिख देते हैं कि बाग पुराना हो गया है और फलता नहीं है। नतीजा यह होता है कि अच्छा खासा बाग कट जाता है। बहुत जगह डालें गाड़ कर वन महोत्सव में दिखला दिया जाता है कि पेड़ लगाये गये हैं और पेड़ बिलकुल लगे नहीं होते हैं।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसमें संदेह नहीं श्रीमन्, कि आज हम प्लानिंग के युग से गुजर रहे हैं। प्लानिंग से ही किसी भी प्रजातांत्रिक देश में और विशेष कर अन्डर-डेवलप्ड कंट्री में उन्नति हो सकती है। उसमें पहले हम टारगेट नियत करते हैं और उसको दृष्टि में रखते हुये अपने साधनों का एकीकरण करके नियोजित ढंग से रखते हैं तब प्लान तैयार होती है। उसमें कई चीजों की आवश्यकता होती है। खास तौर से हमारे इस देश में यह प्लान भी पीपुल्स प्लान है, इसलिये उसके लिये कुछ आवश्यकताएं हैं। जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि हम जनता की भावनाओं को देखते हुए अपने उन तमाम साधनों को ऐसा प्लान करें कि जिससे हमारी प्रगति में कोई रोड़ा न हो सके और हमारे लक्ष्य भी प्राप्त हो जायं।

सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्लान में यह है कि हम देखें कि आवश्यकतायें क्या हैं और आवश्यकताओं को इकट्ठा करके फिर उनको प्रायोरिटीज दें, यही पहला काम है। आज जो हमारी प्लान चल रही है उसका चौथा वर्ष है और इसमें जो भारी कमी मुझे नजर आयी वह यह है कि जो टारगेट्स नियत किये गये या जो निर्माण के कार्य अपने प्लान में अंकित किये गये उनको ठीक प्रकार से प्रायोरिटी नहीं दी गयी। जरूरत इस बात की है कि जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो उसको पहली प्रायोरिटी और जिसकी कम जरूरत हो उसको दूसरी प्रायोरिटी दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ यह है कि जहां पर जिस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा सुविधा हो वह पहले बना दी गयी, लेकिन आवश्यकता को आधार नहीं लिया गया। ऐसी मिसालें आज भी मौजूद हैं, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जिनको पहले लेना चाहिये था उन्हें आजतक नहीं लिया गया। हम तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जब यह सेकेंड फाइव ईयर प्लान खत्म होने जा रहा है तो कम से कम अपना प्लान उठा कर देखें कि कौनसी चीजें बनाने की आवश्यकता थी और बनाने को कौन सी रह गयीं।

यह सही है कि आज सबसे प्रथम आवश्यकता हमारे प्रदेश की उपज को बढ़ाने की है। उसके क्या क्या साधन हैं, उन साधनों को किस तरह से हम नियोजित करें जिससे उपज बढ़े, खाद्यान्न की समस्या हल हो और हम इतना पैदा करें कि केवल यही नहीं कि हमारे प्रदेश के रहने वालों के लिये काफी हो, बल्कि हम खाद्यान्न का निर्यात करके पूंजी भी इकट्ठी कर सकें तभी हम समझते हैं कि हम समृद्धिशाली हो सकेंगे। आज तक जो भी कार्य सरकार ने किये हैं, चाहे अच्छे बीज बनाने का, बीज गोदाम बनाने का या सिंचाई के साधन देने का या सेहत के साधन क्यों न हों, ये सब उसी तरफ हम को ले जाता है जिस तरफ हम किसानों को अधिक से अधिक सुविधा पहुंचायें, लेकिन थोड़ा सा संकेत अगर मैं इस ओर कर दूं कि आज जब हमको खाद्यान्नों के पैदा करने की आवश्यकता है, जबकि हम को अपनी उपज बढ़ाने की आवश्यकता है तो आवश्यक यह होता है कि प्राथमिकता हम गांव वालों को दें। हमें आज शहर की जो जरूरियात हैं उनको जरा सा नजरअन्दाज करके देहात की ओर चलना चाहिये। हम आज अपने प्रदेश की जनता को यह नारा दें कि "चलो गांव की ओर" और हम गांव की ओर चल दें और जितने भी साधन और सहूलियतें हो सकती हैं वह गांव में पहुंचायें। मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही अपनी उपज प्रदेश की बढ़ा सकेंगे।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव]

आज, जैसा कि अभी एक भाई ने कहा कि गांव के अन्दर भले ही सड़कें न हों, लेकिन शहरों को जो ब्यूटीफाई करने की सरकार की टेंडेंसी है, जो उनके डेकोरेटिंग व्हिम्स हैं उनको छोड़कर के उसे गांव वालों को देखना चाहिये कि आज उनको अस्पताल मिले हैं या नहीं, उनको सड़कें मिली हैं या नहीं, उनको साफ पानी पीने को मिल रहा है या नहीं, वहां बीज के गोदाम बने हैं या नहीं, क्या प्रदेश का जो पिछड़ा अंचल है वहां ब्लाक्स खुले हैं या नहीं। जिस तरह से हमारे प्रदेश की प्लानिंग है, मैंने जहां तक उसका अध्ययन किया है, मैं तो उसके लिये अपनी सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि वह एक निश्चित और ठीक ढंग से हुई है, लेकिन प्लान बना लेना ही सारा काम नहीं है, बल्कि जनता में एक भावना पैदा करनी है कि यह पीपुल्स प्लान है और जनता यह समझे कि हम खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें इस चीज के लिये बहुत सतर्क रहना है। ऐसा न हो कि सब प्लान तैयार करके हम जनता को पंगु करके डाल दें। आज हम चाहे जितनी यूनिवर्सिटियां खोल दें, चाहे जितने अस्पताल बनवा दें, लेकिन अगर हमने जनता के दिमाग का नियोजन नहीं किया तो नियोजन सफल नहीं हो सकता। जरूरत इस बात की है कि हम जनता का सहयोग लें और जनता का सहयोग तभी मिल सकता है जब हम अपनी प्लान को एक पीपुल्स प्लान बनायें। अगर यह ख़याल जनता में फैल जाय कि सरकार कुयें बनवायेगी, सरकार नहर बनवायेगी, सरकार बीज देगी तो बड़ा भारी नुकसान हो जाने का अन्देशा है। लिहाजा मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि जब वे तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं और द्वितीय पंचवर्षीय के चौथे वर्ष में पदार्पण कर पांचवें वर्ष में जा रहे हैं तो अपने प्लान को ऐसे सांचे में ढालें जिससे हम उसे पीपुल्स प्लान विद पीपुल्स पार्टिसिपेशन (Peoples' plan with peoples' participation) कह कर सफल कर सकें।

इस संबंध में सब से बड़ी चीज प्लान के इम्प्लीमेंटेशन की है। यह ठीक है कि हमने पूलिंग का सिद्धांत अपनाया और तमाम विभागों की ऐक्टिविटीज को एक जगह पूल कर दिया, लेकिन उसके करने का ढंग क्या है यह तो देहात में जा कर ही पता चल सकता है। यह मैं नहीं कहता कि हमारे ब्लाकों से देहातों की कोई तरक्की नहीं हुई, लेकिन जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जो हमारे सरकारी अफसरान ब्लाक्स के जिम्मेदार हैं वे वहां हुकूमत करने के लिये नहीं भेजे गये हैं। वे वहां जनता के दिमाग को बदल कर जनता को स्वावलम्बन के द्वारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये भेजे गये हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो ब्लाक्स की ऐडवाइजरी कमेटीज के रेजोल्यूशन्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं, यह एक मूलभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी प्लानिंग सफल हुई या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पुस्तिका जिसका नाम "Our Plan" है उसका पहला जुमला पढ़ना चाहता हूं :---

"A better, richer and happier life for every man and woman is the chief purpose of the Five-Year Plan,"

पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय प्रत्येक नरनारी के जीवनस्तर को ऊंचा करने, धनवान् बनाने तथा अधिक प्रसन्न करने का है। जब हम इस कसौटी के ऊपर दोनों पंचवर्षीय योजानाओं को कसते हैं तो बिलकुल असफल पाते हैं।

श्रीमन्, सरकार कृषि उत्पादन की उन्नति की बड़ी डींगें मारती है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन के लिये अच्छे बीज की आवश्यकता होती है। यह देखने में आता है कि सरकार अच्छे बीज का समुचित प्रबन्ध अपने बीज स्टोर्स के जरिये नहीं कर पाती है। इस बार सीड स्टोरों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, बाद में यहां से उसको खारिज किया गया, लेकिन पहले यह प्रतिबंध था कि जो काश्तकार फर्टिलाइजर लेगा उसी को अच्छे बीज दिये जायेंगे।

श्रीमन्, अनइरीगेटेड एरियाज, जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं उनमें फर्टिलाइजर्स से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उलटे नुकसान होता है। हमारे जिले खीरी में दो तहसीलें ऐसी हैं जिनमें सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां फर्टिलाइजर्स दिये गये। उनसे कोई लाभ नहीं हुआ उलटे किसानों को नुकसान ही हुआ।

यह सरकार जो प्लानिंग करती है वह ज्यादातर कागज के ऊपर होती है। इतनी ज्यादा पुस्तकायें और पत्रिकायें छापी जाती हैं कि उनको संकलित करने वाले ही उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं।

हर महीने लगभग १८ या २० दिन होते हैं जब बी० डी० ओ० को जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा उनका समय मीटिंगों में व्यय होता है और जिस काम के लिये वह रखे जाते हैं उस काम को अच्छी तरह से नहीं देख पाते। उच्चाधिकारियों के निरीक्षण इतने ज्यादा होते हैं कि उनका अधिक समय निरीक्षण कराने में ही व्यय होता है। स्पाट पर काम करने के लिए १० विलेज लेविल वर्कर्स और १० अन्य वर्कर्स होते हैं, लेकिन निरीक्षण पर ४ ए० डी० ओज०, १ बी० डी० ओ०, एक डी० पी० ओ० और ए० डी० एम० पी० और उसके अलावा तमाम कोआपरेटिव आफिसर और ऐग्रीकल्चर आफिसर कितनी संख्या निरीक्षण करने वालों की होती है, लेकिन मौके पर काम करने वालों की तादाद बहुत कम होती है। इस तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो ब्लाक्स की बिल्डिंग्स बनवायी हैं उनमें बहुत सी अच्छी जगह पर नहीं बनी हैं। मैंने उनमें से बहुत सी देखी हैं और उनमें से एक के बारे में अपने तजुर्बे को कहता हूं। उन्नाव जिले में बिछिया में नहर के किनारे जो बिल्डिंग बनी हुई है वह रेहू और लोना मिट्टी पर बनी है और धीरे धीरे नीचे से गिरना शुरू हो गयी है।

इनकी बिल्डिंस का नकशा तरीके से नहीं बनता है। मुझे आश्चर्य होता है यह बताते हुए कि इन की लैट्रिन्स में किवाड़ों की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दें और इसकी व्यवस्था कराये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो श्रमदान कराती है आज उसका जिक्र बहुत कम हुआ है और असल में अब श्रमदान कम होना भी शुरू हो गया है, लेकिन यह ज्यादातर गरीबों से ही कराया जाता है और श्रमदान से जो सड़कें बनती हैं तथा अन्य काम होते हैं उनके निरीक्षण तथा दुरूस्ती की व्यवस्था ठीक से नहीं होती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस विभाग में दुनिया भर के नक्शे आदि बनाये जाते हैं, लेकिन अभी तक इसके कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट नहीं बनी है।

दूसरा सुझाव यह है कि बी० डी० ओज का जो डायरेक्ट चुनाव होता है वह इस तरह से होना चाहिये कि ५० प्रतिशत ए० डी० ओज० में से लिये जायं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। सरकार शहरों की सड़कों की तरफ बहुत तवज्जुह देती है, लेकिन देहात की तरफ कोई तवज्जुह नहीं है। जमींदारी खत्म होने के बाद लोगों ने गांवों के गलियारे तथा सड़कें जोत ली हैं। गो इसके लिये कानून हैं, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो रहा है, इसलिये सरकार आदेश दे कि जो गलियारे और सड़कें जोत डाली गई हैं उनको निकाला जाय और इसके लिये जिलाधीशों को समरी पावर्स दी जायं, ताकि ऐसे लोग बेदखल किये जा सकें।

टूरिस्टस ब्यूरियों की एक ब्रांच हमारे खीरी जिले में भी है। अभी हाल में उनका एक हाथी मार डाला गया। वहां जंगल काफी हैं और बाहर के लोग शिकार करने आते हैं इसलिये इधर सरकार को ध्यान देना चाहिये जिससे उनको प्रोत्साहन मिले। पहाड़ों पर कोई इंडस्ट्री नहीं है और अब गर्मियों में लोग कम जाते हैं जिससे वहां जो कुली वगैरह का काम करते थे उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है कि टूरिस्टस को प्रोत्साहन दिया जाय और अगर पहले की तरह से लोग पहाड़ पर जाने लगें तो गरीब मजदूरों का बड़ा हित होगा।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

श्रीमन्, जो बजट हम यहां पास करते हैं वह जुलाई अगस्त में विभागों को रिलीज होता है । इसके बाद नवम्बर, दिसम्बर, में जाकर कहीं ब्लाक्स में पहुंचता है । सरकार इस ओर ध्यान दे कि ३, ४ महीने में कितना काम हो सकता है । मई तथा जून तक बजट रिलीज हो जाना चाहिये जिससे उसका ठीक तरह से उपयोग किया जा सके । श्रीमन्, प्रांत के गरीबों के उत्थान के लिये जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं वे ज्यादातर नाकामयाब रहती हैं । उनको मकान कुआं बनाने के लिये तकावी नहीं मिल पाती है । इसमें इतनी देर की जाती है कि मार्च में ज्यादातर रुपया लैप्स हो जाता है । इस तरफ ध्यान दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--मान्यवर, इसके पहले कि मैं इस वाद-विवाद में हिस्सा लूं मैं अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं कि आपको इसके लिये धन्यवाद दूं कि आपने मुझे मौका दिया है । राजनीतिक आजादी के बाद हमने सोचा कि एक नियमबद्ध योजना बनायें ताकि उन वचनों को, उन प्रतिज्ञाओं को, उन आश्वासनों को जो लड़ाई जीतने के पहले हमने जनता में उद्घोषित किये थे कि जब हमारे देश में हमारा राज्य होगा, जब हम देश की हुकूमत अपने हाथ में लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस सफे जमीन पर गरीबी न रहे, निरक्षरता काफूर हो जाय । अतः हमने आते ही आते सर्वप्रथम उन तमाम अभिशापों को, जिनसे हमारी सुषुप्त शक्तियां उद्बोधित होने में अवरुद्ध थीं उनको दूर करने के लिये हमने योजना बनायी । प्रथम योजना को हमने पंचवर्षीय योजना की संज्ञा प्रदान की । यह सही बात है कि वह जनता की योजना नहीं थी । सरकार की योजना थी । उसके बाद हमने दूसरी योजना बनायी जो हम चला रहे हैं । इस योजना का भी जनता से उतना सम्बन्ध नहीं है जितना होना चाहिये था । इस योजना का भी सम्बन्ध सरकार से ही ज्यादा है ।

प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये हम इस विभाग पर खर्च करते हैं, गरीबी के विनाश के लिये, निरक्षरता के विनाश के लिये, अपनी सुषुप्त शक्तियों को उन्नत करने के लिये । बाअदब अर्ज करना चाहता हूं कि हम प्रयास तो काफी करते हैं, धन ज्यादा व्यय करते हैं, प्लानिंग एक बड़ा विभाग है जिसमें सैकड़ों अधिकारी प्रदेश के स्तर से ले कर जिले के स्तर तक हैं, लेकिन जब हम उनका प्रतिफल देखते हैं, उनकी क्रियाओं का निष्कर्ष देखते हैं तो निश्चय इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितना हमने सरफा और मेहनत की है हमें उतनी प्राप्ति नहीं हुई है । हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना का मेरुदंड कृषि रही है । और यह कहा गया कि हमने अपने टार्गेट को पूरा कर लिया है, लेकिन जब हमारी बाजारों में खाद्यान्नों का भाव बढ़ने लगा और हम सोचने लगे कि आखिर बात क्या है तो प्लानिंग कमीशन ने भी यह कहा कि हमारे आंकड़ों में गलती थी । हमारा टार्गेट पूरा नहीं हुआ था । आज हम देखते हैं कि कृषि की उन्नति के लिये जितना प्रयत्न हम करते हैं उतनी उन्नति नहीं हो पाती है । हमारा खाद्यान्न उतना पैदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिये । क्या वजह है ? आप आंकड़े उठा कर देखें सन् १९५५-५६, ५६-५७, ५७-५८ की बनिस्बत क्रमशः हमारा कृषि उत्पादन कम होता चला जा रहा है । इसका कारण तो हमें ढूंढना ही चाहिये । इसका कारण अगर हम अंधेरी कोठरी में ढूंढते रहें तो हमारा श्रम और धन बेकार ही होगा । आज हम जिले स्तर की बात करना चाहते हैं । जब तक ग्रामों में ग्रामीण नेतृत्व का उद्बोधन नहीं होगा, तबतक हजार आप ऊपर से प्लान चलाने की कोशिश करें, नियोजन करें, योजना बनायें, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । आप जानते हैं, मेरा निजी अनुभव भी है, ५३-५४ में हमने देखा कि जब इस प्लानिंग का शुरु शुरू का चरण था, हमारे देहातों में क्या श्रमदान, क्या नालियां बनाना, क्या सड़क बनाना, क्या कुंए बनाना, एक धूम सी मची हुई थी । लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए इसकी तरफ से लोग उदासीन होते चले जा रहे हैं । लोगों के दिलों में अब उतनी रुचि नहीं है । आखिर इसका कोई कारण होगा ? कारण साफ है । जो आपके अधिकारी रखे गए हैं और जो ग्रामीणों को जगाना चाहते हैं उनमें राष्ट्रप्रियता एवं ग्रामों के साथ प्रेम, स्नेह,

के भाव, की कमी है। वह ऐसी वेशभूषा में रहते हैं, इस तरह की वाणी बोलते हैं, जिससे जनता अनभिज्ञ है। उनको वह समझती है कि वह कुछ दूसरे ही तरह के व्यक्ति हैं। कुछ कुछ वैसा ही समझने लगी है जैसे कि सन् ४७ के पहले सरकारी अधिकारी समझा करते थे। उन पर से धीरे धीरे उनकी आस्था घटती चली जा रही है। जब तक उस निष्ठा को जोड़ा नहीं जायगा तब तक हजार स्कीमें आप बनाइए, मुख्य मंत्री योजना बनायें, मुझे दुख है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह योजना रद्दी की टोकरी में पड़ जायगी और उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

अपने जिले की बात है। अफसरों ने कहा कि कुएं बनवाये जायं, लोगों ने कुएं बनाये। बनवाने के बाद अबतक दौड़ रहे हैं, सन् ५२ से लेकर ५९ तक। उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ। बताइए कि उनके मन में कौन-सी आस्था जागेगी इन अफसरों के प्रति ? बहुत से कुओं के लिये लोगों को ऋण दिया गया था। लोगों ने वह कुएं कुछ वक्त बाद बनवाये कुछ वक्त के बाद बनवाने के भी कारण थे। इधर दो तीन सालों से अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण हमारे यहां लोगों की हालत बहुत खराब थी, वह कुएं बनवा नहीं सकते थे। हमारे यहां के उस समय के जिलाधीश जो आजकल हमीरपुर में हैं, उन्होंने वहां के लोगों को कुआं बनवाने के लिये और समय दिया। उनके चले जाने के बाद दूसरे जिलाधीश आज्ञा देते हैं कि एकमुश्त ५०० रुपया वसूल कर लिया जाय। किसान कहता है कि हमने कुएं बनवा लिये, लेकिन उसकी जांच तक नहीं कराई जाती। जब ऐसी स्थिति हो तो जनता का सहयोग अधिकारियों के साथ कैसे रह सकता है ? छोटी छोटी बूंदों से समुद्र बनता है और वही समुद्र एक सतह पर जाकर प्रलयंकर रूप धारण कर लेता है। ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका नतीजा बड़ा भयंकर हो सकता है। मैंने यह भी देखा कि कुछ एक गांव के रहने वालों ने मिलकर के सहयोग से कुंआ बनाया। लेकिन एक व्यक्ति ने (जैसे कि हर गांव में होते ही हैं) यह लिखकर कि मैंने कुआं बनवाया है और बी० एल० डब्लू० से मिल कर फर्जी कागजात पेश करके उसका रुपया ले लिया। ग्रामीणों ने रिप्रेजेंटेशन किया कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनकी बातों को कौन सुने ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। क्या कोई गवर्नर दीर्घा या आफिसर्स दीर्घा में बैठकर अखबार पढ़ सकता है ? जब माननीय सदस्यों के लिये यह ठीक नहीं है तो उनके लिये भी ऐसा करना हाउस के डिकोरम के खिलाफ होगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह सदन में माननीय सदस्यों का नियंत्रण तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई गवर्नर दीर्घा में सदन के काम के सम्बन्ध में दो एक मिनट अखबार देखता है तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, जिस तरह कि माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि सदन में कोई पैर बाहर लटकाकर नहीं बैठ सकता जिसमें वह अध्यक्ष की तरफ पड़ता हो, तो वह सबके लिये थी, उसी तरह यह व्यवस्था भी सबके लिये होनी चाहिये क्योंकि सदन के डिकोरम की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले पूरी व्यवस्था सुन लें। कभी कभी आवश्यकता हो सकती है कि किसी अंश को देखने के लिये जो हाउस से सम्बन्धित हो दो एक मिनट तक कोई अखबार देखा जाय, लेकिन आम तौर पर इसका नियम बना देना यह हाउस के डिकोरम के विरुद्ध है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—मैं यह कह रहा था कि जब ऐसी स्थिति है तो जनता की रुचि इन अधिकारियों के प्रति कैसे हो। हमारे मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा कि अगर बालक लड़खड़ाकर गिरता हो तो यह हमारे लिये हंसने की बात नहीं है। मैं भी कहता हूं कि यह हंसने की बात नहीं है और हंसना नहीं चाहिये। हमें मालूम है कि समय पाकर वह दौड़ेगा और कूदेगा

[श्री गंगा प्रसाद सिंह]

और ऊंचे पर चढ़ सकेगा, लेकिन---मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैं उप मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लड़का इस अवस्था में गिरेगा, गिर सकता है पर उसके लिये जो धाय आपने निश्चित की है, जो दाई उसके लिये नियुक्त की है, अगर वह दूध के बदले पानी पिलाये तो आप क्या करेंगे ? आप उसके लिये क्या दंड निर्धारित करेंगे ? आज जो ये हमारे अधिकारी हैं, जो हमारी जनता के भीतर जनप्रेम जागृत करने के लिये गये थे उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं है, वे जनता में प्रेम पैदा नहीं कर सकते। उनमें हुब्बुल वतनी की कमी है। जब नहीं है तो ऐसे अधिकारियों के दिमाग़ों को बदलकर टोन अप करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---मान्यवर, अनुदान संख्या ४५ पर लाये गये सभी कटौती के प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं जोरदार शब्दों में यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्लानिंग विभाग को बिलकुल एबालिश कर दिया जाय। इस लिये समाप्त कर दिया जाय क्योंकि किसी जमाने में जिस प्रकार रियासतों में पोल मशहूर थी उसी प्रकार इस विभाग में भी पोल हो गई है। जिस तरह से यहां पर ब्यूरोक्रेसी हर विभाग पर छा गई है और जिस तरह से इस विभाग में विकास के नाम पर रुपया लूटा जा रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं है। यह विभाग १ करोड़ रुपया खर्च करता है जिसमें से तीन चौथाई तो ब्यूरोक्रेसी के पेट में चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लानिंग का काम, इस विकास योजना का काम लेजिस्लेचर के हाथ में दे दिया जाय जो नजदीक से देहाती जनता, गरीब जनता की परेशानी और बुरी हालत को, उनकी तकलीफ को, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। ये कुर्सी पर बैठने वाले लोग, लम्बी तनख्वाह पाने वाले लोग और मजे उड़ाने वाले लोग कुछ भी पता नहीं रखते हैं कि देहातों की आज क्या दशा है। मैं मिसाल के तौर पर बतलाना चाहता हूं कि ५६-५७ में करीब ६।। करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया। उसको बचा दिया गया। मालगुजारी में ६१ लाख, सिंचाई में १७।, लाख गांव पंचायत में ८ लाख, जन स्वास्थ्य में ४५ लाख, चिकित्सा में २४ लाख, कृषि विकास में ५७ लाख, पशु चिकित्सा में ३४,६२,०००, सहकारिता में ३७ लाख, राजस्व से किये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यों में ४,८६,००० रुपया, दुर्भिक्ष, सहायता में ४३,९६,००० रुपया, समाज कल्याण में २४ लाख, विविध व्यय में १७ लाख, नियोजन में १,६९,००,००० रुपया, इस सब को जोड़कर ६।। करोड़ रुपया होता है जो बचाया गया है। मुझे इस बात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने कई विभागों के मन्त्रियों से बात की जिनका सम्बन्ध कृषि से है और उनका ध्यान दिलाया।

पच्छिमी जिलों की बहुत बुरी हालत है जहां पर गर्की और रेत के कारण बहुत जमीन बरबाद हो गई है। उत्पादन वहां घट रहा है जिससे लोग भूखे मर रहे हैं। देश की हालत खराब होती जा रही है। पश्चिमी जिलों के लिये ५८-५९ के बजट वर्ष में केवल ११।। लाख रुपया वाटर लागिंग की समस्या को दूर करने के लिये मंजूर किया गया। आप देखिये कि यह कैसा प्रश्न है शर्म आती है इसको देखकर कि एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। फिर लम्बे चौड़े बजट बनाये जांय और फिर यह बचत, यह क्यों ? अफसोस की बात है कि इस विकास के काम में १,६९,००,००० रुपया खर्च नहीं किया गया। आप प्लानिंग उन लोगों के लिये कर रहे हैं कि जिनका विकास पहले से हो रहा है। जो विकसित हैं उनका और बिकास कर रहे हैं। यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट की १९५७ की रिपोर्ट से है। इसके पहले पन्ने पर ही कहा गया है कि :

The Planning Commission, in their First Five-Year Plan, described community development as a "method through which the Five-Year Plan seeks to initiate a process of transformation of the social and economic life of the villages".

गांव की उन्नति के लिये प्लानिंग कमीशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा है कि देहात के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन विकास के लिये पंचवर्षीय योजना में उन्नति के मार्ग अपनाये जाते हैं और अब यह दूसरी योजना चल रही है । आज तक यह हमारी समझ में नहीं आया कि क्या विकास आपने किया है ? आपके आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि का उत्पादन घट रहा है और उसके साथ ही शहरों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और देहात की घट रही है । क्या यह विकास है ? सिवाय इसके कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं और यह कुछ नहीं है । यह व्यवस्था बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है । जो मिनिस्टर्स यहां बैठते हैं उनको कोई तजुर्बा नहीं है । (व्यवधान) हां, आयेंगे, जरूर आयेंगे और आप देखेंगे कि जल्दी ही आयेंगे । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर्स यहां बैठते हैं उनको कोई तजुर्बा नहीं है और वे सब इस ब्योरोक्रेसी के हाथ में खेल रहे हैं अपनी कमजोरियों की वजह से । वह अपनी आंखों से देख नहीं सकते, देखना नहीं चाहते । जनता के वह नजदीक नहीं जाना चाहते (व्यवधान) आप चिन्ता मत करिये । वह दिन अब नजदीक आ चुके हैं । आज प्लानिंग की अहमियत क्या है ? विकास का मतलब यह है कि जो लोग गिरी हुई दशा में हैं, जो गांव अविकसित अवस्था में हैं उनको उठाया जाय, उनका विकास किया जाय । मैं आज के मिनिस्टर साहबान से कहूंगा कि वे देहात में मिनिस्टरी का लेबिल लगा कर न जायं, जनसाधारण की तरह, जैसे विक्रमादित्य या अशोक अपनी प्रजा को देखने जाते थे, वैसे जायं और देखें कि उनकी आज क्या दशा है । अभी भी उनको एक टाइम रोटी नहीं मिलती । मेरे क्षेत्र की ही सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन पानी से डूबी हुई है । उसके बारे में वहां के इंजीनियर ने मुझ को बतलाया कि ४,२९,००० रुपये की वहां २५ ड्रेन्स बनाये जाने की योजना है, लेकिन सरकार कहती है कि रुपया नहीं है ।

एक और मिसाल देना चाहता हूं रबी और खरीफ कैम्पेन की । हम लोगों के पास मोहनलाल जी गौतम का एक लेटर पहुंचता है जिसमें अपील की जाती है विधायकों से कि आप उन जरूरतमन्द किसानों की जरूरत पूरी कराने के लिये बीज, खाद, पानी आदि का इंतजाम करायेंगे । काफी कुछ किया गया, लेकिन अफसोस है कि जब हम बी० डी० ओ० और डी० पी० ओ० साहबान के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है और तमाशा यह है कि उन सब विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है । प्लानिंग विभाग अलग विकास कर रहा है और रेगुलर डेवलपमेन्ट डिपार्टमेंट अपना अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई समझौता नहीं है । मैं मिसाल देना चाहता हूं कि अभी इस रबी कंपेन के समय पर मैं अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में मौजूद था । हजारों किसान जिनकी लिस्टें पटवारियों के जरिये बनवाई गयी थीं कि किसको कितने बीज की जरूरत है, अपनी अपनी बोरियां लिये हुए सीड स्टोरों पर बैठे हुए थे, लेकिन वह सब खाली हाथ लौट गये और बड़े किसानों को १०० और ५० मन बीज दिया गया । जिनके पास साधन थे, उनको बीज दिया गया लेकिन गरीबों को नहीं दिया गया । एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक आर्डर इश्यू होता है कि कोआपरेटिव फार्म्स को एग्रीकल्चरल, सीड स्टोरों से बीज दिया जाय, लेकिन ४, ५ और ६ दिन तक लगातार उनके स्टोरों में धक्के खाने के बाद जब यह नौबत आ गयी कि हम एक दाना भी यहां से उठने नहीं देंगे जब तक कि हमको बीज नहीं मिलेगा तब कहीं जा कर उनको बीज मिला और इसमें उनका खर्च कितना हुआ यह तो वे ही जानें । आप यहां प्लान बनाते हैं, सैकड़ों हजारों योजनायें हैं । आप देखें कि उन पर खर्च, उनके इस्टैबलिशमेंट पर खर्च कितना होता है । उसका कोई ठिकाना नहीं । विकास का तीन चौथाई रुपया बचाया जा सकता है अगर रेगुलर डिपार्टमेंट्स को यह काम दे दिया जाय और उनमें ईमानदारी से काम हो । कम से कम लूट तो नहीं होगी । रिहन्द डैम बन रहा है, करोड़ों रुपया गबन हो रहा है, ठीक से काम नहीं होता, तो यह क्या तमाशा है ? लाखों करोड़ों रुपया करोड़पतियों को दिया जा रहा है, कोई हिसाब नहीं । राज्य व्यापार की योजनाओं में जहां जहां आपके शेयर्स हैं उनके बारे में आपने कभी क्या यह बताया कि

[स्वामी विश्वेश्वरानन्द]

आपको कितना घाटा या मुनाफा हुआ है ? कभी नहीं । अब आप अन्न का व्यापार हाथ में लेने जा रहे हैं । पहले एक प्रोक्योरमेंट स्कीम १९४७-४८ में चली थी । उस समय किसानों से गल्ला खरीदा गया और उसमें जब वह छोटे छोटे अधिकारियों के हाथ में आया तो उन्होंने रेत और मिट्टी मिला दी । आंखों देखी बात है । आज भी हालत यही है । तो इसमें लाभ होने वाला नहीं है जनता का । मैं बड़े जोरदार शब्दों में अपील करता हूं कि आप इस प्लानिंग विभाग को खत्म कीजिये और इस काम को रेगुलर डिपार्टमेंट्स को दे दीजिये । वह खुद इस काम को अच्छी तरह से करेंगे ।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं इकोनामी के बारे में । इसी रिपोर्ट के पेज १५७ पर कहा गया है कि :

"About 50 per cent of the grants-in-aid in each block should be spent on productive purposes, the remaining 50 per cent on amenities. The limit is only suggestive and may be varied by the State for different areas according to local conditions".

मैं कहना चाहता हूं कि ५० नहीं ७५ फीसदी रुपया प्रोडक्टिव स्कीम्स में खर्च होना चाहिये । इसी तरह से इसमें यह भी कहा गया है कि ब्लाक्स से जीपें छीन लेनी चाहिये । इसी रिपोर्ट के १५८ पन्ने पर है :

"All jeeps should be withdrawn from the blocks, only exception can be a jeep for the Mukhya Sewika".

दूसरी चीज और है कि जो पब्लिकेशन के बारे में हैं:

"The publication of too many similar publications printed on expensive paper with necessary pictures and a number of articles irrelevant to the purpose needs careful re-examination by the Ministers concerned".

लेकिन मिनिस्टर साहबान नहीं देखते । चमकीले कवर्स होंगे और अच्छी अच्छी तस्वीरें होंगी । कीमती कागज पर वह छापे जायंगे । यह रिपोर्ट है कि जिस पर आपकी तवज्जह जानी चाहिये, मिनिस्टरों की तवज्जह जानी चाहिये, लेकिन उनकी तो फोटो छप गयी और वह खुश हो गये, यह होता है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मैं समझता हूं कि हर माननीय सदस्य ने अपने दृष्टिकोण से प्लानिंग के ऊपर अपने विचार कहे हैं । फर्क हो सकता है जानकारी में और जजमेंट करने में और असेसमेंट करने में । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश की प्लानिंग हुई और उसमें बहुत रुपया भी खर्च हुआ और हो रहा है, लेकिन यह हमारी मुसीबत है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को महसूस नहीं किया कि जिस मुल्क को हम प्लानिंग कर रहे हैं उसकी जहनियत, आदत, उसके कस्टम्स, उसकी प्रैक्टिस, उसका मोड आफ थिंकिंग और लिविंग और उसका रहनसहन कैसा है । किसी देश में किसी विचारधारा को जारी करने के लिये और उसका संचालन करने के लिये यह देखना होगा कि उस विचारधारा को पनपाने के लिये उस देश की स्वायल फर्टाइल है या नहीं; वह स्वायल है हमारा दिल, दिमाग, हमारी आदत, हमारा मेथड आफ लिविंग और थिंकिंग । विचारधारायें इंसानों और जानवरों की तरह ही पनपा करती हैं । मुझे दुख है कि हमारे देशवासियों ने इस प्लानिंग को दूसरे देशों से लिया और उसको यहां के लोगों पर लादा गया । उन देशों में संपत्ति थी, लेकिन पैदावार ठीक नहीं थी उनमें उपयुक्त भूमि थी, लेकिन वह भूमि बड़ी तादाद में कल्टीवेशन के अन्डर नहीं लो गयी थी । उस मुल्क में बड़े बड़े चरागाह थे भेड़ों के झुंड न थे । परन्तु इस देश में साधनों की नितान्त कमी है ऐसे देश में उस प्रकार की प्लानिंग को लादना, एक समृद्धशाली देश की प्लानिंग को एक

गरीब देश पर लादने से जो उसका नतीजा होगा, वह हमारे सामने है। जिन भाइयों ने गत वर्ष चुनाव लड़ा है वे इस बात को जानते हैं। हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपने अपने इलाकों में पहले इन कामों को खोला था इसलिये कि इन कामों से उनकी इम्पारटेंस बढ़ जायगी, जनता की सहानुभूति वह प्राप्त कर लेंगे, हजारों की तादाद में सीट्स जीत लेंगे, लेकिन उसका नक्शा हम लोगों के सामने है। जहां जहां यह प्लानिंग चली, जहां जहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चले, एन०ई०एस० ब्लाक्स इन्ट्रोड्यूस हुये, उन्हीं स्थानों में अक्सर कांग्रेस हारी है और बड़ी भारी तादाद में हारी है। इसमें दो रायें नहीं हैं। हमारे पास इसकी फिगर्स हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह उधार खाते की प्लानिंग हिन्दुस्तान में सफल नहीं हो सकती है।

प्लानिंग चलाने के लिये हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क की जरूरतें क्या हैं, अर्जेंसी क्या है। इन चीजों का ईमानदारी के साथ असेसमेंट करना होगा और उसका निर्धारण हमारे इन्टेलेक्चुअल केलीबर के ऊपर है। अगर हमने अपनी बुद्धि से ठीक प्रकार से काम नहीं लिया, गलती की, और जिस चीज को लोग चाहते हैं उस चीज को हमने प्लानिंग के अन्दर नहीं रखा तो मुल्क ऊपर नहीं उठ सकता। हमारे मुल्क में पहले खाने की और कपड़े की समस्या है। पेट से ही दुनियां चलती है। जिस मुल्क में पेट का इंतजाम नहीं होता, उस मुल्क में प्लानिंग बेकार ही है। आप नाच घरों में जायं, क्या भूखा नाच सकता है? आप खुशी मनायें, क्या भूखा खुशी मना सकता है? आप इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्या उसको भूखा अपने दिल से मना सकता है? आप उसको शराब पिला कर पागल बना दें, लेकिन वह दिल और दिमाग से खुशी नहीं मना सकता। आज हम आजादी के बाद अपने गरीब देश के अन्दर खाने पीने और रहने का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं। सरकार इन चीजों का प्रबन्ध नहीं कर पायी है। क्या आपने इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि आपने जो करोड़ों और अरबों रुपया खर्च किया है उससे हमारे प्रदेश में और देश में कितनी सुविधा लोगों को हुई, कितना सुख लोगों को हुआ? हमारे प्रदेश में और देश में जो प्लानिंग हुआ उससे बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी पूंजी बनायी, रुपया मारा, इसका सबूत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। कुछ दिन पहले जिन लोगों का कोई स्टेटस नहीं था, जो दर दर मारे फिरते थे, उन्होंने जनता की प्लानिंग को छोड़कर अपनी प्लानिंग कर ली। ये कल कारखाने जो चल रहे हैं कहां से चल रहे हैं, ये कहां से आये? ये कार और ऐश आराम की चीजें उन के पास कहां से आयीं? क्या आपने इन बातों का खयाल करने की कोशिश की है?

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे प्रकाश स्तम्भ थे, हमें अंधेरे से बचाते थे, उन्होंने अपने स्वार्थ से मुल्क को तबाह कर दिया, इसका हमें बड़ा खेद है। एक कहावत है कि हर व्यक्ति अपने लिये है और भगवान सब के लिये है। होना क्या चाहिये था? होना तो यह चाहिये था कि हम मुल्क के लिये होते और मुल्क हमारे लिये हो जाय। लेकिन आज इसका उल्टा हो रहा है। हर आदमी एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से काम करने को तैयार नहीं है। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनको सबसे पहले अपने क्षेत्र का विश्वास प्राप्त होना चाहिये था और उसके बाद उस काम को करना चाहिये था। लेकिन आज हिन्दुस्तान के रहने वालों का उनमें विश्वास नहीं है और आज हर व्यक्ति रुपया जमा करने के फेर में है। उसका कारण यह है कि जो हमारे मुल्क के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी अपने भविष्य के प्रति विश्वास नहीं है। वे नहीं जानते कि उनके बच्चे का इन्तजाम मुल्क करेगा इसीलिये वे धन इकट्ठा करते जा रहे हैं। वरना अगर वे समझते कि देशवासी उनके बालबच्चों का इंतजाम करेंगे तो फिर उनको रुपया, जमीन जायदाद इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वे यही समझते हैं कि अगर मैं हुकूमत में न रहा तो पौड़ी गढ़वाल में इंटर कालेज और डिग्री कालेज नहीं खुलेगा। वे अपने को इंडिस्पेंसिबिल समझते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि "नो बाडी इज इनडिस्पेंसिबिल

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

फार दि सोसाइटी" no body is indispensable for the society. । हमारे यहां मुश्किल है कि हमारे देश के जो नेता होते हैं वे समझते हैं कि बिना उनके मुल्क का काम नहीं चलेगा। उनका यह समझना गलत है। कोई भी व्यक्ति समाज के लिये ऐसा नहीं है जिसके बिना समाज न चल सके। अगर शैक्सपियर की खोपड़ी पर चोट मार कर उसे खत्म कर दिया गया होता तो भी सैकड़ों शेक्सपियर इंगलिस्तान में पैदा हो सकते थे। इसलिये मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि किसी व्यक्ति के न रहने से समाज का कोई काम रुक सकता है।

यह माननीय सदन जो इस उत्तर प्रदेश का भाग्यविधाता है वह प्रदेश के साढ़े ६ करोड़ व्यक्तियों का भाग्य निर्णय करने के लिये यहां बैठा हुआ है। मैं समझता हूं कि इस देश के रहने वाले जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको इस बात पर गौर करना होगा कि हम क्या हैं। इस मुल्क की हम झूठी तारीफ करने के लिये नहीं हैं। जो काम अच्छा है उसका हम स्वागत करते हैं, जो काम अच्छी तरह से नियोजित है उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं परन्तु मुझे खेद है कि हम भूल गये कि सबसे पहले बुद्धि नियोजित करने की आवश्यकता है। जब तक बुद्धि नियोजित न हो तब तक दुनियां का कोई कार्य संचालित नहीं हो सकता। इंसान पहले सोचता है और तब कोई काम करता है। पहले दृढ़ निश्चय करके ही कोई काम करना ठीक होता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री उग्रसेन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुदान भाषण को सुना जिसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। श्रीमन्, आज मैं सुबह से इस अनुदान पर बहस को सुनता रहा, लेकिन मैंने एक भी ऐसा सदस्य नहीं पाया जिसने इस योजना को सही बतलाया हो और इस तरह से भाषण सदन में हुये तो यह स्पष्ट बात है कि कोई बहुत बड़ी गलती योजना के मूल में ही है नहीं तो आखिर इस सदन के सदस्यों को संतोष क्यों नहीं है। यह सही बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है यह बहुत मासूम मालूम पड़ते हैं। जनता के चरित्र का विकास हो, सहिष्णुता बढ़े, स्वार्थ के बदले परमार्थ, संघर्ष के बदले सहयोग, यह होना चाहिये। लेकिन श्रीमन्, मूलभूत योजना कैसी हो और कैसे हो इस संबंध में एक भी विचार उन्होंने व्यक्त नहीं किया। मैं समझता हूं कि इन आलोचनाओं का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी देते हुए कह देंगे कि जिस तरह से बच्चा गिरता, पड़ता है, फिर आगे बढ़ता है उसी तरह से हमारी यह योजना भी है जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि योजना का सीधा अर्थ यह है कि प्राप्त साधनों को सुरक्षित रख कर और संभावित साधनों को प्राप्त करके उनको सामान्य जनता के भौतिक और मानसिक अभ्युत्थान के लिये नियोजित करने का नाम ही योजना है। अब अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो २,३ सवाल उठते हैं। क्या जो प्राप्त और संभावित साधन हैं वे योजना में लगाये गये हैं? अगर इस दृष्टि से देखा जाय, चूंकि माननीय उग्रसेन जी ने आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं, मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जितनी जमीन हल के नीचे है उसका भली प्रकार उपयोग किया गया, इंटेन्सिव कल्टीवेशन किया गया? नहीं। क्या जो जमीन कट रही है उसको रोकने के लिये सरकार ने कोई काम किया? जो जमीन बोने के लिये है और गरकी में आ गई, या पानी भरा है, उसको मुक्त करने के लिये कोई प्रबन्ध सरकार ने किया? आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो काम में नहीं लगे हुये हैं इन सब का खाने पीने और पढ़ाई का प्रबन्ध हुआ या नहीं? तो जितने साधन प्राप्त हैं, संभावित हैं उनका समुचित प्रयोग इस योजना में हो रहा है या नहीं, पहला सवाल तो यह है। अगर इस दृष्टि से देखें तो तमाम सदस्यों के विचारों से स्पष्ट हो जाता है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम ४३० आदमी बैठे हुये हैं उनकी आंखों से देखते हैं, अगर देखते तो मालूम होता कि योजना पूर्णरूपेण फेल हो गई है, किसी प्रकार की तरक्की नहीं हुई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी कह सकते हैं कि कुछ काम तो हो रहा है। श्रीमन्, जब अरबों रुपया देश का बरबाद हुआ और नगण्य काम दिखाई पड़े तो यह योजना नहीं हुई, विनाश हुआ। क्योंकि वह भवन है इसका भी विनाश किया जाय तो उसमें भी पैसा खर्च होगा। तो अगर विनाश करने में पैसा खर्च होता है उसी को विकास मान लें तो यह बुद्धिवि भ्रम ही है।

अब सम्भावित साधन क्या हैं ? हमारे यहां प्रदेश में ९०,००,००० एकड़ जमीन खेती के योग्य पड़ी हुई है। आज तक सरकार ने कोई अन्न सेना नहीं तैयार की है ? इसके तैयार करने पर बेकारी भी हल होती और खाद्य समस्या जो भीषण रूप से मुंह बाये हमारे सामने खड़ी है उसका भी समाधान होता, लेकिन सम्भावित साधनों का भी उपयोग इस प्लान में नहीं किया गया। इसी प्रकार मानसिक उन्नति के लिये क्या किया गया ? आखिर हमारे देश में पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं। प्रधान मंत्री ने कहा कि तृतीय योजना तक शायद कम्पलसरी ऐजूकेशन कर सकेंगे। अभी तक संविधान में १९६० तक लिखा हुआ था, लेकिन अब प्रधान मंत्री कहते हैं कि सन् १९६५ तक करेंगे। तो बातों से तो काम चलेगा नहीं। एक बहुत साधारण सी बात थी मनुष्यों की बेकारी की समस्या की। सबसे पहले आदमियों को खाना मिलता, इंटेंसिव कल्टीवेशन होता, लेकिन पानी का ही कोई प्रबन्ध नहीं, माताटीला की और कई योजनायें बिजली की ठप्प हैं। आखिर योजना हमारे देश में चलेगी कैसे ? मैंने उद्योग विभाग की बहस में कहा था कि जो हमारे साधन हैं उनका उपयोग और संभावित साधन पानी के अलावा हमारे देश में यूरेनियम काफी है जिससे ऐटामिक ऐनर्जी पैदा हो सकती है। तो वह तो दूर रहा, हाइडल से बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो जो साधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं फिर योजना से क्या तात्पर्य हो सकता है ? जो साधन प्राप्त हैं और सम्भावित हैं उनको उपलब्ध करने के लिये कुछ भी सरकार ने काम किया ? ऐक्सप्लायटेशन आफ रिसोर्सेज आफ दी कंट्री expoitation of resources of the country. के संबंध में सरकार ने कुछ नहीं किया।

कृषि को देखा जाय तो पता चलेगा कि लगातार तीन साल से पैदावार गिरती चली जा रही है, अन्न की समस्या सामने खड़ी है। तो विकास के नाम पर विनाश क्यों हो रहा है मुल्क का ? बेकारी कम नहीं हुई। फिर इसके अतिरिक्त श्रीमन्, आप शब्दों के प्रयोग से भी देखें, रबी और खरीफ अभियान चला। जैसे अशोक का कलिन्ग का अभियान था। तो मैंने समझा कि वास्तव में शब्द के रूप में ही काम चल रहा है। अशोक ने कलिंग पर अभियान किया। उसे परास्त किया। यह खरीफ और रबी पर अफसरों का अभियान हुआ और फसल चौपट कर दी। जैसा अभियान का भाव था वैसा कर दिया। शब्द का जो अर्थ है उससे मालूम पड़ता है कि क्या नियत है। खेती की उन्नति हुई नहीं। बेकारी की समस्या हल नहीं हुई। ए०डी०ओ० खेती की तरक्की क्या करेंगे। अगर ईमानदारी से सर्वे किया जाय तो मैं बता देना चाहता हूं कि जितने आफिसर खेती की तरक्की के लिये नियुक्त हैं उनमें मुश्किल से एक दो प्रतिशत आदमियों ने अपनी जिन्दगी में १०० घंटे से ज्यादा हाथ से खेती की होगी। वे खेती सिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर में जो बी०एस०सी० ए०जी० करते हैं वह केवल ४५ घंटे हाथ से खेती करते हैं। और वह उनको खेती सिखायेंगे जो जिन्दगी भर खेती करते रहे हैं। यह उल्टी गंगा बह रही है। एक अजीब तमाशा कर दिया।

श्रीमन्, मेरे पास बहुत शिकायतें आईं प्लानिंग विभाग की। बी०डी०ओज० वगैरह कुछ नहीं करते हैं, सब माननीय सदस्यों ने कहा है। श्रीमन्, अगर देश का निर्माण करना है तो नियोजन का जो अर्थ है कि रिसोर्सेज को काम में लावें, तभी काम होगा। यह जो प्लान है, यह तो आफिसर प्लान है, पीपुल्स प्लान है कहां ? जनता का जब प्लान है तो गांव सभा किस लिये है, जिला परिषद् किस लिये है, विधान सभा के सदस्य क्या कर रहे हैं ? पैसे

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

का जो वितरण होता है उसमें १०० रुपये में से ४८ रुपया आफिसर्स पर खर्च होता है। यह लोग करते क्या हैं? तरह-तरह की शिकायतें इनके संबंध में आती हैं। एक ए० डी० ओ० (डब्ल्यू) जिला देवरिया की शिकायत मेरे पास आई है, जिसमें उन्होंने बी०डी०ओ० के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर दिया है। इस तरह की शिकायतें बराबर आती हैं।

चौखम्भा राज्य ही एक साधन हो सकता है। हम पैसे का वितरण करें गांवों के द्वारा तो कार्य हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में विराजमान नहीं हैं। मैं उनसे निवेदन करता कि वह लेखपाल वगैरह के अलावा और कोई आफिसर हमारे यहां प्लानिंग का न रक्खें और गांव सभाओं को काम दे दें। एम० एल० एज० और एम०पीज वगैरह की देख-रेख रहे तो निश्चय ही तरक्की हो जायेगी। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस तरह जो शासन टाप टु बाटम हैवी हो गया है इसको खत्म करके योजना को जनता द्वारा चलाया जाय और खास खयाल रक्खा जाय कि दरिद्रनारायण की आवभगत होती है। उनका कुछ भला होता है या नहीं।

अगर इन तमाम दृष्टियों से हम योजना को कसौटी पर कसते हैं तो इससे कोई सफलता नहीं मिली है। इस योजना से भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश का चरित्र गिरा है। देश के पैसे को खींचकर उसका बड़ा भयंकर अपव्यय किया गया है। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन में भी बेकारी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि यहां आगे के नेताओं को ही बुलाया जाता है। जो नेता हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, सब को खत्म किया जाय क्यों कि जब अगले बैठने वाले भी खत्म होकर पीछे आ जायेंगे तभी हमारी बेकारी दूर होगी। मैं कई बार-७-बार खड़ा हुआ, लेकिन हमारी बात, कोई नहीं सुनता श्रीमन्, मैं दस मिनट बोलूंगा और यदि मुझे नहीं बोलने दिया गया तो सदन का परित्याग कर दूंगा। सब पार्टियों के निकम्मे नेता हैं, जो गरीब हैं बेकार हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठें आपको मौका दिया जायगा।

श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान योजना और एकीकरण के विषय में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आजादी के बाद जैसा कि अभी दोनों तरफ से कहा गया, देश की ऐसी परिस्थिति थी कि उसके लिये एक योजना की आवश्यकता थी और उस योजना की आवश्यकता को ही सामने रख कर कांग्रेस सरकार ने एक योजना बनाई और उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं। इन खामियों के भी कुछ कारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष---सदन में शान्ति रखें।

श्री सूरतचन्द रमोला---जिस सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान में हम चल रहे हैं वह जब बनाई जा रही थी और उसके लिये भिन्न-भिन्न जिलों से आंकड़े मंगाये गये थे, वह जब इकट्ठा किये गये तो पता लगा कि उस पर पैसा अधिक व्यय हो रहा है और इतने साधन सरकार के पास मौजूद नहीं हैं। जितने सरकार के साधन थे उसके अनुसार योजना में कटौती की गई। इसी कमी के कारण इस योजना में खराबी आई, वह आंकड़े जो घटाये गये वह काल्पनिक ढंग से कम किये गये और कुछ ऐसे मुख्य आइटम्स भी काटी गयीं जो काटी नहीं जानी चाहिये थी। इस तरह से प्रारम्भिक के स्टेज में ही कुछ खामियां रह गईं, लेकिन हमारा विश्वास है कि आगे तीसरी योजना में वह खामियां न रहने पायेंगी। समय कम है इसलिये विस्तार में न जाकर कुछ सुझाव देकर ही मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा।

पहली बात मुझे यह कहना है कि हमारे हिली जिलों में इस योजना का कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है। यहां तक कि पहाड़ों पर पहले जो टूरिस्ट्स जाते थे उन्होंने भी वहां जाना बन्द कर दिया है और सरकार भी जो पहले नैनीताल जाती थी वह भी अब नहीं जाती। मैं अर्ज करूंगा कि पहाड़ों के लिये ऐसा करना बड़े नुकसान की बात है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, मैं आशा करता हूं कि वह सरकार को आइन्दा हर साल नैनीताल ले जाया करेंगे जैसे पहले जाती थी। हमारी इस योजना के अधीन टूरिज्म डेवेलपमेंट कौंसिल की व्यवस्था हैं। यह पहाड़ों में टूरिस्ट्स के पहुंचने और उन के आराम के साधनों का प्रबंध करें, लेकिन वह कौंसिल्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं और उनका काम वहां पर सुचारु रूप से नहीं चलाया जा रहा है। अच्छा होता कि टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का रूप दिया जाता, जैसा कि काश्मीर में है। वहां पर जो ब्यूटी स्पाट्स अर्थात् सुरम्य स्थान हैं उनकी discovery होती है। प्रचारार्थ उसका लिटरेचर तैयार होता है और इंडस्ट्री का रूप उसे दिया जाता है, अगर ऐसा भी किया जाय तो मैं समझता हूं, कि वहां हजारों आदमियों को व्यवसाय मिल सकता है और रोजगार का रास्ता खुल सकता है कम पढ़े-लिखे लोगों की अनएम्प्लायमेंट की स्थिति सुधर सकती है। इस चीज को सुचारुरूप से चलाने के लिये प्रान्तीय रक्षक दल के लोगों को ट्रेन किया जाय तो इस कार्य को काफी प्रगति मिल सकती है। लेकिन प्रान्तीय रक्षक दल के बजट को देखा जाय तो १९५७-५८ में १९,४८,३८५ रुपया इसके लिये था और ५८-५९ में १८,८६,००० रुपया रखा गया और इस वक्त के बजट में १६ लाख रुपया। इस प्रकार इस बजट में हर साल कमी आती जा रही है और मुझे डर है कि कुछ दिनों के बाद इस बजट में प्रान्तीय रक्षक दल का नाम भी नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि प्लानिंग के काम में अगर किसी काम को किसी संगठन से प्रगति मिल सकती है तो वह प्रान्तीय रक्षक दल है। उसमें हमारे जो पुराने सिपाही हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सा काम किया है, वह घिसे-पिसे लोग हैं, अगर उनको पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ट्रेंड करने के बाद हम उनसे अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं।

दूसरे मैं स्पोर्ट्स के बारे में कहूंगा कि अगर सरकार ध्यान दे तो पहाड़ी जिलों में विन्टर स्पोर्ट्स जैसे हार्किंग और स्कीइंग अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करूं कि एक पिक्चर निकली है जिसमें पहाड़ों के दुर्गम स्थानों को दिखाया है और उसके देखने से जो आम लोग हैं उनको एक प्रकार की निराशा होती है कि उन पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, इससे इच्छुक पर्यटक वहां जाने में कतराते हैं, परन्तु अगर इन टूरिस्ट ब्यूरो के जरिये हम सुरम्य स्थानों का एक लिटरेचर बनायें और उन स्थानों के महत्व की ओर ध्यान दें और साथ ही आवागमन के रास्ते ठीक कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत आर्थिक फायदे की बात हो सकती है और बहुत सी इम्प्लायमेंट की दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय एक चीज और है कि जो बीज वितरण का सिस्टम है उसके लिये बहुत थोड़ी रकम रखी गयी है। दूससी बात यह भी है कि जो बीज मैदानों में चलता है वह पहाड़ों में दिया गया है। मैंने इसे खुद देखा। यह गलत चीज वहां कैसे हुई? इस की जांच होनी चाहिये। उससे किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। वहां पर सरकारी बीज जो दिया गया है उन खेतों में गेहूं बिलकुल नहीं उगा है और जहां पर किसानों ने अपने घर का बीज बोया है वहां फसल अच्छी है। टेहरी-गढ़वाल में गुसाई पट्टी में मैंने खुद देखा। इससे काश्तकारों की जो आस्था है सरकार की ओर या विभाग की ओर खासतौर से वह दिन पर दिन घटती है और यह समझते हैं कि ये एक प्रकार का ढोंग रचते हैं और हमको धोखा देने के लिये यह सब काम करते हैं। श्रीमन्, हमारे जिले के एक एम०एल० ए० श्री रामचन्द्र उनियाल के गांव में तो बीज तब गया जब वहां के खेत बोये जा चुके थे। तो इतनी देर से काम किया जाता है।

सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहाड़ी प्रदेश में सब से पहले सड़कों का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है। जब तक वहां सड़कों का निर्माण नहीं हो जाता

[श्री सूरतचन्द रमोला]

तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिये नियोजन और पी०डब्ल्यू०डी० विभाग में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। हमने इस साल यहां दो, एक जीपे एबिल रोड्स पी०डब्ल्यू० डी० के सहयोग से बनवायी हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी से जल्द से जल्द इन सड़कों को पी० डब्ल्यू०डी० के चार्ज में ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके लिये कोई अनुदान पी०डब्लू०डी० से नहीं दिया गया तो ये सड़कें बेकार हो जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने उन मित्रों की राय से सहमत नहीं हूं जो आज नियोजन और नियोजन विभाग की आवश्यकता को ही नहीं समझते। आज नियोजन का अपना महत्व है और इसी महत्व के नाते चाहे पूंजीवादी देश हो या समाजवादी, सभी ने नियोजन को एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है और राष्ट्र के जीवन में ही नहीं मेरा तो अपना मत है कि मनुष्य के निजी जीवन में भी बगैर नियोजन के कोई तरक्की सम्भव नहीं है।

जब आज हम नियोजन और विकास के इस अनुदान पर विचार कर रहे हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष को हम समाप्त कर चुके हैं उसमें जिन उद्देश्यों को उद्घोषित किया था, जिन लक्ष्यों को हमने सामने रखा था आया उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल हुये हैं या नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बतलाते हुये यह कहा गया था कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय का अधिकाधिक वृद्धि करना है जिससे देश के रहन-सहन के स्तर को उठाया जा सके और जिसके अधीन जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अनियमितता को मिटाया जा सके और लोगों की आय में असमानता को घटाया जा सके। जब हम इस उद्देश्य को सामने रख कर इस अनुदान पर विचार करते हैं तो हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमने इन उद्देश्यों को हासिल करने में पूर्णरूप से असफलता प्राप्त की है। सन् १९५५--५६ में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब हमने शुरू की थी तो हमारे प्रदेश की कुल आय १,७६५ करोड़ रुपये थी। सन् १९५६--५७ में, योजना के दूसरे वर्ष में यह आय घट कर १,७३९ करोड़ रह गयी और तीसरे वर्ष में १,६९२ करोड़ हो गयी। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश की जो हमारे देहात की आय थी वह भी १,०८८ करोड़ से घट कर १,०७८ करोड़ रह गयी। इसी प्रकार से शहरी जीवन की आय घटी। प्रति व्यक्ति भी हमारी आमदनी गिरी इसको हम इस सदन में पहले भी कह चुके हैं।

दूसरा उद्देश्य जो हमारे सामने था कि हम अपने प्रदेश की बेकारी को दूर करेंगे तो सन् ५५ में हमारे प्रदेश में कुल ३,२१,९७७ बेकार आमदियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वहां सन् ५६ में उनकी संख्या बढ़ कर ३,३६,४,४० हो गयी और सन् १९५७ में बढ़ कर ३,४३,६६३ हो गयी।

दूसरी तरफ प्रतिवर्ष खर्च करने के लिये नियोजन और विकास विभाग को जितना रुपया दिया गया वह विभाग उस रुपये को भी खर्च करने में असफल रहा है। सन् १९५६--५७ में हमारा लक्ष्य था कि ४८.१७ करोड़ रुपया खर्च करेंगे लेकिन हमने खर्च किया केवल ४०.६७ करोड़ रुपये। सन् १९५७--५८ में हमारा लक्ष्य था ५२.८० करोड़ रुपये खर्च करने का, लेकिन हमने खर्च किया ४५.७६ करोड़ रुपया और तीसरे वर्ष ४६.६६ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य था, लेकिन उस रुपये को भी खर्च करने में संदेह प्रकट किया गया है। तो श्रीमन् हम देखेंगे कि जो उद्घोषित लक्ष्य थे उनको हासिल करने में हमारा नियोजन और विकास विभाग पूर्णतया असफल रहा है।

आज इस अनुदान पर विचार करते समय हमें गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये क्योंकि इन तीन वर्षों के अनुभव पर हमें अपने भावी विकास की योजनायें स्थित करनी हैं। श्रीमन् इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जब से प्लानिंग शुरू हुआ हमारे प्रदेश

का विकास हुआ। सड़कें अधिक बनीं स्कूल अधिक खुले, अस्पताल अधिक निर्मित हुये, ब्लाक्स खुले, लेकिन इनके बढ़ने से ही इस नियोजन का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मैं मुख्य मंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि किसी भी देश के नियोजन का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है कि हम सामाजिक विषमताओं को दूर करें, उसका लक्ष्य होता है कि हम अपने राष्ट्र की परम्पराओं के अनुसार अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, उसकी प्रतिभा के अनुसार नागरिक पैदा करें। यदि हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें उत्साह नहीं प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि हमारे राष्ट्र के अन्दर जनता का उत्साह नियोजन के साथ नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिये कि क्या कारण है कि आज हम जनता को इस नियोजन के साथ उत्साहित नहीं कर पाये हैं? मुझे मुख्य मंत्री जी की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य हुआ था जिसमें उन्होंने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी कि हमारी जनता में नियोजन के साथ उत्साह नहीं है। यह ऐसा गम्भीर विषय है कि जिस पर हमें सोचना चाहिये और अन्वेषण करना चाहिये।

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की उन दो घोषणाओं का स्वागत करता हूं। उन्होंने बताया था कि देहातों में वह कृषि समितियां बनायेंगे। उन समितियों का एक लक्ष्य होता होगा जिसको प्राप्त करने के लिये हम आगे बढ़ेंगे। विकास समितियां जो हैं उनके लिये एक अरसे से मांग थी कि उन्हें पूर्णाधिकार दिये जांय और केवल सलाहकार समितियों का ही उनका दर्जा न हो ताकि वह जो योजनायें बनायें उनके मुताबिक हम आगे बढ़ें। लेकिन केवल इन समितियों का नाम बदल देने से ही वह लक्ष्य हासिल नहीं होगा इससे सभी सहमत होंगे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां हम कृषि की उन्नति के ऊपर विचार करते हैं तब श्रीमन् हमें इस बात को देखना चाहिये कि आज क्या कारण है कि हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़ती नहीं है। आज क्या कारण है कि इन नियोजन के ८ सालों के बाद भी हमारे प्रदेश के सामने एक खाद्य संकट उपस्थित है। इसका मुख्य कारण यह है कि कृषि के अन्दर जो क्रान्तिकारी भूमि सुधार होना चाहिये था वह आज तक नहीं किया गया। कृषि के अन्दर जब तक मूल परिवर्तन नहीं होता है, जब तक हमारे देहातों के अन्दर सामन्ती और अर्द्धसामन्ती प्रथायें चल रही है जब तक जिनके चंगुल में आर्थिक व्यवस्था थी उनके अवशेषों को समाप्त नहीं किया जाता, जब, तक काम करने वालों के हाथों में सत्ता नहीं जाती है तब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि प्लानिंग कमीशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह कहा था कि हमें क्रान्तिकारी भूमि सुधार करना होगा, हमें जमीन की हदबन्दी करनी होगी और जमीन का बटवारा करना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि कृषि विकास की तरफ बढ़ना है तो उन सुधारों को हमारे राज्य के अन्दर लागू करना चाहिये, छोटे-छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना चाहिये और उनको संरक्षण देना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने गत वर्ष इस बात की घोषणा की थी इस सदन में कि इस कार्य के लिये वे अलग विभाग खोलना चाहते हैं ताकि छोटे-छोटे उद्योगों का संरक्षण हो सके। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १ वर्ष बीत गया और वह विभाग अलग से क्यों नहीं खुला, उसमें क्या कठिनाई है?

तीसरी बात यह है कि मेरा अपना मत है कि इन प्लानिंग की योजनाओं से हमारी गरीब जनता लाभ नहीं उठा पाती है। जितना आगे बढ़ा हुआ समाज है वही लाभ उठा लेती है। इसके लिये आवश्यकता आज इस बात की है कि देहात की जनता का आर्थिक आधार पर वर्गीकरण होना चाहिये और इकोनोमिक ग्रुप बनाया जाय और प्राथमिकता उसको दी जाय जो सब से गरीब हो, जो शोषित हो, जो दबा हुआ हो समाज का और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये जो सब से पिछड़े हुये हों। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक कदम उठाया गया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूर्वी जिलों के लिये एक योजना बनाई गई है, बुन्देलखंड के लिये बनाई है जो स्वागत करने के योग्य है। यह कदम सरकार का बढ़ा है और बहुत मजबूती के साथ बढ़ाया गया है।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्रीमन्, सरकार द्वारा जो रबी अभियान और खरीफ अभियान शुरू किये गये हैं, उनके लिये शोर तो बहुत मचाया गया है और जितनी लम्बी-चौड़ी सफलता की बात कही गई है वस्तुतः उतनी सफलता तो नहीं मिली है। फिर भी यह दोनों बहुत अच्छे हैं और हमें इनका स्वागत करना चाहिये, इनको आगे बढ़ाना चाहिये। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि इनको मास मूवमेंट देनी चाहिये। पिछली बार मैंने नैनीताल में स्टैंडिंग कमेटी में माननीय मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव दिया था कि इन अभियानों को एक मास मूवमेंट की शक्ल दी जानी चाहिये और जनता को इनके नजदीक लाया जाय ताकि जनता इनको चलाना अपना कर्तव्य समझे और जनता के दिलों में एक सच्चा उत्साह पैदा हो। इसके लिये बड़ी-बड़ी मीटिंग्स को जायं और लोगों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लिया जाय। मुझे खुशी है कि वह मेरे सुझाव से सहमत भी हो गये थे। मैंने निवेदन किया था कि इस तरह की मीटिंग्स से काम नहीं चलेगा बल्कि जैसे पोलिटिकल पार्टियों की मीटिंग्स होती हैं उस तरह से होनी चाहियें और गांव के मेलों में होनी चाहिये। इस शक्ल में इस आन्दोलन को चलाया जाय तो सफलता हो सकेगी।

श्रीमन्, आखिर में मुझे एक शब्द सरकारी अधिकारियों के बारे में भी कहना है और वह यह है कि जिस प्रकार से आज कल इनका रिक्रूटमेंट होता है उसको नीचे से लेकर ऊपर बिल्कुल बदल दिया जाय ताकि सही माने में जन-सेवक रखे जा सकें।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे केवल ५ मिनट का समय दिया है उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। लेकिन ५ मिनट में मैं क्या कह पाऊंगा? अगर मेरी बात का तनिक भी इशारा मुख्य मंत्री जी तथा उनके मंत्रिगण सोच लेंगे तो मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा और समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल हुआ।

श्रीमन्, प्लानिंग के ऊपर यह एक सरकारी पुस्तक "अवर प्लान" के नाम की है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से केवल दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :---

Objects and Approach

"Increased production and reduction of the existing inequalities are the two main objectives of the plan".

अब श्रीमन् देखा जाय कि इंक्रीज आफ प्रोडक्शन की हालत क्या है? इसके सम्बन्ध में मुझे कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि देवरिया और लखनऊ के माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और इसके अलावा उधर से भी यह बात मानी गई है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घटा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ और हमारा प्रोडक्शन घटा। अब दूसरी बात देखी जाय कि इनइक्वेलिटी घटी या बढ़ी। तो श्रीमन्, इनइक्वेलिटी (inequality) घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है जो हमारे पूंजीपति हैं उनका धन और करोड़ों बढ़ा है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी है कि पर कैपिटा इंकम घट गई है।

अब श्रीमन्, ११ वर्ष के बाद प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिये जाने के बाद अब हमारे नेहरू जी ने इस बात को महसूस किया है कि खेती भी एक बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है। हमारे मंत्रिगण कब तक हमको सेल्फ सफीशेंट बना पायेंगे इसमें हमें सन्देह है और शायद इनको १,१०० वर्ष लगेंगे। जब हम कहते थे कि हमारा प्रोडक्शन घटा है और खेती में नुकसान हुआ है तो उधर से बराबर यही फरमाया जाता था कि घटा नहीं है। यह लोग झूठ बोलते हैं और चीप प्रोपेगेंडा करते हैं और जब फंस जाते हैं तो कहते हैं कि दैवी प्रकोप के कारण ऐसा हो गया। हम क्या करें?

"दैव दैव".... केवल आलसी पुकारता है यह गोस्वामी तुलसीदास जी कह गये हैं।

श्रीमन्, एक बात हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह फरमाई कि हमको सेंटर से केवल दो करोड़ रुपया मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम पर कब और कैसे लाठियां बरसावें इसमें जितना समय खर्च होता है वह यदि इसमें लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता। आज केन्द्र में हमारे उत्तर प्रदेश के कितने ही लोग हैं, पं० जवाहरलाल, पंत जी, हाफिज जी, अजित-प्रसाद जी, शास्त्री जी--उनसे कुछ रुपया लेकर ज्यादा क्यों नहीं लाते? यह कहना कि केवल दो करोड़ रुपया ज्यादा मिला है यह काफी नहीं है। एक बात यह भी कि हमारे प्रदेश में दो जातियां विशेष हैं और वह हैं तराई में थारू और पहाड़ में बोक्सा। इनके उत्थान के लिए अगर मेरे सुझाव का कोई असर हो तो निवेदन है कि उनके लिए पाइलट प्रोजेक्ट और कोआपरेटिव बैंक सिस्टम स्थापित किये जायं।

टूरिस्ट्स के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज जो कहा उसको सुन कर अत्यन्त प्रोत्साहित हुआ। उसका एक कारण यह है कि टूरिस्ट्स सिर्फ बर्फ देखने के लिए नहीं आते। आपके यहां जंगलों की एक बड़ी भारी सम्पत्ति है वाइल्ड लाइफ, जो टूरिस्ट्स को आकर्षित करती है। इस सम्बन्ध में आपके प्रदेश में केवल एक संस्था है वैसे दो संस्थाएं हैं एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है और एक यू० पी० की है, वैसे दोनों यू० पी० की हैं, लेकिन टेक्निकली केवल एक है। इसको आप जरा सा प्रोत्साहित करें। रुपये से नहीं। लेकिन उनको सहूलियत दें। उनको सहूलियत अभी तक कैसे हुई? एक उनका हाथी खत्म कर दिया गया। कहा कि पागल हो गया है और मार डाला। कुत्ते पागल होते थे, हाथी पागल होते मैंने नहीं देखा। मस्त जरूर होते हैं। फीलवान मौजूद था। लेकिन गोली मार दी गयी। अगर थोड़ा सा भी फर्क होता तो गोली फीलवान को ही लग जाती। अगर सुरथबहादुरशाह से गोली चलती तो ३०४ का मुकदमा चलता। लेकिन चूंकि उनकी मण्डली ने मारा तो कहा गया कि हाथी पागल हो गया था। आखिर को अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे दिन आकर थाने में मार डाला गया। अगर इसी तरह से प्रोत्साहन मिलेगा टूरिस्ट्स कंसर्न्स को तो टूरिज्म की उन्नति हो चुकी।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पांच मिनट का मौका दिया है। आज उपाध्यक्ष महोदय, १४ मार्च, १९५९ है। १४ मार्च, १९४८ को सेवा-ग्राम में मैं प्रथम सर्वोदय सम्मेलन में अपने साथी व सहपाठी रामप्रताप शर्मा के साथ गया। वहां मुझे पास मिल गया। देश देशान्तर के कर्मठ ऋषियों की मण्डली मैंने देखी। पं० नेहरू, मरहूम अबुल कलाम आजाद और राष्ट्रपति हमारे देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। वहां पर यह तय हुआ कि हम इस देश की गरीबी, तथा बेकारी और निरक्षरता को दूर करेंगे। यही हमारी श्रद्धाञ्जलि पूज्य बापू जी की शहीदात्मा के लिए होगी। विनोबा जी ने, जयप्रकाश जी ने वह रास्ता अपना लिया और वह जो सेवा कर रहे हैं विश्व में अमर हो गये हैं। उसी लक्ष्य, आधार के ऊपर हमारी पंचवर्षीय योजना बनी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हम आजाद हुए थे तो दो अरब मन केवल गेहूं हमारे देश में कम था। अलावा इसके हजारों लाखों आदमी जो पाकिस्तान से भाग कर आये हुए थे वह देश में बेघरबार पड़े हुए थे। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री की कार्यपरायणता ने हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा रखा। आज उन शरणार्थियों के लिए रोजी, रोटी, घर, मकान सब मौजूद है। यह गर्व की बात है। प्रकृति के भयंकर कोप का मुकाबला करते हुये अपने निर्धारित रास्ते पर हम चलते चले जा रहे हैं। हमारी योजनाएं बनती हैं। उनमें कमियां हैं, वे विदेशों की खर्चीली योजनाओं पर आधारित हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम इस बात को भी देखें कि हमारे विश्वामित्र जी ने क्या किया था? उन्होंने अनुसंधान करके मकरा, सावां, कोदों, काकुन वगैरह, नये अनाज पैदा किये। जंगली धान से धान की सैकड़ों जातियां उन्होंने पैदा कीं। जई जौ से कई नये अनाज बनाये, फलों के ऐसे वृक्ष पैदा

[श्री नारायणदास पासी]

किये जैसे कि आम जो १२ मास फलता है, अमरूद जो दो-दो मर्तबे फलता है, कटहल जो बारहों महीने फलता है, सरवती घास से कितने गल्ले बनाये तो वह भी एक तरह के अनुसंधान के आश्रम थे और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हैं तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

आज हमारे यहां क्या हो रहा है? प्लानिंग के अन्दर आफिसर्स बैठेंगे तो कहेंगे कि अमोनियम सल्फेट डाल दो, सुपर फास्फेट डाल दो खेतों में। इस तरह की खाद डालने से जमीन की भूख नहीं मिटने वाली है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि लखनऊ शहर को देख लीजिए। लखनऊ के अन्दर उस कूड़े से मल मूत्र से हजारों मन खाद रोज तैयार हो सकती है, लेकिन वह सब बेकार गोमती नदी में जाती है। कानपुर ने हमें इस ओर रास्ता दिखाया है, ७० लाख रुपया खर्च करके उसने मनुष्य के मलमूत्र का उपयोग करने की ओर कदम उठाया है। इसी तरह प्रदेश के सभी नगरों को कदम उठाना चाहिये क्योंकि जब तक यह कम्पोस्ट खाद धरती को नहीं मिलती है तब तक आपका उत्पादन नहीं बढ़ सकता।

आज काम करने वालों की हालत को देखिए, वे सर्दियों के सताये हैं, अब वस्त्र नहीं हैं, उनके पास खेत नहीं हैं। उनकी हालत में एक शेर में कहता हूं--

रंज का खूंगर हुआ इन्सां तो मिट जाता है रंज,
मुश्किलें इतनी पड़ीं मुझ पर कि आसां हो गईं।

यह दशा है गरीब समाज की। मैं श्रीमन्, दो मिनट और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आपके दो मिनट और हैं।

श्री नारायणदास पासी--दूसरी चीज देखिए कि हमारा गोवंश है, भैंस वंश है, सूअर वंश है, भेड़, बकरी वगैरह का वंश है। ये हमारे बहुत ही उपयोगी पशु हैं। इस अमूल्य पशुधन को लोग मार कर नाश कर रहे हैं, खाये जा रहे हैं। इनसे हमको दूध, घी, खाद आदि मिलता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, उनके चरणों की रज लेकर प्रार्थना करूंगा कि वेदों में देखें। वे वेद वेदांगों के बड़े विद्वान् हैं, वेदों में इनके बारे में लिखा है--

धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादपि महीयसी।
गोर्मे माता वृषभः पिता मेदिक्यमशर्म जगती में प्रतिष्ठा।

और बैलों के लिए कहा है--

वृषो अहि भगवान धर्मस्चतुष्पादः प्रकीर्तितः।
वृणोभिवत त्वामहं भक्तस्था सा, मा रक्षतु सर्वदा।

यह हमारे वेदों में दिया है। अतएव समय की मांग है कि प्रदेश के कीमती पशु धन की रक्षा होनी चाहिये और इन सबका वध बन्द होना चाहिये।

जब तक अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं की जायगी, बुनियादी चीजों को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक इन अंग्रेजी भाषा में बात करने वालों से सूट बूट पहन कर गरीब देहातियों में चलने वालों से न हमारा प्लान बनेगा, न हमारा उद्धार होगा, न हमारे राज्य का स्तर ऊंचा हो सकेगा। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कह कर के जो उधर हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने क्रिटिसिज्म किया उसको देखते हुए और हमारा खाद्यान्न का प्रोडक्शन घट रहा है उसे देखते हुये ऐसे कठिन वक्त में माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि कम से कम प्लान के दिनों में अगर प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता तो घटना तो नहीं चाहिए था। इस बात पर जरा गौर से विचार करें और ऐसे वक्त में श्रीमन् जब हमारा प्लान दूसरों के ऊपर मुनहसिर हो, कर्ज का रुपया लाकर उसको

चला रहे हों तो उस समय जो प्लान बने उसमें नाच गाने के ऊपर खर्च हो यह कुछ शोभा नहीं देता। इस समय तो उसे कुछ दिनों के लिए तब भी कम से कम टाल देना चाहिए।

दूसरी बात, एक उदाहरण महाभारत का यहां दिया गया, मैं दूसरा उदाहरण महाभारत का ही देता हूं कि रणभूमि में जाने से चक्रव्यूह में पड़ कर अभिमन्यु खुद खत्म हो गया। तो इसमें जरूरी है कि बहुत जरूरी जो काम हैं उन्हीं पर रुपया खर्च किया जाय। फिजूलखर्ची न की जाय।

इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मोटरें हैं। मैं अर्ज करूंगा कि जीपें ब्लाक्स से वापस ले ली जायं। अगर विकास अधिकारी पैदल चलेंगे तो वे देहात के लोगों से ज्यादा मिल सकेंगे और देहातियों से उनके विचारों का आदान-प्रदान ज्यादा हो सकेगा। तब हमारी योजना ज्यादा सफल हो सकेगी।

दूसरी तरफ श्रीमन्, आप देखेंगे कि एक जगह एक बांध बनने वाला था तो पत्थर की जगह ईंटें लगाई गईं। इसके बारे में प्रश्नोत्तर भी हाल ही में इस सदन में हुआ। ऐसे कच्चे निर्माण कार्य न किये जायं। ऐसे ही जिले अल्मोड़े में जब भूचाल आया, श्रीमन् के द्वारा माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि उसमें सब से पहली बिल्डिंग जो टूटी वह विकास की थी, कप कोट कम्युनिटी प्रोजेक्ट में बनी थी। तो यह क्या बात है, इसकी जांच होनी चाहिए ?

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात यह है कि सरकार को चारों तरफ की अपनी प्रजा को देखना चाहिये। यही नहीं कि इधर ही देखती रहें, सरकार को पहाड़ वालों की भी खबर लेनी चाहिये। अभी श्री चन्द्रजीत जी ने सुझाव दिया कि नैनीताल में बैठ कर, उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था। दरअस्ल ठंडे दिमाग से अच्छा काम हो सकता है। अस्तु गर्मी में सरकार को वहां जाना चाहिये तथा गढ़वाल और अल्मोड़े से भी सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए। वहां पर भी इसी प्रकार से ठंडा पुर शान्त इलाका है।

इसके अलावा मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारी प्लानिंग जो हो रही है वह इटावा के प्रोजेक्ट के आधार पर की गई है। वह पहाड़ के लिये फिट नहीं आती है। मैं अर्ज करूंगा कि पहाड़ों की ऊंचाई के मुताबिक वहां प्रोजेक्ट खोल कर तजुर्बा किया जाना चाहिए। मैदानी पैटर्न के प्रोजेक्ट जो वहां पर खोले जाते हैं वह चलते नहीं हैं। यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है जब कि पहाड़ पर सर्दी ज्यादा होती है। जैसे बाढ़ के माने यहां पर गांवों व जमीन में पानी भर जाने के होते हैं जिससे बचने के लिये गांवों को ऊंचा करना होता है। मगर पहाड़ के गांव तो वैसे ही ऊंचे होते हैं। वहां बाढ़ से जमीन कट व बह जाती है न कि पानी से ढकी रहती है। वहां पानी से गांवों व पहाड़ गिर जाते हैं। मैंने राजस्व मंत्री जी से मांग की थी कि परिभाषा में उन गांवों को भी शुमार किया जाय जहां पर बाढ़ से जमीन या पहाड़ टूट या बह जायं। वह बात यहां वालों की समझ में नहीं आती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां के लिये अलग तरीके का पायलेट प्रोजेक्ट होना जरूरी है।

आजकल सरकारी रवैया यह हो रहा है कि उसने हर जगह औरतों को मर्दों के बराबर कर दिया। मैं यह समझता हूं कि औरतों को कहीं वी० एल० डब्लू० बना कर न भेजा जाय। जब भगवान् ने ही ऐसा किया है तो आप मर्दों और औरतों को बराबर नहीं बना सकते। अगर अकेली जवान औरतों को गांवों में भेजा जायगा तो इससे खतरा ही है।

मेरी गुजारिश यह भी है कि पहाड़ों के लिये जो नई करीब ३ करोड़ की स्कीम बनाई है उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं। जैसे कि चम्पावत से खेती खान को एक मोटर सड़क बनाने का प्रस्ताव है। वह सड़क न बन कर खेतीखान--मोरनौला को सड़क से जोड़ दिया

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

जाय। मोरनौला जिसे पहाड़पानी से जोड़ा जा रहा है इस तरह नैनीताल से जुड़ जायगा। इससे वहां की जनता को बहुत लाभ होगा। इसको नैनीताल मोटर सड़क से जोड़ने से अल्मोड़ा और नैनीताल का मार्ग जुड़ जाता है। इसी तरह से बाड़े छीना—बेणीनाग सड़क का भी बनना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीमावर्ती सड़कें हैं। इससे बोर्डर का संरक्षण होगा।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि पानी को वहां पर रोका जाय। इससे जो बाढ़ आती है वह भी नहीं आयेगी। वह पानी बाढ़ के लिये नहीं आयेगा। वहां पर रुका रहेगा। वहां पर उससे पनबिजली भी बन सकती है। उससे बिजली पैदा होगी तो प्रदेश में जो बिजली की कमी है वह पूरी होगी। वह सारा पहाड़ी एरिया अच्छा हो जायगा और गर्मी में पानी भी प्रदेश के काम आयेगा। हमारे प्रान्त में जो बेतहाशा बाढ़ आने लगी है उनका अधिकांश पानी कुमाऊं के पर्वतों से आता है। सारे प्रदेश को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिये काली, सरयू, कोसी अलखनन्दा, पिंडर में बांधों का बनाना जरूरी है। अल्मोड़ा में जहां पर टूरिस्ट्स नहीं जाते हैं वहां पर इस वजह से नहीं जाते हैं कि वहां पर रहने की कोई सुविधा नहीं है। वह गरीब इलाका है लोगों की कोई आमदनी नहीं है। वहां पर उद्योग धन्धे भी नहीं हैं। इस वजह से इस बेकारी को दूर करने के लिये वहां पर कुछ उद्योग करना जरूरी है टूरिस्ट्स भी तब वहां पर जायंगे। टूरिज्म पर वहां अधिक खर्च करने की जरूरत है। अब तक वहां कुछ नहीं किया गया।

देहात में पहले गरीब आदमियों की बहुत मदद की जाती थी। हमारे यहां यह भारतीय संस्कृति में देहात के रहने वाले और खास कर गरीबों की बहुत मदद की जाती थी। एक दूसरे की लोग सामूहिक रूप से मदद करते थे। किसी ने घर बनाया तो दूसरे ने उसमें सहयोग किया। पर अब ऐसा नहीं है, दिन पर दिन सहयोग कम हो रहा है। यह सहयोग भावना क्यों कम हो गई इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पहले जो देहाती बच्चा गांव में भैंस की पीठ कर चढ़ कर उसे चराता था आज भी उसी तरह वह भैंस चरा रहा है। आप की योजनायें उसे भैंस की पीठ से नहीं उतार सकीं। यह आप देहात में जाकर देखें। इस पर विचार करने की जरूरत है कि किसान मजदूर कैसे तरक्की करेगा।

जहां तक नया प्लान बनाने की बात है वह नया प्लान सब लोगों के सहयोग से हर स्तर पर बनाया जाय और हर स्तर पर सभी दलों की समितियां सुझाव के लिये बनाई जायं। लोगों से उसके लिये सुझाव लिये जायं और तब यह तीसरी प्लान बनायी जाय। जहां तक माइनर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स की बात है, यहां आपने बड़ा सुन्दर किया कि छोटे कुओं की बड़ी योजना बनाई, लेकिन पहाड़ में छोटी गूलों और डिग्गियों के लिये रुपया बहुत कम है, उसे ज्यादा रखा जाय। साथ ही टेक्निकल स्टाफ भी ज्यादा रखा जाय, जैसे योजना बनाने के लिये ओवरसियर ही नहीं मिलता है तो रुपया लैप्स हो जाता है। कुओं के लिये तकावी आधी न रक्खी जाकर पूरी रक्खी जाय। क्योंकि हर किसान के पास बकाया आधा जमा करने को हर वक्त रुपया न होने से वह उस आधे मिले रुपये को भी और मदों में खर्च कर देता है।

श्री टीकाराम पुजारी—अध्यक्ष महोदय, सदन में जो जिक्र चल रहा है वह मैं अच्छी तरह से २ घंटे से सुन रहा हूं। मैं तो बहुत परेशान हूं। सब चीजें बनावटी आ रही हैं। कोई टिकाऊ चीज नहीं है। टिकेगी तब जब कि पहले हम टिक सकेंगे। ग्राम पंचायतों का नक्शा बदलना होगा। उनमें वे पुश्तैनी गुलाम दरगुलाम हैं, जो तीसरे नम्बर के होते हैं, वही हैं। उनके निकलने के बाद किसान और मजदूरों के लड़के ४०, ५० वर्ष के जो हल चलाना, मेड़ बनाना और खेती करना जानते हैं, वे उनमें आवेंगे तो ग्राम की जनता का भला होगा। उनमें से सभापति, पंच और सरपंच बनने चाहियें। जब तक पुश्तैनी गुलामों को अलग नहीं किया जायगा कोई योजना सफल नहीं होगी। किसानों के लड़कों की कमेटियां होनी चाहिये। अमरीका, रूस और जापान की नकल यहां नहीं हो सकती। वे सर्व मुल्क हैं और

हमारा गर्म मुल्क है। वहां की खाद हमारी जमीन के माफिक नहीं पड़ेगी। नहरों से जो हजारों बीघे जमीन रेह होती जा रही है उसे रोकना होगा। सादाबाद तहसील में हजारों बीघे में पानी भरा हुआ है, नाला नहीं निकाला गया। फिर वर्षा होने वाली है। बहुत से किसानों के लिये खरीफ और रबी के आन्दोलनों में कुछ पैदा नहीं होगा।

एक हमारे यहां कुश्ती होती है। पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। हनुमान ने लंका जलाई, ऊदल ने कितनी बीरता दिखाई और अंगद ने पैर जमाया और राममूर्ति ने छाती पर हाथी चढ़वाया। हमारी देवियां भी ऐसा करती थीं। जनतंत्र में जो संख्या बढ़ रही है वह भी स्त्रियों के व्यायाम से नहीं बढ़ेगी। --

दिन दूजे का हो बारी, चौथे दिन होय अनारी,
प्राणी षटरस गमन करे, छठे दिन गमन होय, चोर होय, काहू ते न डरे।
बीज आठवें दिवस पड़ै सीप के बीच, सब समझे बोदी भली, सोबत बैठे नीच।
इंद्री दस में गमन करे, ठाकुर होय सिर पै ताज धरे,
पुरुष दिन बारह में आवे, नारि सुत पहलवान जावे,
विद्या के दिन चौदहवें साधि के धर्म करे अतिकर्म, सेज बिछवावे,
जब रहे नारि के गर्भ गुनी सुत पावै।
राजा होइ झूंठि मत मानो, गरभ सोलहवें दिन को,
रुति पै सिंगार बदन कौ।

अब जरा एक मिनट और, श्रीमन्! बहुत जरूरी बात--

स्वान नहिं देंगे काम बैठिके राकेट मांहि,
बानर विहीन वीरता न दिखायेंगे,
अमरीका पूंजीवाद, पूंजी जोरने में मस्त,
पूंजीवाद पूंजी से न कभी विजय पायेंगे।।
कथनी और करनी में कोई नहिं भेद होगा,
सत्य और अहिंसा के शस्त्र को उठायेंगे,
कृषकों के बेटे रुई धुनि के बनावें पौनी,
चन्द्रमा की माता पर चरखा चलवावेंगे।।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से थोड़ा समय मिल गया, इसके लिये मैं आभारी हूं। वैसे तो सुबह से ही इस विषय पर बहस हो रही है तथा आप और यह सदन जानता है कि यह मद बहुत ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण मद है। क्योंकि इस देश का भविष्य और इस देश की गरीबी का निवारण इस देश की उन्नति इसी मद पर निर्भर करती है।

हमें प्रसन्नता है कि आज इस विभाग का संचालन, उसकी नीति-रीति ऐसे प्रकांड समाजवादी विद्वान और महान व्यक्ति के हाथों में है जिसकी ख्याति इस प्रदेश की जनता में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि संसार में है। इस पर बहुत से साथियों ने बहस की और बिना इस लिहाज के कि इन पिछले ७-८ सालों में कितना कार्य हुआ है एक ही दृष्टि से आलोचना कर डाली। इस प्रकार की आलोचना इस सरकार के साथ में ही नहीं बल्कि इस देश और प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। आज हमें मालूम है और अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि हमारे यहां पैदावार कम है, अन्न की कमी है और प्रदेश के हर व्यक्ति को और हर जन-सेवक को यह चीज खटकती है।

मगर उसके साथ ही साथ यह भी एक मान्य बात है कि इस सरकार ने पिछले दिनों में जो जो प्रयास किये हैं चाहे वह काश्तकारों की खाद के रूप में हो, बीज के

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

रूप में हो या सिंचाई की योजना के रूप में हो, उनको भूला नहीं जा सकता है । इस सिलसिले में मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल इस सरकार ने और उसके कर्मचारियों ने अपने दिमाग से परिश्रम द्वारा एक नवीन योजना का प्रादुर्भाव किया जो आज रबी और खरीफ आन्दोलन के रूप में हमारे यहां चालू है । मुझे इस पर गर्व होता है कि यह नवीन योजना इस प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही बल्कि देश की सरकार ने दूसरे प्रांतों के लिये भी इसको एक आदर्श के रूप में अपनाया है । साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आगे भी इस मुसीबत को दूर करने के लिये प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर हम गर्व करते हैं । आज हम यह कहने में नहीं चूकेंगे कि अभी खरीफ की फसल आने में बड़ी देर है, लेकिन इसी योजना के तहत में जो हमारे प्रदेश के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसे ऊंचे चरित्र और लगन के व्यक्ति आज इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिये मिले हुए हैं । वे अभी से इस कार्य में लगे हुये हैं ।

श्री सूरथबहादुरशाह---वे कौन है ?

श्री रामेश्वरप्रसाद---आपको जानना चाहिये कि आपका डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है और अगर आप इतना भी नहीं जानते तो मैं समझता हूं कि आप जनता की हकतल्फी करते हैं । तो आज मैं देखता हूं कि सरकार उस कमी को दूर करने के प्रयास में लगी हुई है । आज प्रदेश की जगह-जगह का पूरा नक्शा इस बात का बना हुआ है कि कहां कहां काम होना है । पहली योजना में जो कमी रह गयी थी उसको दूसरी योजना में पूरा करने की कोशिश की गयी है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का कोआपरेशन मिले ।

इसके अलावा श्रीमन्, तीसरी योजना की तैयारी भी होने लगी है और इस सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि अभी तीसरी योजना शुरू होने में दो साल बाकी हैं, फिर भी स्टेट प्लानिंग बोर्ड ने अभी से तीसरी योजना की स्कीमों पर विचार करना शुरू कर दिया है और विभिन्न तरीके अपनाये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का कोआपरेशन मिले ।

साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस सरकार की योजना काफी लचीली है और अगर कहीं दायें बायें से राजनारायण जी का या और किसी का सुझाव आता है तो उसका का भी खयाल रखा जाता है । श्रीमन्, इसका सबूत है कि बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जो भी सुझाव दिये प्लानिंग के जरिये उसका पालन करने की कोशिश की गयी है । मैं यह बतला देना चाहता हूं और यह बतलाते हुए मुझे हर्ष है कि इस सरकार ने बहुत सी बातों को काफी पहले अपने दिमाग से निकाल कर, सोच कर किया । इसकी मिसाल में बतलाना चाहता हूं कि २० मई से २४ मई, सन् १९५८ तक माउंट आबू में देश के प्लानिंग थिंकर्स की एक बैठक हुई तो उसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा कोआपरेशन पाने के लिये अगर ऐसा हो कि ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नान आफिशियल हो तो बहुत अच्छा है । ज्यादा कोआपरेशन मिल सकता है । और आप देखें तुरन्त ही यह लागू हुआ और ब्लाक्स ऐडवाइजरी कमेटीज के चेयरमैन नान-आफिशियल्स होते हैं, एक गांव का सभापति उसका चेयरमैन होता है और एस० डी० ओ०, तहसीलदार बी० डी० ओ० आदि गजटेड आफिसर उसके मातहत बैठकर सारे प्लान्स बनाते हैं ।

मैं बताऊं कि जहां यह भी इश्यू कन्सीडर किया गया कि पावर्स के डिसेन्ट्रेलाइजेशन के लिये यह जरूरी है कि प्रदेशों में, गांव गांवों में पंचायतें आर्गेनाइज की जायं । तो मैं कहना चाहता हूं यह चीज जहां माउन्ट आबू की मीटिंग में मई, १९५८ में सोची गई, लेकिन मुझे कहते हुए गुमान है कि इस प्रदेश ने उस सुझाव के आने के पहले प्रत्येक गांव में गांव पंचायत बना दी थी । तो यह बातें टाली नहीं जा सकतीं । आलोचना का अख्तियार है, करना चाहिये, लेकिन जो काम हैं उनका भी मूल्यांकन होना चाहिये । जन-सहयोग, जो हमारी और सभी की धारणा है, उसके लिये और प्लान्स को पब्लिक के लिये प्रिय बनाया जाय

इसके लिये माननीय गोविन्द सहाय जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी हुई है और हमें उम्मीद है कि जो भी कमी होगी प्लान में, उन्होंने बड़े पैमाने पर गांवों तक जा कर सर्वे किया है वह दिग्दर्शित होंगे और साथ ही साथ जो सुझाव होंगे जन-सहयोग अधिक प्राप्त करने के बारे में वे उस कमेटी से मिलेंगे । सरकार चाहती है कि जिस दिशा से भी प्रेरणा मिले, जन सहयोग प्राप्त हो उस दिशा से वह लेने के लिये तैयार है ।

अन्त में मैं यह कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस सदन के सहयोग से सरकार को बल मिले और जो इरादे हैं समाजवादी व्यवस्था लाने के जो लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति हो । और तभी हम समझते हैं जो समाजवादी व्यवस्था का प्रयत्न हम कर रहेहैं, गरीबों की सेवा का नारा दे कर यहां आये हैं, वह हमारी मंजिल पूरी होगी ।

श्री उग्रसेन––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस विवाद में खुलकर हिस्सा लिया । मैं भाषण सुनता रहा और एक आध सदस्य को छोड़कर सभी ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया, इसकी मुझे प्रसन्नता है । यह बात दूसरी है कि अनुशासन के कारण हाथ दूसरी ओर उठावें, लेकिन समर्थन में सभी ने खुल कर भाषण दिये, इसलिये मैं आभारी हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि संघर्ष की जगह पर सहयोग से काम लें । व्यक्तिगत संघर्ष की जहां तक बात है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से जहां तक वर्ग संघर्ष की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि मिश्रित आर्थिक व्यवस्था में, और कोई भी सोशलिस्ट जो अपने को समाजवादी कहता है, बिना वर्ग संघर्ष के रास्ते को लिये आगे नहीं चल सकता । इसी लिये सोशलिस्ट पार्टी ने श्रीमन्, आज के हिन्दुस्तान के पैमाने में, आज के वातावरण में जो नारा दिया है सिविल नाफरमानी का, वह गरीबों को ऊपर उठाने के लिये दिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों प्लान्स में जनता के हाथ उत्पादन और वितरण की शक्ति आई ? श्रीमन्, अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की कि प्राइस स्टेबिलाइजेशन के लिये "प्राइस कमीशन" होना चाहिए । हमारे यहां इसके द्वारा लूट मची है ।

श्रीमन्, यह सही है कि हमारे मंत्री जी और प्लानिंग डिपार्टमेंट योजनाओं से देश को आधुनिक बनाना चाहते है । लेकिन अमेरिका में औसत एक उद्योग में १५ से २० हजार, रूस में १० से १५ हजार की लागत है और हमारे यहां २५० रुपये से ज्यादा नहीं है । अगर श्रीमन्, मान लिया जाय कि पांच में से दो आदमियों को धंधा देना है तो २७०० अरब रुपये की जरूरत होगी देश को ऊंचा उठाने के लिये और नियोजित करने के लिये । तो सरकार को तीन सौ वर्ष लगेंगे नियोजन करने के लिये । यह कैसी योजना है ? मैं मानता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी विदेश के कुश्चेव का और दूसरों का मुकाबला करते है, नकल करते हैं । करोड़पतियों का मुकाबला टाटा, बिड़ला करते हैं, लेकिन क्या यहां का भंगी वहां के भंगी के बराबर हो सकता है ? यूगोस्लेविया का भंगी और बड़ा आदमी एक ही तरह के क्वार्टर में रहते हैं । अगर देश में पैसा भी कर दिया जाय तो भी देश की गरीबी मिट जाय, पर कैपिटा इंकम बढ़ जाय यह जरूरी नहीं है । यह सब नियोजन पर मुनहसर करता है । अमेरिका में काफी पैसा है । क्या अमेरिका में बेकारों का आंदोलन नहीं रहता है कि 'डोल' बढ़ा दिया जाय ? क्या वहां पर लोग शिकागो में पी कर पड़े नहीं रहते ? अभी छपा था कि इंगलैंड में बेकारी बढ़ रही है । यहां पर जो योजना है, वह बेकार रही है । सोशलिस्ट पार्टी का कहना है कि प्रदेश की कमर टूट जायेगी ।

[श्री उग्रसेन]

पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिये योजना बनी, कार्यान्वित नहीं हुई। गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमेटी बैठी, हाई पावर कमेटी कि बाढ़ क्यों आती है। उन्होंने फाइंडिंग दी कि सरजू, घाघरा नदी बाढ़ का कारण है। प्रदेश की सरकार ने कहा कि घाघरा को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा बहुत लगेगा। मैं जानता हूं कि घाघरा की तह में रहने वाले हजारों लाखों की तादाद में बे-घरवार हो गये। उसकी योजना क्या है ? १५ करोड़ की योजना है राप्ती की। जल कुन्डी की नैपाल बांध योजना है। बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में भी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि कम से कम जमीन सरकार से निर्धारित हो जानी चाहिए। सरकार अब जमीन निर्धारण की बात करती है नागपुर कांग्रेस के बाद। मैं कहना चाहता हूं कि एक परिवार के पास एक हल बैल से जितनी खेती होती है उसकी तिगुनी से ज्यादा खेती किसी के पास न रहने पावे। माननीय माल मंत्री जी ५०, ६० और ७० बीघे की बात करते हैं। दूसरे १००-१०० एकड़ की भी बात करते हैं।

बलवंतराय मेहता कमेटी ने लिखा है कि फैलो लैंड को तोड़ा जाय। क्या यह होता है सरकार की सहायता से ? बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट में कैटिल इंश्योरेन्स की बात है। कैटिल का भी इंश्योरेन्स होना चाहिए, वह क्यों नहीं होता ? मैं पूछना चाहता हूं कि जानवरों का क्या उपयोग है ? मेरा चार्ज है सरकार पर कि जानवरों की जो गणना कराई गई वह लेखपालों से कराई गई, उस में हुआ यह कि अगर गांव में एक गड़रिया रहता है तो उसने लिख दिया कि ३५ भेड़ें हैं। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी तरह से कुमायूं विकास बोर्ड है, माननीय गोविन्द वल्लभ जी जब मुख्य मंत्री थे तब उस का निर्माण हुआ था, लेकिन कोई विकास पहाड़ों का नहीं हो पाता है और कुमायूं के लिये कोई स्कीम नहीं है। एक बात और यह कहना है कि १५ अगस्त और २६ जनवरी को बहुत से ब्लाक्स नये खुलने वाले थे और उन के लिये वी० एल० डब्लूज० को ट्रेनिंग भी दी गई थी, लेकिन वह नहीं खोले गये, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका जवाब दें कि वह ब्लाक्स क्यों नहीं खोले जा सके ?

एक बात मैं कहूंगा कि यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के आर्डर्स हैं कि जिस जिले से यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आयेगा वहां पर उतनी ही रकम कम कर दी जायगी। हमारे यहां का विकास विभाग अपने लाडले लोगों से यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं मांगता और वह सालों नहीं दिया जाता और नतीजा यह होता है कि जो पैसा मिलना चाहिये वह उन को नहीं मिल पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी कोई सहूलियत पैदा करने की कृपा करेंगे।

कुओं की बात कही जाती है। अभी तक दो पंचवर्षीय योजनाएं खत्म होने वाली हैं और उन में २२-२५ अरब रुपया खर्च करने की बात है, इतने में अगर सब को पानी पीने की भी व्यवस्था कर दी जाती तो हम समझते कि रामेश्वरलाल जी ने बड़ा काम करा दिया, लेकिन दिल्ली जाना हो तो कलकत्ते का टिकट नहीं कटाया जाता, आज सैंकड़ों आदमी पानी बिना मर गये। बरमा में ८६ प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं, लेकिन हमारे यहां आज भी लोग निरक्षर हैं। रात्रि पाठशालायें हैं, लेकिन उन से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। हमारे यहां शिक्षा की हालत यह है कि जो वाइस चांसलर हैं उन को २५०० रु० वेतन दिया जाता है और मामूली अध्यापक को २५-३० रुपया मिलते हैं, जो परिश्रम करने वाले हैं उनको २५ रुपया और वाइस चांसलर को २५०० रुपया, कहां का न्याय है ? सरकार ने विषमता को मिटाने के लिये तो क्या उस को कम करने के लिये ही कोई कदम उठाया ? यह भी कुछ नहीं हुआ। मेरा कहना यह भी है कि विकास जिन लोगों के लिये किया जा रहा है उन का भला नहीं हो रहा है। काफी सरकारीकरण हो रहा

है, सारे सर्कुलर्स अंग्रेजी में होते हैं और जनता उनको नहीं समझ पाती । ब्लाक एडवाइजरी कौंसिलों की बात कही गई वह भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जो अधिकार हैं वह ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर को हैं और उनका कोई काम नहीं होता है । इस तरह से कैसे नियोजन हो सकता है ?

एक बात स्पोर्ट्स या खेलों के बारे में भी कहूंगा । हमारे यहां स्पोर्ट्स कौंसिल है । उस में तमाम लोग बड़े-बड़े अफसर ५–६ सौ रुपया वेतन पर रखे जाते हैं और जो बार-बार दिल्ली और बाहर जाने में पैसा खर्च करते हैं और तुर्रा यह है कि टेनिस पर २,००० रुपया व्यय होता है और कबड्डी पर २०० रुपया। पूंजीपतियों के खेल पर हजारों रुपया व्यय होता है और तमाम भत्ते बनते हैं इस तरह का खेलों का विकास हो रहा है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह खासतौर से मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि नियोजन में जो खामियां हैं उनके दूर होने से प्रदेश का बड़ा लाभ हो सकता है ।

नियोजन उप-मंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम मेम्बर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्लानिंग के सिलसिले में अपनी तकरीरों के जरिये से मुख्तलिफ किस्म की तजवीजें दीं और उनके सजेशंस हमारे पास आये । मेरे लिए इस थोड़े से वक्त में यह तो शायद मुमकिन नहीं होगा कि मैं हर एक सुझाव के बारे में कुछ जवाब दे सकूं, लेकिन इतना मैं जरूर यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव आये हैं चाहे इधर से या उधर से, उन सब के ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे और जो कुछ मुनासिब होगा उसे जरूर करेंगे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग के सिलसिले में जब हम कोई बात सोचें तो उससे पहले हमें एक बात माननी पड़ेगी और वह यह है कि हमारे मुल्क के अन्दर जो प्लानिंग है इसका तरीका दूसरे मुल्कों से जरा मुख्तलिफ है । यों तो प्लानिंग चीन में भी हो रहा है, रूस में भी हुआ, लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर जो प्लानिंग हो रहा है वह बिलकुल वालंटरी है और एक नया तजुर्बा है जो हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं । यह जरूर है कि इसमें कमियां होंगी, लेकिन वह इसी तरह से दूर हो सकती हैं कि हम सब एक जगह बैठ कर उन पर गौर करें और उनको दूर करने की कोशिश करें ।

आज की दुनिया एक बदलती हुई दुनिया है । आजकल विचारधाराएं रोजाना बदलती हैं, हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं इसलिए प्लान में भी मुनासिब तरमीमें की जाती रही हैं और अगर जरूरत पड़ी तो की जायंगी । यही वजह थी कि बलवन्त राय मेहता कमेटी ने जब इस प्लान के ऊपर गौर किया तो उन्होंने कुछ तजवीजें दीं जिनको सरकर ने मान लिया और उन पर अमल कर रही है ।

कहा गया कि इस प्लान में ज्यादातर आफिश्यलडम है, आफिसर्स के हाथ में काम होता है, मगर जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने बहुत कुछ कदम आगे रखा है कि हम अपनी तमाम ऐक्टिविटीज को डिसेंट्रलाइज़ करें और सरकारी हाथ कम से कम करके जनता के हाथ में उस काम को बढ़ाने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर जो हमारी ब्लाक ऐडवाइजरी कमेटीज़ पहले थीं जिनको अब हमने ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज़ का रूप दिया है उनको एक स्टेट्यूटरी सूरत दी है और उनका चेयरमैन भी गैर-सरकारी बना दिया है । वह इस बात की शाहिद हैं कि हम इस तरफ कदम उठा रहे हैं । अगर हमारा कदम बावजूद कुछ कमियों के सही तरफ उठ रहा है तो हमदर्दी के साथ उस पर गौर किया जाय और मुनासिब सलाह-मशविरा दिया जाय ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जैसा कि कहा गया है, यह पीपिल्स प्लान है और इसके अन्दर सब लोगों का मशविरा शामिल कर दिया गया है और वह मशविरा ब्लाक और डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर और स्टेट लेविल पर भी शामिल कर दिया गया है। किसी के मशविरे को शामिल करने का मंशा यह नहीं होता कि प्लान एक आदमी या एक पार्टी के डिक्टेशन से बनायी जाय। आज दुनिया मानती है कि हिन्दुस्तान का प्लान एक कौमी प्लान है और इसको पूरा करने के लिये सरकार ने जो बीड़ा उठाया है उसको वह पूरा करने के लिए हर तरह से तैयार है।

मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही, उसी सिलसिले में अगर यह भी कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि वह कदम जो इस तरह का उठाया गया है अंतरिम जिला परिषद् की तरफ वह वाकई हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जा रहा है। ब्लाक का जहां तक ताल्लुक है हमने यह फैसला कर दिया है कि जब कभी भी यह सवाल सामने आये कि हमारे ब्लाक्स के क्वार्टर्स कहां लोकेट हों, उसके मुताल्लिक कोई और सलाह-मशविरा देने की जरूरत हो तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी और उसके साथ-साथ अंतरिम जिला परिषद् की राय भी हम जरूर मालूम करें। और जहां तक हो सके उसकी राय पर अमल करने की हम कोशिश करें।

जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने जब भाषण दिया और आपको बहुत वजाहत के साथ बतलाया कि हमारा मौजूदा प्लान ५७.५० करोड़ का है और इस साल का प्लान जो हम बनाने जा रहे हैं उसको बड़ी कोशिश के साथ ५० करोड़ रुपये का हमने रखा है। अभी कुछ साथियों ने यह शिकायत की कि पिछले साल १ करोड़ ६९ लाख रुपये की बचत हो गयी तो ऐसा प्लान बनाने से क्या फायदा कि रुपया रखा जाय और फिर बचत कर दी जाय। मैं जानता नहीं कि कहां तक यह मुनासिब होगा कि अगर रुपये के खर्च की जरूरत नहीं है या जिस काम के लिये रुपया खर्च किया जा रहा है उसमें कोई दिक्कतें और दुश्वारियां ऐसी आती हों जिनसे वह रुपया न खर्च हो सकता हो तो भी हम ख्वामख्वाह खर्च कर दें। अगर ऐसा किया जाता तो फिर यह एतराज़ हो सकता था कि यह रुपया बेजा तरीके से क्यों खर्च किया गया। सभी को मालूम है कि हमारे प्लान को पिछले साल स्टैगर किया गया और जितने ब्लाक हमको मिलने वाले थे उससे बहुत कम मिले जिसकी वजह से हमारा कुछ रुपया बच गया और वह रुपया हम आइन्दा दूसरे काम पर खर्च करेंगे।

इसके अलावा अक्सर इस सदन में यह सवाल भी उठाया जाता रहा है कि जो विलेज लेविल वर्कर्स हमने ट्रेन कराये हैं उन सबको जगह नहीं दी। मैंने कई मर्तवा इस ऐवान के सामने इस बात का जिक्र किया और आज उसे फिर दोहराना चाहता हूं कि इस प्लान के स्टैगर होने की वजह से हमारा प्लान बहुत धीमा पड़ गया और हमने इस बात की कोशिश की कि जितने लोगों की खपत हम अपने यहां कर सकते हों करें। इसके अलावा कृषि विभाग में, सहकारी विभाग में पंचायत सेक्रेटरी की जगह पर उनको रखने की कोशिश की। यह भी किया गया कि जो लोग पाबन्द हो गये थे कि ट्रेनिंग के बाद तीन साल तक सर्विस करें उनके ऊपर से वह पाबन्दी उठा ली गयी कि अगर उनको कोई दूसरी जगह मिल सके तो वहां चले जायं। बहरहाल, जो कुछ इमकानी तौर पर किया जा सकता था वह सब कुछ किया गया और जो आइन्दा भी किया जा सकता है वह किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि जब कभी भी कोई प्लान बनाया जायगा तो उसमें कुछ न कुछ प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। यों तो हमें अपने देश और और प्रदेश की तरक्की के लिये बेशुमार रुपये की जरूरत होगी और वह रुपया हम एक साथ नहीं ला सकते इसलिये हमें अपने काम को एक प्लान्ड तरीके पर ले जाना पड़ेगा

और हर काम के लिये प्रायोरिटी मुकर्रर करनी पड़ेगी । जाहिर है कि हमारे जैसे सूबे के अन्दर जिसकी एकोनामी बिल्कुल ऐग्रीकल्चरल एकोनामी है हम किसी तरह से भी कृषि को नजर-अन्दाज नहीं कर सकते और हमारे पहले प्लान में उस पर इसीलिये काफी जोर दिया गया था। दूसरे प्लान में यह सही है कि हमने कुछ एम्फैसिस इंडस्ट्री के ऊपर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कृषि के ऊपर हमारा जो एम्फैसिस था वह अब भी कायम है और उससे पीछे हम हटे नहीं हैं । एक माननीय सदस्य ने सन् १९५७–५८ के कुछ आंकड़े दिये और बताया कि हमारी पैदावार घट रही है । उन्होंने जो आंकड़े दिये उनको मैं मानता हूं, लेकिन उन माननीय सदस्य को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वह साल ऐसा था कि जब नैचुरल कैलैमिटीज़ हमारे उपर बराबर आयीं और हर किस्म की आफतें आती रहीं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन घटा । मैं उनकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमने शायद इस मुल्क के अन्दर पायनियर बन कर इस बात की कोशिश की कि हम ऐसा आन्दोलन चलायें जिससे हमारी पैदावार बढ़े और इसीलिये हमने पहला एक आन्दोलन खरीफ का चलाया और उसके बाद दूसरा रबी का आन्दोलन चलाया और अब तीसरा खरीफ का आन्दोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह—खुदा न करे, और घट जायगा ।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जो खरीफ का आन्दोलन चलाया गया अभी कुछ साहबान ने इस बात की शिकायत की कि हम इस तरफ कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों के अन्दर एन्थूजियाज्म बढ़ायें, लोगों को प्लान की तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करें। मैं उनकी खिदमत में यह आंकड़ा पेश करना चाहता हूं कि रबी के ड्राइव में हमने तय किया था कि हम ढाई लाख ग्राम सेवक ट्रेन्ड करेंगे परन्तु हमने उसके बजाय ३,०८,६६३ आदमी ट्रेन्ड किये । इन्होंने जो काम किया वह ऐसा नहीं है जिसको हम कहें कि वह काबिल कदर नहीं है । उन्होंने काबिल कदर काम किया और उन्होंने बड़ी कोशिश की और उनकी वजह से खरीफ की पैदावार ११·१३ फीसदी बढ़ गयी । जापानी तरीके से खेती करने से सौ फीसदी पैदावार बढ़ी और इसके अलावा यू० पी० मेथड से व्हीट कल्टीवेशन हुआ उससे १२५ फीसदी पैदावार बढ़ी ।

एक सदस्य—वह पैदावार कहां चली गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैंने बड़े सब्र और जब्त के साथ अपने दोस्तों की तकरीरें सुनी अब मैं अगर यह ख्वाहिश करूं कि जो मैं अर्ज करूं वह खमोशी से सुन लिया जाय तो कोई बेजा नहीं होगा । तो यह कहा गया है कि हमारे यहां पैदावार नहीं बढ़ी, तरक्की नहीं हुई यह नहीं हुआ है और वह नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि हम अपने दिलों में यह भी टटोलें कि इस पैदावार के बढ़ने में, इस मुल्क को तरक्की देने में और डेवलपमेंट को अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिये हमने क्या किया ? उसमें हर शख्स का फर्ज है कि हम अपने यहां की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करें । मैं यह पूछता हूं कि जहां तक इस नियोजन का ताल्लुक है मैं यह नहीं कहता कि हम में से सब साहबान ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन हमने उतना हिस्सा नहीं लिया जितना हमें लेना चाहिये था । हम जानते हैं कि हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर और हमारा स्टाफ बराबर घूमता रहा और कोशिशें करते रहे उनसे जितनी भी कोशिश हो सकती थी उन लोगों ने की, लेकिन हम सब लोग भी अगर अपनी-अपनी जगह पर कुछ थोड़ा सा असर अपने काम में लाते और इसकी तरफ तवज्जह करते तो मुझे यकीन है कि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकते थे ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

एक बात इस मौके पर मैं यह अर्ज कर दूं तो कुछ बेजा न होगा और उसमें भी आप सब साहबान का सहयोग हासिल करने की कोशिश करना चाहिये और वह यह है कि पैदावार बढ़ाने की तरफ तो हम बराबर तवज्जह करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमें इस बात को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी पैदावार के ऊपर और हमारे स्टैंडर्ट आफ लिविंग पर काफी असर पड़ सकता है। यह हकीकत है कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हमारे मुल्क में ५० लाख आदमी हर साल बढ़ जाते हैं और उत्तर प्रदेश में करीब १० लाख आदमियों का इजाफा हर साल हो जाता है। तो सवाल यह भी है कि इस प्लानिंग के जरिये और दूसरे तरीकों से हम जो कुछ भी पैदावार बढ़ायें, लेकिन अगर हमारी आबादी की रफ्तार इसी तेजी से बढ़ती गई तो हम शायद कभी भी इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आज हमारे सामने सवाल यह है कि हम बाहर से अरबों रुपये का गल्ला मंगाते हैं। इनके साथ-साथ बहुत सी मुसीबतें आती हैं। पांच हजार फेयर प्राइस शाप्स हमको खोलनी पड़ीं। इसके अलावा और बहुत से काम करने पड़े। स्टेट ट्रेडिंग का मसला हमारे सामने आ रहा है और मुझे यकीन है कि हमारे सब साथी उसमें अपना सहयोग देंगे। कोआपरेटिव फार्मिंग और सर्विस कोआपरेटिव्ज आ रही हैं। हम सब लोगों से इस बात की अपील करेंगे कि वे अपना पूरा सहयोग दें।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---आपने फेमिली प्लानिंग के बारे में क्या नतीजा निकाला ?

श्री अध्यक्ष---अब हर एक का जिन बातों में कुतूहल है उन सब बातों का जवाब तो इतने थोड़े वक्त में नहीं हो सकता।

श्री सुल्तान आलम खां---मैं अर्ज कर रहा था कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत की वजह से हम अपनी काटेज इंडस्ट्रीज को जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं वह हमारा इरादा पूरा नहीं हो पा रहा है। आज हमें शिकायत होती है कि हमारे सूबे में इंडस्ट्रीज काफी नहीं मिल रही है और यह सही है, अगर्चे हमारे मुख्य मंत्री जी की कोशिश से रिहन्द डैम आ गया और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का ऐक्सपेंशन हो रहा है। उसके लिये किसी न किसी तरीके से रुपया हासिल करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी हमारे सूबे का इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, चाहे वह काटेज इंडस्ट्रीज में हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज में हो, जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल यह आता है कि अगर हम पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं तो गल्ले के मसले को भी हल नहीं कर सकते हैं, तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारा फारेन एक्सचेंज गल्ला बाहर से मंगाने में ही खर्च हो जायगा। कोई भी सरकार इस बात को गवारा नहीं कर सकती है कि अगर लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो तो वह बाहर से गल्ला न मंगाये बल्कि मशीनें मंगाने में फारेन एक्सचेंज सर्फ करे। यह बहुत बुनियादी सवाल ह और इसमें बहुत सोच समझ कर काम करना है। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का सवाल है और हर शख्स को पूरी कोशिश करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं कुछ माइनर इर्रीगेशन स्कीम का जिक्र करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था १६८.३८ लाख रुपया स्टट की ओर से प्राइवेट और स्टेट सैक्टर में खर्च कर रहे हैं। हमारे सामने तकरीबन ९ अरब रुपये का बजट है वह प्लानिंग में सर्फ करते हैं। इसके अलावा हम ५० करोड़ और सर्फ करते हैं जो मुख्तलिफ महकमों से करते हैं। इसमें भी खर्च करने की कोशिश की गई है। हर महकमे के बजट में डेवलपमेंट स्कीमों का जिक्र है उसमें भी हम रुपया सर्फ करते हैं। जो हमने १६८.३८ लाख रुपया माइनर इर्रीगेशन स्कीम पर खर्च किया है उसके अलावा ग्रो मोर फूड के सिलसिले में ३४३ लाख रुपया खर्च हुआ है। इस तरह से ५११.३८ लाख रुपया खर्च हुआ है। इसके अलावा स्केअरसिटी डिपार्टमेंट की ओर से ७५ लाख रुपया खर्च किया गया है। इस तरह से कुल ५८५.३८ लाख (करोड़) रुपया इस मद में हम खर्च करना चाहते हैं और

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जब गवर्नमेंट इतना रुपया माइनर इर्रीगेशन स्कीम पर खर्च करना चाहती है तो उसकी मंशा यही हो सकती है कि हमारे प्रदेश की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बढ़े ।

यह बात मान ली गई है कि हमारा आबपाशी का मसला उस वक्त तक तय नहीं हो सकता है जब तक कि कुयें, रहट वगैरह न बनाये जायं । इसलिये हमारी सरकार नहरों को आगे बढ़ाने और ट्यूबवैल्स को लगाने के अलावा ज्यादा से ज्यादा माइनर इर्रीगेशन स्कीम पर खर्च करना चाहती है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आंकड़ा ठीक नहीं बता रहे हैं । अभी उन्होंने ५८५ करोड़ कहा है । इसके माने हैं कि यहां लफ्फाजी हो रही है....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने 'लाख' कहा है लेकिन एक दफा लहजे में गलती से वह करोड़ फरमा गये । (उपमंत्री से) शायद आपने ५८५ लाख कहा है ।

श्री सुल्तान आलम खां—५८५ करोड़ ३८ लाख । श्रीमन्, मैं माफी चाहता हूं यह ५ करोड़ ८५ लाख रुपया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने बाज-बाज बातों की शिकायत की है । जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं सब बातों का जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातों का जबाव देना चाहता हूं । दो-तीन सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे यहां जो ब्लाक्स में जीपें दी गई हैं इन जीपों की जरूरत नहीं है । इसके लिए हमने काफी हिदायतें जारी की हैं और यह भी कोशिश की है कि जो सफर वह महीने में करते हैं उसको भी कम कर दिया जाय। हमने उन लोगों को यह हिदायत की है कि वह ४५० मील से ज्यादा जीपों को इस्तेमाल न करें और मैं इस बात का भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य डेफिनिट शिकायत कोई लायेंगे कि उसका दुरुपयोग किया गया तो उस सिलसिले में मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—जरा शान्ति कायम रखें । आपने अपने सुझाव तो दे दिये थे । अब उनका जबाव सुन लीजिये ।

श्री सुल्तान आलम खां—हमारे कुछ पहाड़ के साथियों ने पहाड़ की दिक्कतें रखीं । जहां तक पहाड़ी इलाकों का ताल्लुक है इस सरकार को उन इलाकों का काफी ध्यान रहा है, हमेशा रहेगा और है । पहाड़ की दो ही प्राबलेम्स हैं—टूरिज्म और फ्रूट कल्टीवेशन । वहां ऐग्रीकल्चर की कोई प्राब्लेम नहीं है । कुमायूं में डेवलपमेंट बोर्ड्स बना दिये गये हैं । इसके अलावा इस बात की कोशिश की जाती है कि वहां फ्रूट यूटिलाइजेशन के लिए कुछ कर सकें । रामगढ़ में एक सरकारी फैक्टरी कायम कर दी गयी है । उस फैक्टरी की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि बड़ी कामयाबी के साथ वह चल रही है । इसके अलावा टूरिज्म के सिलसिले में इतना कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ किया है वह आपके सामने है । जो लिटरेचर हमारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट और प्लानिंग और दूसरे मुहकमों से आपके सामने जाता है अगर आप साहबान उसको पढ़ने की कोशिश करें तो उससे आपको काफी जानकारी हो सकती है । चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं सिर्फ एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । एक प्रान्तीय रक्षा दल के बारें में है । यह फिर रिआर्गेनाइज किया गया है । इसमें तकरीबन पांच लाख आदमी काम कर रहे हैं । इसमें जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा परमानेंट किया जाय । प्लानिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को भी मुस्तकिल करने की तरफ हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं ।

[श्री सुल्तात आलम खां]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे प्लान में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए काफी धन की जरूरत होगी। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि स्माल सेविंग्ज की तरफ अगर आपकी तवज्जह हो जाय और आपका सहयोग हो जाय तो हम इस काम को बड़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। अगर एक नया पैसा रोजाना हम बचा सकें तो उससे शायद हम लोग छः लाख रुपया रोज बचा सकते हैं और २२ करोड़ रुपया हम साल में बजट में दे सकते हैं। हमारे बाज दोस्तों ने प्लानिंग के बाज कर्मचारियों के रवैये की शिकायत की। मैं कह नहीं सकता, हर शख्स से तवक्को की जाती है कि वह मिशनरी स्पिरिट से काम करे। हमारा डिपार्टमेंट ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि मिशनरी डिपार्टमेंट है। इस सिलसिले में अगर कोई डेफिनिट बात सामने आये तो जरूर देखा जायगा, लेकिन मैं उनको यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा महकमा इस बात की कोशिश में लगा हुआ है कि हम पूरी से पूरी कोशिश करके आप सबका सहयोग हासिल करें और आपके सहयोग से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं और ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि मैं एक बार फिर सब साहबान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कि अपने अपने सुझाव दिये और मुझे यकीन है कि वह हमेशा हमें अपना सुझाव देते रहेंगे जिससे हमें लाभ होगा और काम करने में आसानी होगी और मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन सुझावों का मैं जिक्र न कर सका उन सब सुझावों को भी मैंने नोट किया है और उनके बारे में जो कुछ किया जा सकता है वह करने की कोशिश करूंगा।

श्री उग्रसेन---मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। उन्होंने वायदा कर लिया है...

श्री उग्रसेन---इतना ही पूछना चाहता हूं कि बी० डी० ओ० से जीपें वापस ले लेने में उनको क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। अब मैं राय लूंगा। श्री उग्रसेन जी का कटौती का प्रस्ताव---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

योजना का प्रदेश की वर्तमान आवश्यकतानुसार अपर्याप्त, अव्यावहारिक तथा प्राथमिकता-विहीन होना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री उग्रसेन द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री अध्यक्ष---अब इन प्रस्तावों के ऊपर और अनुदानों के ऊपर राय लेने में जितना समय लगेगा उतने समय तक ५ बजे के बाद भी सदन बैठेगा। यह मैंने निश्चय किया।

(घंटी बन्द होने पर प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---३३,

विपक्ष में---१०९।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री टम्बरेश्वर प्रसाद तथा गोविन्दसिंह बिष्ट का प्रस्ताव ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

योजना की फिजूलखर्ची व भ्रष्टाचार ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

नियोजन में प्राथमिकता के सिद्धान्त (Principle of Priority) का पालन न होना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

अल्मोड़ा जिले में (Co-ordination) एकीकरण की नीति (वर्तमान) की असफलता की चर्चा तथा सुझाव ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

वर्तमान योजना खर्चीली, अपव्ययपूर्ण व गरीबी, बेकारी मिटाने व विकास करने में असमर्थ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है ।

योजना की धीमी गति तथा सहयोग का अभाव ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहती हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में बनने वाली इमारतों पर अनावश्यक रूप से अधिक रुपया खर्च होता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक: ६३--क--युद्धोत्तर योजना (Post-war Planning) और विकास (Development) सम्बन्धी व्यय और ६३--ख--सामुदायिक विकास योजनायें--राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ८,९७,७३,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर सोमवार, १६ मार्च, १९५९ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रा,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
१४ मार्च, १९५९ ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१२ एल० ए०--१९५९--८४५ ।